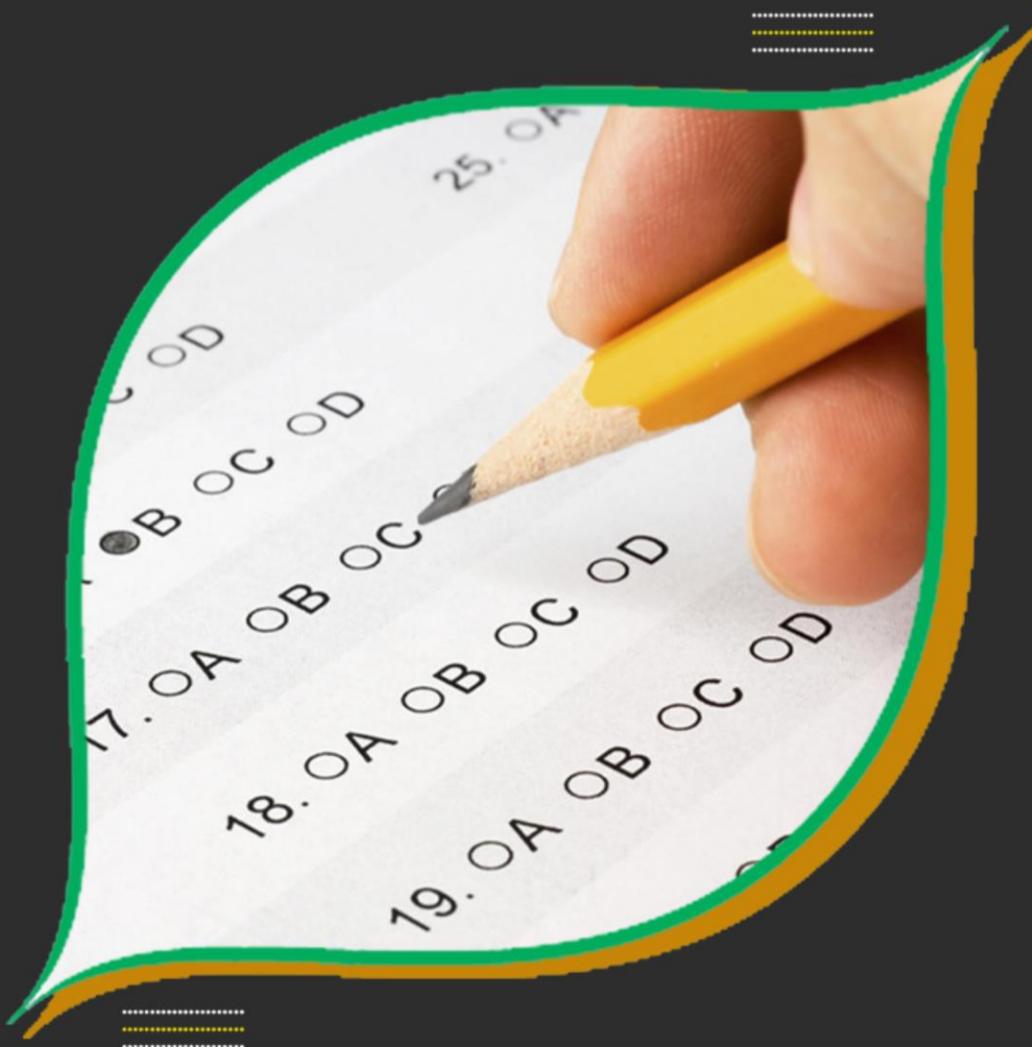


Monthly Current Affairs

June 2021

Practice Current Affairs MCQs



www.gradeup.co

Monthly Current Affairs

Jun 2021

महत्वपूर्ण समाचार: राज्य

असम के मुख्यमंत्री ने 'अभिभावक मंत्रियों' की नियुक्ति की

चर्चा में क्यों?

- असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपने विभिन्न जिलों के लिए 'अभिभावक मंत्री' नियुक्ति किए।

प्रमुख बिंदु

- इन अभिभावकों, प्रत्येक हिमंत बिस्वा सरमा कैबिनेट के मंत्री को, सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं और राज्य की अपनी प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए 2-3 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है।
- 34 जिलों में सरकार के नीतिगत निर्णयों, प्रशासनिक सुधारों और जनता के लिए अन्य कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 13 मंत्री जिम्मेदार होंगे।

असम के बारे में तथ्य:

राज्य नृत्य: बिहू नृत्य

राज्य पक्षी: सफेद पंखों वाली बतख

राज्य जानवर: एक सींग वाला गैंडा

राज्य फूल: फॉकसटेल ऑर्किड

राज्य वृक्ष: हॉलोंग

मेकेदातु परियोजना

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, कर्नाटक सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा कावेरी नदी पर बांध के निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल मेकेदातु में कथित उल्लंघनों को देखने के लिए एक समिति का गठन किया है, के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया है।

प्रमुख बिंदु

समिति के बारे में:

- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने कर्नाटक में मेकेदातु में कावेरी नदी पर एक जलाशय के निर्माण में मानदंडों के कथित उल्लंघन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

मेकेदातु परियोजना

- यह एक बहुउद्देश्यीय (पीने और बिजली) परियोजना है, जिसमें रामनगर जिले के कनकपुरा के पास एक संतुलन जलाशय का निर्माण शामिल है।
- एक बार पूरी होने वाली परियोजना का उद्देश्य बैंगलुरु और पड़ोसी क्षेत्रों (4.75 TMC) को पीने का पानी सुनिश्चित करना है और 400 मेगावाट बिजली भी पैदा कर सकता है, और परियोजना की अनुमानित लागत 9,000 करोड़ रुपये है।



- यह पहली बार 2017 में कर्नाटक सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) से अनुमोदन महत्वपूर्ण है क्योंकि कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य का 63% वन क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा।

नोट: 2018 में, तमिलनाडु ने परियोजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, भले ही कर्नाटक ने माना हो कि यह तमिलनाडु में पानी के प्रवाह को प्रभावित नहीं करेगा।

तमिलनाडु द्वारा विरोध के कारण:

- तमिलनाडु ऊपरी तट पर प्रस्तावित किसी भी परियोजना का विरोध करता है जब तक कि इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है।
- कर्नाटक को इस मामले में निचले तटवर्ती राज्य यानी तमिलनाडु की सहमति के बिना अंतर-राज्यीय नदी पर कोई जलाशय बनाने का कोई अधिकार नहीं है।
- यह परियोजना कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (CWDT) के अंतिम आदेश के खिलाफ है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि कोई भी राज्य विशेष स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता है या अन्य राज्यों को अंतर-राज्यीय नदियों के पानी से वंचित करने के अधिकारों का दावा नहीं कर सकता है।

कावेरी नदी

- कावेरी एक भारतीय नदी है जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है।
- यह दक्षिण भारत में गोदावरी और कृष्णा के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी है और तमिलनाडु राज्य में सबसे बड़ी है।

विवाद:

- चूंकि नदी कर्नाटक से निकलती है, केरल से आने वाली प्रमुख सहायक नदियों के साथ तमिलनाडु से होकर बहती है और पुडुचेरी से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसलिए विवाद में 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।

हाल के घटनाक्रम:

- सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला 2018 में आया जहां उसने कावेरी को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया और CWDT द्वारा अंतिम रूप से जल-बंटवारे की व्यवस्था को बरकरार रखा और कर्नाटक से तमिलनाडु को पानी के आवंटन को भी कम कर दिया।
- सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, कर्नाटक को 284.75 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (tmcft), तमिलनाडु को 404.25 tmcft, केरल को 30 tmcft और पुडुचेरी को 7 tmcft मिलेगा।
- इसने केंद्र को कावेरी प्रबंधन योजना को अधिसूचित करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने 'कावेरी जल प्रबंधन योजना' जून 2018 में अधिसूचित की, जिसमें 'कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण' और 'कावेरी जल विनियमन समिति' का गठन किया गया।

मध्य प्रदेश सरकार ने 'अंकुर' योजना की शुरुआत की

चर्चा में क्यों?

- मध्य प्रदेश सरकार ने मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए लोगों को पुरस्कृत करने के लिए 'अंकुर' योजना शुरू की।
- पौधरोपण की पहल करने वाले लोगों को उनकी भागीदारी के लिए प्राणवायु पुरस्कार दिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु



'अंकुर' योजना के बारे में:

- यह योजना कार्यक्रम में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करेगी।
- जो लोग वृक्षारोपण अभियान में भाग लेना चाहते हैं, वे वायुदूत ऐप पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
- प्रतिभागियों को पौधा लगाते समय एक तस्वीर अपलोड करनी होगी और 30 दिनों तक पौधे की देखभाल करने के बाद दूसरी तस्वीर अपलोड करनी होगी।
- सत्यापन के बाद मुख्यमंत्री प्रत्येक जिले से चयनित विजेताओं को प्राणवायु पुरस्कार प्रदान करेंगे।

इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क रायपुर, छत्तीसगढ़

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में वर्चुअल रूप में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क के बारे में:

- मेगा फूड पार्क मेसर्स इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- मेसर्स इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड को 63.8 एकड़ भूमि में 145.5 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से स्थापित किया गया है।

लाभ:

- मेगा फूड पार्क मूल्यवर्धन, कृषि उत्पादों के लिए लंबी शेल्फ लाइफ, किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति, उत्कृष्ट भंडारण सुविधा सुनिश्चित करेगा और क्षेत्र में किसानों के लिए वैकल्पिक बाजार प्रदान करेगा।
- पार्क लगभग 5,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करेगा और लगभग 25,000 किसानों को लाभान्वित करेगा।

मेगा फूड पार्क योजना के बारे में:

- मेगा फूड पार्क भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की एक योजना है जिसका उद्देश्य संग्रह केंद्रों (CC) और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों (PPC) के नेटवर्क के माध्यम से "खेत से प्रसंस्करण और फिर उपभोक्ता बाजारों तक सीधा संबंध" स्थापित करना है।
- मेगा फूड पार्क परियोजना एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) द्वारा कार्यान्वित की जाती है जो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत एक निगमित निकाय है।
- इस योजना के तहत भारत सरकार प्रति मेगा फूड पार्क परियोजना 50.00 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

नोट:

- छह चरणों में 42 मेगा फूड पार्क स्वीकृत किए गए हैं।
- वर्तमान में, 22 मेगा फूड पार्क चालू हैं।

स्रोत: PIB

इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क रायपुर, छत्तीसगढ़

चर्चा में क्यों?



Follow us on
Telegram



- केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में वर्चुअल रूप में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क के बारे में:

- मेगा फूड पार्क मेसर्स इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- मेसर्स इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड को 63.8 एकड़ भूमि में 145.5 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से स्थापित किया गया है।

लाभ:

- मेगा फूड पार्क मूल्यवर्धन, कृषि उत्पादों के लिए लंबी शेल्फ लाइफ, किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति, उत्कृष्ट भंडारण सुविधा सुनिश्चित करेगा और क्षेत्र में किसानों के लिए वैकल्पिक बाजार प्रदान करेगा।
- पार्क लगभग 5,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करेगा और लगभग 25,000 किसानों को लाभान्वित करेगा।

मेगा फूड पार्क योजना के बारे में:

- मेगा फूड पार्क भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की एक योजना है जिसका उद्देश्य संग्रह केंद्रों (CC) और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों (PPC) के नेटवर्क के माध्यम से "खेत से प्रसंस्करण और फिर उपभोक्ता बाजारों तक सीधा संबंध" स्थापित करना है।
- मेगा फूड पार्क परियोजना एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) द्वारा कार्यान्वित की जाती है जो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत एक निगमित निकाय है।
- इस योजना के तहत भारत सरकार प्रति मेगा फूड पार्क परियोजना 50.00 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

नोट:

- छह चरणों में 42 मेगा फूड पार्क स्वीकृत किए गए हैं।
- वर्तमान में, 22 मेगा फूड पार्क चालू हैं।

स्रोत: PIB

मध्य प्रदेश 'युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान' शुरू करेगा

चर्चा में क्यों?

- मध्य प्रदेश में, 'युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान' यानी कोरोना मुक्त एक युवा शक्ति अभियान की मदद से लोगों को COVID महामारी के बारे में जागरूक करने के लिए शुरू किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

'युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान' के बारे में:

- यह अभियान उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से चलाया जाएगा।
- युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान में महाविद्यालय के शिक्षकों एवं लगभग 16 लाख विद्यार्थियों को COVID उपयुक्त व्यवहार एवं टीकाकरण सीखकर कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक किया जायेगा।

मध्य प्रदेश के बारे में तथ्य:

- राजधानी: भोपाल



Follow us on
Telegram



Gradeup
PCS & Other
State Exams



- राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल
- मुख्यमंत्री: शिवराज सिंह चौहान

बिहार के मुख्यमंत्री ने युवाओं और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए दो नई योजनाओं की शुरुआत की

चर्चा में क्यों?

- बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की 'मुख्यमंत्री उद्यमी योजना' योजना के तहत सभी वर्गों के युवाओं और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए दो नई योजनाएं शुरू कीं- 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना' (MYUY) और 'मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना' (MMUY)।

प्रमुख बिंदु

- 'मुख्यमंत्री उद्यमी योजना' 2018 में शुरू की गई थी और यह SC, ST और अत्यंत पिछड़े वर्गों (EBC) के सदस्यों तक सीमित है।

'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना' (MYUY) के बारे में:

- MYUY के तहत, एक बेरोजगार युवा को एक नया उद्यम या उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। कुल 10 लाख रुपये में से 5 लाख रुपये सब्सिडी की राशि होगी, जिसे युवाओं को वापस करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी 5 लाख रुपये एक प्रतिशत के साधारण ब्याज पर कई किश्तों में लौटाए जाने वाले ऋण होंगे।

'मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना' (MMUY) के बारे में:

- MMUY के तहत, एक बेरोजगार महिला को एक नया व्यवसाय या छोटा उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। 10 लाख रुपये में से 5 लाख रुपये सब्सिडी राशि होगी जिसे महिला को वापस करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि बाकी 5 लाख रुपये ब्याज मुक्त ऋण होंगे, जिसे कई किश्तों में वापस किया जाएगा।

स्रोत: TOI

असम सरकार ने SVAMITVA (स्वामित्व) योजना को लागू करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता जापन पर हस्ताक्षर किए

चर्चा में क्यों?

- असम सरकार ने राज्य में SVAMITVA योजना को लागू करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ एक समझौता जापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय और असम सरकार के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग पंचायत और ग्रामीण विकास के सहयोग से इस योजना को लागू करेंगे।
- भारतीय सर्वेक्षण विभाग, प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों के विस्तृत स्थानिक डेटाबेस को सक्षम करने के लिए ड्रोन द्वारा ग्रामीण भूमि के सर्वेक्षण के साथ-साथ जमीन आधारित नियंत्रण स्टेशनों की स्थापना के लिए कदम उठाएगा।
- इससे ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति संबंधी विवादों और कानूनी मामलों में कमी आने की उम्मीद है।

SVAMITVA (सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज) योजना के बारे में:

- यह राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यानी 24 अप्रैल 2020 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना है।
- पंचायती राज मंत्रालय योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है।
- भारतीय सर्वेक्षण विभाग कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में कार्य करेगा।
- इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बारे में:

- यह मानचित्रण और सर्वेक्षण के प्रभारी भारत की केंद्रीय इंजीनियरिंग एजेंसी है। 1767 में स्थापित, यह भारत सरकार के सबसे पुराने इंजीनियरिंग विभागों में से एक है।

स्रोत: TOI

दिल्ली सरकार की 'मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना'

चर्चा में क्यों?

- दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग ने 'मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना' शुरू की।
- COVID-19 से मरने वालों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना को अधिसूचित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- योजना उन लोगों के परिवारों को 2,500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिन्होंने COVID-19 के कारण अपने कमाने वाले सदस्य को खो दिया है और यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है तो 50,000 का एकमुश्त मुआवजा भी।

नोट: जिन बच्चों ने अपने दोनों या एकल माता-पिता को COVID-19 से खो दिया है, उन्हें भी 25 वर्ष की आयु तक प्रति माह 2,500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। सरकार उन्हें मुफ्त शिक्षा भी देगी।

स्रोत: TOI

तमிலनாடு ने 5 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया

चर्चा में क्यों?

- तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री के लिए 5 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया।

पांच सदस्य:

- एस्टर इफलो- नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री
- रघुराम राजन- RBI के पूर्व गवर्नर
- अरविंद सुब्रमण्यम- भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार
- एस नारायण- पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव
- ज्यां द्रेज- कल्याणकारी अर्थशास्त्री और सामाजिक वैज्ञानिक

प्रमुख बिंदु

- परिषद आर्थिक और सामाजिक नीति, सामाजिक न्याय और मानव विकास से संबंधित मुद्राओं और महिलाओं के लिए समान अवसर और वंचित समूहों की भलाई से संबंधित मामलों में सामान्य मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

तमिलनाडु के बारे में तथ्य:

- राजधानी: चेन्नई
- राज्यपाल: बनवारीलाल पुरोहित
- मुख्यमंत्री: एम के स्टालिन

स्रोत: द हिंदू

पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच के लिए NHRC ने 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया

चर्चा में क्यों?

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की शिकायतों की जांच करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार, एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है।
- पैनल का नेतृत्व NHRC सदस्य राजीव जैन करेंगे।

नोट: हाल ही में, TMC प्रमुख ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के बारे में: NHRC एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है जिसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश 28 सितंबर 1993 के तहत किया गया था। इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 द्वारा वैधानिक आधार दिया गया था।

स्रोत: TOI

महत्वपूर्ण समाचार: भारत

आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिट्री पोर्टल और आयुष संजीवनी ऐप

चर्चा में क्यों?

- आयुष मंत्रालय ने वर्चुअल आयोजन में आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिट्री पोर्टल (ACCR) पोर्टल और आयुष संजीवनी ऐप का तीसरा संस्करण लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल के बारे में:

- यह आयुष चिकित्सकों और आम जनता दोनों का समर्थन करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा।
- इस पोर्टल का उद्देश्य बड़े पैमाने पर आयुष चिकित्सकों द्वारा प्राप्त नैदानिक परिणामों के बारे में जानकारी एकत्र करना है।

आयुष संजीवनी ऐप के तीसरे संस्करण के बारे में:

- आयुष संजीवनी ऐप के तीसरे वर्जन से बिना लक्षण तथा हल्के और मध्यम लक्षण वाले कोविड रोगियों के उपचार में आयुष 64 और कबासुरा कुदिनीर औषधि सहित आयुष के अन्य उपायों की प्रभावकारिता का अध्ययन किया जा सकेगा।
- पहला संस्करण मई 2020 में लॉन्च किया गया था।



Follow us on
Telegram



Gradeup
PCS & Other
State Exams



- इसे आयुष मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है।
- आयुष 64** आयुर्वेदिक विज्ञान में केंद्रीय अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित एक पॉली-हर्बल फॉर्मूलेशन है। आयुष 64 बिना लक्षण, हल्के और मध्यम COVID-19 संक्रमण के उपचार में उपयोगी है। प्रारंभ में मलेरिया के लिए वर्ष 1980 में दवा विकसित की गई थी।
- कबासुरा कुदिनीर सिद्ध चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक पारंपरिक सूत्रीकरण है। यह सामान्य श्वसन स्वास्थ्य के उपचार में उपयोगी है।

संबंधित पहल:

- आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र
- राष्ट्रीय आयुष मिशन (NAM):** भारत सरकार आयुष चिकित्सा प्रणाली के विकास और प्रचार के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से NAM की केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रही है।
- हाल ही में, सरकारी अधिसूचना ने आयुर्वेद के स्नातकोत्तर मेडिकल छात्र द्वारा विशिष्ट सर्जिकल प्रक्रियाओं को सूचीबद्ध किया है।

नए IT नियम 2021 में ट्रेसबिलिटी प्रावधान

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने नए IT नियम 2021 में ट्रेसबिलिटी प्रावधान को चुनौती देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है।

प्रमुख बिंदु

ट्रेसबिलिटी प्रावधान:

- ट्रेसबिलिटी प्रावधान सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 का एक हिस्सा है।
- दिशानिर्देशों के अनुसार, संदेश सेवा प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों को अदालत या सक्षम प्राधिकारी के आदेश के आधार पर सूचना के पहले प्रवर्तक की पहचान करनी चाहिए।
- व्हाट्सएप के अनुसार, मैसेजिंग ऐप्स के चैट को 'ट्रेस' करने की आवश्यकता व्हाट्सएप पर भेजे गए हर एक संदेश का फिंगरप्रिंट रखने के लिए कहने के बराबर है, जो एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को तोड़ और मौलिक रूप से लोगों के निजता के अधिकार को कमजोर कर देगा।
- व्हाट्सएप ने पुट्टस्वामी जजमेंट 2017 का हवाला देते हुए तर्क दिया कि ट्रेसबिलिटी प्रावधान असंवैधानिक है और लोगों के निजता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है।
- एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन यह सुनिश्चित करता है कि प्रेषक और रिसीवर को छोड़कर कोई भी संदेश को नहीं पढ़ सकता है। इसमें व्हाट्सएप भी शामिल है।

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 माध्यमिक या अधीनस्थ कानून है जो भारत के मध्यवर्ती दिशानिर्देश नियम 2011 को बदलता है। 2021 के नियम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87 से उपजी हैं और मध्यवर्ती नियम, 2018 और डिजिटल मीडिया के लिए OTT विनियमन और आचार संहिता मसौदे का एक संयोजन हैं।

बागवानी कलस्टर विकास कार्यक्रम



चर्चा में क्यों?

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बागवानी के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम (CDP) शुरू किया।

प्रमुख बिंदु

क्लस्टर विकास कार्यक्रम (CDP) के बारे में:

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) द्वारा कार्यान्वित, एक केंद्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम CDP का उद्देश्य वैशिक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए पहचाने गए बागवानी समूहों को बढ़ाना और विकसित करना है।
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 53 बागवानी क्लस्टर की पहचान की है, जिनमें से 12 को कार्यक्रम के पायलट लॉन्च के लिए चुना गया है।
- CDP से लगभग 10 लाख किसानों और मूल्य श्रृंखला के संबंधित हितधारकों को लाभ होगा।
- सभी 53 क्लस्टर में लागू होने पर CDP से 10,000 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है।

भारत में बागवानी क्षेत्र:

- भारत विश्व स्तर पर बागवानी फसलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो दुनिया के सब्जियों और फलों के उत्पादन का लगभग 12% है।
- भारत केला, आम, अनार, एसिड लाइम, आंवला और सपोटा जैसे फलों के उत्पादन में अग्रणी है।

हाल ही में उठाए गए कदम:

- मंत्रालय ने 'MIDH-मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर' के लिए वर्ष 2021-22 के लिए 2250 करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ आवंटन प्रदान किया है।
- MIDH बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

NCPCR ने ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल "बाल स्वराज (Covid देखभाल)" की शुरूआत की

चर्चा में क्यों?

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 109 के अंतर्गत एक निगरानी प्राधिकरण के रूप में अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए और COVID-19 से प्रभावित बच्चों से संबंधित बढ़ती समस्या को देखते हुए देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल "Bal Swaraj (COVID-Care Link)" तैयार किया है।

प्रमुख बिंदु

"बाल स्वराज" के बारे में:

- आयोग का यह पोर्टल देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ऑन लाइन ट्रैकिंग तथा डिजिटल रियल टाइम मॉनिटरिंग व्यवस्था के उद्देश्य से बनाया गया है।
- आयोग ने इस पोर्टल के उपयोग को COVID-19 के दौरान माता-पिता या उनमें से किसी एक को खो देने वाले बच्चों की ट्रैकिंग के लिए बढ़ाया है और संबंधित अधिकारी/ विभाग द्वारा ऐसे बच्चों का डाटा अपलोड करने के लिए "COVID-Care" के नाम से लिंक प्रदान किया है।

NCPCR के बारे में:

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) संसद के एक अधिनियम, बाल अधिकार संरक्षण आयोग (CPCR) अधिनियम, 2005 द्वारा स्थापित एक भारतीय वैधानिक निकाय है। आयोग भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में काम करता है। आयोग ने 5 मार्च 2007 को कार्य करना शुरू किया।

NITI आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 जारी किया

चर्चा में क्यों?

- NITI आयोग ने सतत विकास लक्ष्य (SDG) इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 का तीसरा संस्करण जारी किया।
- NITI आयोग ने 'SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21: पार्टनरशिप्स इन द डिकेड ऑफ एक्शन' शीर्षक रिपोर्ट जारी की।
- इंडेक्स 2030 SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति का दस्तावेज है।
- भारत में संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से विकसित SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 सभी राज्यों और केन्द्र - शासित प्रदेशों की प्रगति को उन 115 संकेतकों पर आंकता है जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (NIF) से जुड़े हैं।
- कुल 115 संकेतक लक्ष्य -17 के बारे में गुणात्मक मूल्यांकन के साथ कुल 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDG) में से 16 को शामिल करते हैं और 70 SDG से जुड़े प्रयोजनों को कवर करते हैं।

प्रमुख बिंदु

कार्यप्रणाली

- SDG इंडिया इंडेक्स प्रत्येक राज्य और केन्द्र - शासित प्रदेश के लिए 16 SDG पर लक्ष्य-वार स्कोर की गणना करता है।
- कुल मिलाकर राज्य और केन्द्र - शासित प्रदेश के स्कोर 16 SDG पर उनके प्रदर्शन के आधार पर उप-राष्ट्रीय इकाई के समग्र प्रदर्शन को मापने के लिए गणना किये गये लक्ष्य-वार स्कोर में से निकाले जाते हैं।
- ये स्कोर 0-100 के बीच होते हैं, और अगर कोई राज्य/केन्द्र- शासित प्रदेश 100 का स्कोर प्राप्त करता है, तो यह इस तथ्य को दर्शाता है कि उस राज्य/केन्द्र - शासित प्रदेश ने 2030 के लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। किसी राज्य/केन्द्र - शासित प्रदेश का स्कोर जितना अधिक होगा, उतनी ही अधिक दूरी तक उसने लक्ष्य हासिल कर लिया होगा।
- राज्यों और केन्द्र- शासित प्रदेशों को उनके SDG इंडिया इंडेक्स स्कोर के आधार पर निम्नलिखित तरीके से वर्गीकृत किया जाता है:

प्रतियोगी (एस्पीरेंट): 0-49

प्रदर्शन करने वाला (परफॉर्मर): 50-64

सबसे आगे चलने वाला (फ्रंट - रनर): 65-99

लक्ष्य पाने वाला (एचीवर): 100

समग्र परिणाम और निष्कर्ष

- देश के समग्र SDG स्कोर में 6 अंकों का सुधार हुआ है - 2019 में 60 से बढ़कर 2020-21 में 66 पहुंचा।



Follow us on
Telegram



Gradeup
PCS & Other
State Exams



- लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में यह सकारात्मक कदम बड़े पैमाने पर लक्ष्य -6 (साफ पानी और स्वच्छता) और लक्ष्य - 7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा) के बारे में अनुकरणीय देशव्यापी प्रदर्शन से प्रेरित है, जिसमें समग्र लक्ष्य स्कोर क्रमशः 83 और 92 हैं।
- केरल 75 के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु 74 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं।
- 52 के न्यूनतम स्कोर के साथ बिहार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले के रूप में उभरा है, इसके बाद झारखंड 56 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है।
- केंद्र शासित प्रदेशों में, चंडीगढ़ 79 के स्कोर के साथ सूची में सबसे ऊपर है।

नोट: 2019 के स्कोर में सुधार के मामले में मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखण्ड 2020-21 में क्रमशः 12, 10 और 8 अंकों की वृद्धि के साथ शीर्ष पर हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मास मीडिया सहयोग पर SCO समझौते को दी मंजूरी

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सभी सदस्य देशों के बीच "मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग" के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर और अनुमोदन हेतु अपनी कार्यतार मंजूरी दी है।
- समझौता, जिस पर जून, 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे, सदस्य राज्यों को मास मीडिया के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं और नए नवाचारों को साझा करने का अवसर प्रदान करेगा।

प्रमुख बिंदु

सहयोग के मुख्य क्षेत्र:

- मास मीडिया के माध्यम से सूचना के व्यापक और पारस्परिक वितरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण ताकि अपने देशों के लोगों के जीवन के बारे में ज्ञान को और परिपक्व किया जा सके।
- अपने राज्यों के जनसंचार माध्यमों के संपादकीय कार्यालयों के साथ-साथ संबंधित मंत्रालयों, एजेंसियों के बीच सहयोग।
- यह टेलीविजन और रेडियो कार्यक्रमों के प्रसारण और दूसरे पक्ष के राज्य के क्षेत्र में कानूनी रूप से वितरित किए जाने में सहायता करेगा।
- यह समझौता मास मीडिया के क्षेत्र में अनुभव और विशेषज्ञों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेगा, मीडिया पेशेवरों को प्रशिक्षण देने में पारस्परिक सहायता प्रदान करेगा और शैक्षिक और वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेगा।

SCO के बारे में तथ्य: शंघाई सहयोग संगठन या शंघाई पैक्ट, एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है।

- स्थापना:** 15 जून 2001
- सदस्य:** चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उजबेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान।
- मुख्यालय:** बीजिंग, चीन

भारत 2017 में SCO का पूर्ण सदस्य बन गया। इससे पहले, भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त था, जो इसे 2005 में प्रदान किया गया था।

SAGE (सीनियरकेयर एंजिंग ग्रोथ इंजन) पहल और SAGE पोर्टल



चर्चा में क्यों?

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए SAGE (सीनियरकेयर एजिंग ग्रोथ इंजन) पहल और SAGE पोर्टल लॉन्च किया।
- सिल्वर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए **100** करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।
- सिल्वर अर्थव्यवस्था के बारे में: यह वृद्ध और वृद्ध लोगों की क्रय क्षमता का उपयोग करने और उनके उपभोग, रहने और स्वास्थ्य की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और खपत की प्रणाली है।

प्रमुख बिंदु

SAGE पोर्टल के बारे में

- SAGE पोर्टल भरोसेमंद स्टार्टअप के जरिए बुजुर्गों की देखभाल में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने वाला "वन-स्टॉप एक्सेस" होगा।
- बुजुर्गों की देखभाल के लिए सेवाएं प्रदान करने के क्षेत्र में उद्यमिता में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को सहयोग देने के लिए SAGE कार्यक्रम और SAGE पोर्टल शुरू किया गया है।
- SAGE के तहत चुने गए स्टार्ट-अप वे होंगे जो स्वास्थ्य, यात्रा, वित्त, कानूनी, आवास, भोजन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बुजुर्ग व्यक्तियों को नए और इन्नोवेटिंग उत्पाद और सेवाएं प्रदान करेंगे।
- चालू वित्त वर्ष यानी **2021-22** में SAGE परियोजना के लिए **25** करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
- SAGE कार्यक्रम बुजुर्गों के लिए स्टार्ट-अप पर अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (EEC) रिपोर्ट की सिफारिशों पर बनाई गई है।

पहल की आवश्यकता

- भारत में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है और सर्वेक्षणों के अनुसार, देश में कुल आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी 2001 में 7.5 प्रतिशत से बढ़कर 2026 तक लगभग 12.5 प्रतिशत और 2050 तक 19.5 प्रतिशत से अधिक होने की उम्मीद है।

बुजुर्ग लोगों के लिए अन्य सरकारी पहल

- वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (IPOP)
- राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY)
- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY)
- वयोश्रेष्ठ सम्मान
- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण (MWPSC) अधिनियम, 2007
- वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष

स्रोत: PIB

भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा कलस्टर GIFT सिटी में स्थापित किया जाएगा

चर्चा में क्यों?

- गुजरात मैरीटाइम बोर्ड (GMB) गुजरात में GIFT सिटी में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा कलस्टर स्थापित करेगा।



Follow us on
Telegram



Gradeup
PCS & Other
State Exams



प्रमुख बिंदु

- समुद्री क्लस्टर को एक समर्पित पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित किया जाएगा जिसमें बंदरगाह, नौवहन, रसद सेवा प्रदाता और प्रासंगिक सरकारी नियामक शामिल हैं, जो सभी एक ही भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद हैं।

समुद्री सेवा समूह के बारे में:

- यह भारत में अपनी तरह का पहला वाणिज्यिक समुद्री सेवा समूह होगा जिसकी अवधारणा समुद्री क्षेत्र में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने और संपूर्ण समुद्री बिरादरी के लिए एक ही स्थान पर समाधान प्रदान करने के लिए की गई है।

गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT सिटी) के बारे में:

- GIFT सिटी भारत का पहला परिचालन स्मार्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) है।
- GIFT सिटी में अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा और विश्व स्तरीय बैंकिंग सुविधाएं और संस्थान हैं जो क्लस्टर के लिए नवाचार, आर्थिक व्यवहार्यता, सहयोग और व्यावसायिक अवसरों को बढ़ावा देने के लिए फायदेमंद होंगे।

गुजरात मैरीटाइम बोर्ड (GMB) के बारे में:

- गुजरात मैरीटाइम बोर्ड - गुजरात सरकार का उपक्रम, और भारत का पहला समुद्री बोर्ड 1982 में स्थापित किया गया था।
- यह 48 गैर-प्रमुख बंदरगाहों के विकास, प्रशासन, संचालन और विनियमन के साथ-साथ गुजरात राज्य में अन्य समुद्री / शिपिंग गतिविधियों के विकास के लिए जिम्मेदार है।

स्रोत: TOI

CBSE पाठ्यक्रम में कोडिंग, डेटा साइंस शुरू करेगा

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2021-2022 शैक्षणिक सत्र में कक्षा 6 से 8वीं के लिए कोडिंग और कक्षा 8वीं से 12वीं के लिए डेटा साइंस के पाठ्यक्रम को नए स्किल्स सब्जेक्ट के रूप में शुरू किया है। इसके लिए CBSE ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ हाथ मिलाया है।

प्रमुख बिंदु

कोडिंग और डेटा साइंस पाठ्यक्रम के बारे में:

- NEP (नई शिक्षा नीति) 2020 को ध्यान में रखते हुए, छात्रों में स्किल्स का निर्माण करने के उद्देश्य से इन पाठ्यक्रमों को शुरू किया गया है।
- कोडिंग और डेटा साइंस पाठ्यक्रम क्रिटिकल थिंकिंग, कम्प्यूटेशनल स्किल्स, प्रोब्लम-सॉल्विंग स्किल्स, क्रिएटिविटी और नई टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन के निर्माण पर केंद्रित हैं।

स्रोत: द हिंदू

‘एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर जागरूकता अभियान’ और ‘इंडिया प्लास्टिक चैलेंज- हैकथॉन 2021’

चर्चा में क्यों?



Follow us on
Telegram



- केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री ने दो महीने के 'एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर जागरूकता अभियान' और 'इंडिया प्लास्टिक चैलेंज- हैकथॉन 2021' की शुरुआत की।
- सरकार भारत ने 2022 तक एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक को खत्म करने का लक्ष्य रखा था।

प्रमुख बिंदु

एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक के बारे में:

- प्लास्टिक जो अपने पहले उपयोग के बाद फेंक दिया जाता है उसे एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक के रूप में जाना जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, आज उत्पादित अधिकांश प्लास्टिक को पहले उपयोग के बाद फेंकने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

'एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर जागरूकता अभियान' के बारे में:

- GIZ (The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI), भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ मिलकर दो माह के इस लंबे जागरूकता अभियान का आयोजन कर रहे हैं।
- इसमें चार ऑन-लाइन क्षेत्रीय कार्यक्रम और व्यापक स्तर पर लोगों तक प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के संदेश को फैलाने के लिए एक सोशल मीडिया अभियान शामिल होगा।

'इंडिया प्लास्टिक चैलेंज- हैकथॉन 2021' के बारे में:

- 'इंडिया प्लास्टिक चैलेंज- हैकथॉन 2021' एक अनूठी प्रतियोगिता है जो स्टार्ट-अप्स/उद्यमियों और उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) के छात्रों को प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने और एकल उपयोग प्लास्टिक के विकल्प को विकसित करने के लिए अभिनव समाधान विकसित करने का आह्वान करती है।

भारत द्वारा की गई पहल:

- भारत सरकार ने पहले ही देश में प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016:

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ही पर्यावरण के अनुकूल तरीके से प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए पहली बार प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 अधिसूचित किए थे।
- नियमों के तहत 50 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- इसके अलावा, मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में संशोधन के लिए मार्च 2021 में डिस्पोजेबल प्लास्टिक कटलरी आदि जैसी 12 एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं को प्रतिबंधित करने के संबंध में एक मसौदा अधिसूचना जारी की गई है।

स्रोत: PIB

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेल को 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के आवंटन को मंजूरी दी

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेल को स्टेशन परिसर एवं रेलगाड़ियों में सार्वजनिक बचाव व सुरक्षा सेवाओं के लिए 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के आवंटन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- नोट: इसके अलावा भारतीय रेल ने TCAS (ट्रेन कोलिजन अवॉइंडेंस सिस्टम) को मंजूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- परियोजना में अनुमानित निवेश 25,000 करोड़ रुपये से अधिक है। यह परियोजना अगले पांच साल में पूरी होगी।
- इसके लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की सिफारिश के अनुसार निजी उपयोग पर रॉयल्टी शुल्क एवं लाइसेंस शुल्क के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित फॉर्मूले के आधार पर स्पेक्ट्रम शुल्क लगाया जा सकता है।
- इस स्पेक्ट्रम के साथ ही भारतीय रेल ने अपने मार्ग पर LTE (लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन) आधारित मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार प्रदान करने की परिकल्पना की है।

LTE (लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन) के बारे में:

- यह एक 4G वायरलेस मानक है जो 3G तकनीकों की तुलना में सेलफोन और अन्य सेन्सर उपकरणों के लिए बढ़ी हुई नेटवर्क क्षमता और गति प्रदान करता है।

उद्देश्य:

- भारतीय रेल के लिए LTE का उद्देश्य परिचालन, बचाव एवं सुरक्षा से जुड़े ऐप्लिकेशन के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद वॉइस, वीडियो और डेटा संचार सेवाएं प्रदान करना है।
- यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) आधारित रिमोट ऐसेट मॉनिटरिंग विशेष रूप से कोच, वैगन व लोको की निगरानी और ट्रेन के डिब्बों में CCTV कैमरों की लाइव वीडियो फीड को सुनिश्चित करने में सक्षम करेगा।

TCAS (ट्रेन कोलिजन अवॉइंडेंस सिस्टम) के बारे में:

- यह, एक स्वदेश में विकसित ATP (ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन) सिस्टम है, जो ट्रेन की टक्कर से बचने में मदद करेगा जिससे दुर्घटनाएं कम होंगी और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित होंगी।

रेडियो स्पेक्ट्रम के बारे में:

- रेडियो स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा है जिसकी आवृत्ति 30 हर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है।
- इस आवृत्ति रेज में विद्युत चुम्बकीय तरंगें, जिन्हें रेडियो तरंगें कहा जाता है, आधुनिक तकनीक में, विशेष रूप से दूरसंचार, में व्यापक रूप से उपयोग की जाती हैं।
- विभिन्न उपयोगकर्ताओं के बीच हस्तक्षेप को रोकने के लिए, रेडियो तरंगों के उत्पादन और प्रसारण को एक अंतरराष्ट्रीय निकाय, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) द्वारा समन्वित राष्ट्रीय कानूनों द्वारा सख्ती से नियंत्रित किया जाता है।

स्रोत: PIB

112 आकांक्षी जिलों में 'सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान' शुरू किया गया

चर्चा में क्यों?



Follow us on
Telegram



- NITI आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में 'सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान' की शुरुआत की, जिससे जिला प्रशासन को COVID-19 के ऐसे मरीजों को होम-केयर सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग मिल सके, जो बिना लक्षण वाले या हल्के लक्षण वाले हैं।

प्रमुख बिंदु

उद्देश्य:

- इस अभियान के घर पर रह रहे लगभग 70 फीसदी COVID मामलों के प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रणाली पर दबाव कम करने और लोगों में डर फैलने को रोकने के लिए जिला की तैयारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।

सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान के बारे में:

- यह अभियान एक विशिष्ट पहल, आकांक्षी जिला सहभागिता का हिस्सा बन रहा है, जिसमें स्थानीय नेता, नागरिक समाज और स्वयंसेवक आकांक्षी जिला कार्यक्रम के ध्यान केंद्रित करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में उभरती समस्याओं का समाधान करने के लिए जिला प्रशासन के साथ काम करते हैं।
- सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान का नेतृत्व 1000 से अधिक स्थानीय NGO की साझेदारी में जिला मजिस्ट्रेट करेंगे, जो इनबाउंड/आउटबाउंड कॉल्स के माध्यम से मरीजों से जुड़ने के लिए 1 लाख से अधिक स्वयंसेवकों को सूचीबद्ध और प्रशिक्षित करेंगे।
- स्वयंसेवकों को COVID प्रोटोकॉल का पालन करने, मनो-सामाजिक सहायता प्रदान करने और प्रशासन को रोगियों के बारे में समय पर अपडेट प्रदान करने के लिए शिक्षित करके प्रत्येक 20 प्रभावित परिवारों का समर्थन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
- पिरामल फाउंडेशन NGO और स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण में सहायता करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के साथ काम करेगा।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में:

- भारत सरकार 2022 तक एक नए भारत की वृष्टि से जनवरी, 2018 में पहल 'आकांक्षी जिलों के परिवर्तन' की शुरुआत की है।
- मानव विकास सूचकांक के तहत भारत की रैंकिंग में सुधार करने, अपने नागरिकों के जीवन स्तर को बढ़ाने और सभी के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

स्रोत: PIB

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गहरे समुद्र अभियान (डीप ओशन मिशन) को स्वीकृति दी

चर्चा में क्यों?

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने "गहरे समुद्र अभियान" पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- यह संसाधनों के लिए गहरे महासागर की खोज करता है और महासागर संसाधनों के सतत उपयोग के लिए गहरे समुद्र की प्रौद्योगिकियों का विकास करता है।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस बहु-संस्थागत महत्वाकांक्षी अभियान को लागू करने वाला नोडल मंत्रालय होगा।

प्रमुख बिंदु

"गहरे समुद्र अभियान" के बारे में:

- गहरे समुद्र परियोजना भारत सरकार की नीली अर्थव्यवस्था पहल का समर्थन करने के लिए एक मिशन आधारित परियोजना होगी।
- इस अभियान को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए 5 वर्ष की अवधि की अनुमानित लागत 4,077 करोड़ रुपए होगी।
- यह मिशन भारत को उन मुट्ठी भर शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक बना देगा जिनके पास पहले से ही समर्पित समुद्री अध्ययन और मिशन हैं, जिनमें अमेरिका, जापान, फ्रांस, रूस और चीन शामिल हैं।

गहरे समुद्र अभियान के प्रमुख घटक:

- गहरे समुद्र में खनन और मानवयुक्त पनडुब्बी के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास
- महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का विकास
- गहरे समुद्र में जैव विविधता की खोज और संरक्षण के लिए तकनीकी नवाचार
- गहरे समुद्र में सर्वेक्षण और अन्वेषण
- महासागर से ऊर्जा और मीठा पानी
- महासागर जीवविज्ञान के लिए उन्नत समुद्री स्टेशन

मिशन का महत्व:

- विश्व के लगभग 70 प्रतिशत भाग में मौजूद महासागर, हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बने हुए हैं। गहरे समुद्र का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा अभी तक खोजा नहीं जा सका है।
- भारत के लिए, इसकी तीन किनारे महासागरों से घिरे हैं और देश की लगभग 30 प्रतिशत आबादी तटीय क्षेत्रों में रहती है। महासागर मत्स्य पालन और जलीय कृषि, पर्यटन, आजीविका और नील व्यापार का समर्थन करने वाला एक प्रमुख आर्थिक कारक है।
- भारत की 7,517 किमी लंबी तटरेखा नौ तटीय राज्यों और 1,382 द्वीपों का आवास है।
- दीर्घकालिक रूप से महासागरों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, संयुक्त राष्ट्र ने 2021-2030 के दशक को सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान के दशक के रूप में घोषित किया है।

नीली अर्थव्यवस्था के बारे में:

- नीली अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए महासागरीय संसाधनों का सतत उपयोग है, जबकि महासागर पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को संरक्षित करता है।

अन्य नीली अर्थव्यवस्था पहल:

- महासागर सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी (ओ-स्मार्ट) योजना
- सतत विकास के लिए नीली अर्थव्यवस्था पर भारत-नॉर्वे टास्क फोर्स
- सागरमाला परियोजना
- राष्ट्रीय मात्स्यकी नीति
- एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन

भारत में सी प्लेन सेवाओं के लिए समझौता जापन

चर्चा में क्यों?

- बंदरगाह, जहाजरानी तथा जलमार्ग मंत्रालय तथा नागरिक उड़डयन मंत्रालय के बीच भारत में सी-प्लेन सेवाओं के लिए एक समझौता जापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया गया।



Follow us on
Telegram



नोट: अहमदाबाद में केवड़िया और साबरमती रिवरफ्रंट के बीच भारत की पहली सी प्लेन सेवा ने सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज के तहत अक्टूबर 2020 में परिचालन शुरू किया।

प्रमुख बिंदु

- इस MoU में भारत सरकार की RCS-UDAN (क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना- उड़े देश का आम नागरिक) स्कीम के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर सी-प्लेन सर्विसेज के गैर-अधिसूचित/अधिसूचित प्रचालन के विकास की परिकल्पना की गई है।
- MoU के अनुसार, विभिन्न स्थानों पर सी-प्लेन सर्विसेज के प्रचालन के कार्य को समय पर पूरा करने के लिए नागरिक उड़ान मंत्रालय, बंदरगाह, जहाजरानी तथा जलमार्ग मंत्रालय तथा पर्यटन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक समन्वयन समिति का गठन किया जाना है।
- नागरिक उड़ान मंत्रालय, बंदरगाह, जहाजरानी तथा जलमार्ग मंत्रालय, SDCL (सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड) सी-प्लेन आपरेटिंग रूटों के प्रचालन के कार्य पर विचार करेंगे जैसा कि सभी एजेन्सियों द्वारा चिन्हित/सुझाव दिया गया है।
- यह सी प्लेन के माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देकर और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देकर पूरे देश में सहज संपर्क को बढ़ाएगा।

UDAN योजना के बारे में:

- RCS-UDAN, "उड़े देश का आम नागरिक" भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय मार्गों पर स्तरीय आर्थिक रूप से व्यवहार्य और लाभदायक हवाई यात्रा प्रदान करना है।
- यह क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना आम आदमी को किफायती मूल्य पर उड़ान भरने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है।
- UDAN योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय नागरिक उड़ान नीति (NCAP) का एक प्रमुख घटक है जिसे नागरिक उड़ान मंत्रालय (भारत) द्वारा 15 जून 2016 को जारी किया गया था।

UDAN 4.1 के बारे में:

- UDAN 4.1 योजना छोटे हवाई अड्डों को जोड़ने के साथ-साथ विशेष हेलीकॉप्टर और सी प्लेन मार्गों पर केंद्रित है।

सागरमाला सी प्लेन सेवाएं:

- सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज बंदरगाह, जहाजरानी तथा जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक परियोजना है।
- यह परियोजना एयरलाइन ऑपरेटरों के माध्यम से एक विशेष प्रयोजन वाहन ढांचे के तहत शुरू की जा रही है।
- परियोजना निष्पादन और कार्यान्वयन सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (SDCL) के माध्यम से होगा।

2021-22 में 2 लाख से ज्यादा गांवों के SLWM में सहयोग के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत 40,700 करोड़ रुपये आवंटित किए गए

चर्चा में क्यों?

- जल शक्ति मंत्रालय, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBM-G) के दूसरे चरण के तहत साल 2021-22 में 40,700 करोड़ से अधिक रुपयों के निवेश के जरिए दो लाख से अधिक गांवों को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) व्यवस्था प्राप्त करने में सहायता करने के लिए तैयार है।
- जल शक्ति मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में SBM-G की राष्ट्रीय योजना अनुमोदन समिति ने राज्यों



Follow us on
Telegram



और केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक कार्यान्वयन योजना (AIP) को मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- SBM (G) के दूसरे चरण का उद्देश्य गांवों में खुले में शौच से मुक्ति (ODF) की स्थिरता पर फोकस और SLWM की व्यवस्था सुनिश्चित करके, व्यापक स्वच्छता प्राप्त करना है जिसे ODF प्लस का दर्जा भी कहा जाता है।
- 2021-22 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में, SLWM के लिए 2 लाख से अधिक गांवों के लक्षित सहयोग के अलावा, 50 लाख से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (IHHLs) और 1 लाख सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, भारत के 2400 से अधिक ब्लॉक्स में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों का निर्माण, 386 ज़िलों में गोबरधन परियोजना और 250 से अधिक ज़िलों में मल-कीचड़ प्रबंधन व्यवस्था शामिल हैं।

स्वच्छ भारत मिशन (SBM):

- स्वच्छ भारत मिशन (SBM) भारत सरकार द्वारा 2014 में खुले में शौच को खत्म करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करने के लिए शुरू किया गया एक देशव्यापी अभियान है।
- स्वच्छ भारत मिशन का पहला चरण अक्टूबर 2019 तक चला। दूसरे चरण को 2020-21 और 2024-25 के बीच लागू किया जा रहा है।
- मिशन को दो भागों में बांटा गया था: ग्रामीण और शहरी।

SBM के हिस्से के रूप में अन्य योजनाएं:

- गोबर-धन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक ऐव-एग्रो संसाधन धन) योजना
- व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (IHHL)
- स्वच्छ विद्यालय अभियान

स्रोत: PIB

बच्चों के लिए 14 पार-दिव्यांगता शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र

चर्चा में क्यों?

- केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग (दिव्यांगजन) के तहत 7 राष्ट्रीय संस्थानों और 7 समग्र क्षेत्रीय केंद्रों में स्थित 14 पार-दिव्यांगता शीघ्र हस्तक्षेप केंद्रों का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

दिव्यांगता शीघ्र हस्तक्षेप केंद्रों के बारे में:

- यह केंद्र अलग-अलग तरह की दिव्यांगता स्क्रीनिंग व पहचान, पुनर्वास, परामर्श, चिकित्सीय सेवाएं एक ही छत के नीचे लगातार प्रदान करेंगे।
- ये 14 शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र मुंबई, देहरादून, दिल्ली, सिंकंदराबाद, कोलकाता, कटक, लखनऊ, चेन्नई, सुरेन्द्रनगर, भोपाल, राजनांदगांव, पटना, नेल्लोर और कोझीकोड में शुरू किए गए हैं।
- इस अवसर पर दिव्यांग बच्चों के लिए शीघ्र हस्तक्षेप केंद्रों पर पुस्तिका का भी विमोचन किया गया।

आवश्यकता:

- साल 2011 की जनगणना के अनुसार, 0-6 वर्ष के आयु वर्ग में 20 लाख से अधिक दिव्यांग बच्चे हैं, जो दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, चलने में निश्कृतता आदि की श्रेणियों से संबंधित हैं।
- इसका मतलब है कि इस आयु वर्ग में देश के लगभग 7 प्रतिशत बच्चे किसी न किसी दिव्यांगता से ग्रसित हैं।
- दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम 2016 के लागू होने के साथ इनमें बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, क्योंकि अब 7 के बजाय दिव्यांगता श्रेणी में 21 श्रेणियां शामिल कर ली गई हैं।

अन्य पहल:

- दिव्यांगजनों के अधिकार (RPWD) अधिनियम 2016
- विशिष्ट विकलांगता पहचान (UDID) पोर्टल
- सुगम्य भारत अभियान
- दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना
- राष्ट्रीय न्यास की योजनाएं
- विकलांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप

स्रोत: PIB

COVID-19 अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के लिये 'विशेष क्रैश कोर्स' कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्किल इंडिया स्कीम के तहत COVID-19 अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के लिये छह 'विशेष क्रैश कोर्स' कार्यक्रम लॉन्च किया।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम 26 राज्यों में फैले 111 प्रशिक्षण केंद्रों में आयोजित किया जाएगा।
- इस पहल के तहत लगभग एक लाख अग्रिम पंक्तियों के कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

प्रमुख बिंदु

पाठ्यक्रम के बारे में:

- COVID योद्धाओं को छह अनुकूलित नौकरी भूमिकाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जैसे कि होम केयर सपोर्ट, बेसिक केयर सपोर्ट, एडवांस केयर सपोर्ट, इमरजेंसी केयर सपोर्ट, सेंपल कलेक्शन सपोर्ट और मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट।
- पाठ्यक्रम कार्यक्रम को 276 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के केंद्रीय घटक के तहत एक विशेष कार्यक्रम के रूप में तैयार किया गया है।
- पाठ्यक्रम कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्र में जनशक्ति की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुशल गैर-चिकित्सा स्वास्थ्य कर्मियों का निर्माण करेगा।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में:

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) का पहला संस्करण 2015 में शुरू किया गया था ताकि मुफ्त लघु अवधि कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके कौशल विकास को प्रोत्साहित और बढ़ावा दिया जा सके।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) 2.0 (2016-20) को क्षेत्रों, भौगोलिक क्षेत्रों को बढ़ाकर और भारत सरकार के अन्य मिशनों/कार्यक्रमों जैसे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत मिशन के साथ अधिक संरेखण द्वारा शुरू किया गया था।
- PMKVY 3.0 को दो चरणों में लागू किया जाएगा: पहला चरण वर्ष 2020-21 के दौरान पायलट आधार पर लागू किया जाएगा जिसे PMKVY 3.0 (2020-21) के रूप में जाना जाता है।

- योजना दूसरे चरण (2021-2026) के लिए एक कार्यान्वयन ढांचे के निर्माण की पहल करेगी।

स्रोत: PIB

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 को मंजूरी दी

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 को मंजूरी दी है जो देश में अंतर्देशीय जलमार्ग पर चलने वाले जहाजों को सुव्यवस्थित करने पर विचार करता है।
- अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 का स्थान लेगा।
- विधेयक अंतर्देशीय जहाजों की सुरक्षा और पंजीकरण को विनियमित करेगा।

प्रमुख बिंदु

अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 के बारे में:

- अंतर्देशीय पोत विधेयक, 2021 राज्यों द्वारा बनाए गए अलग नियमों के स्थान पर देश के लिए एक एकीकृत कानून के रूप में कार्य करेगा।
- यह पोत पंजीकरण, चालक दल और जहाजों के विवरण के रिकॉर्ड रखने के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस प्रदान करने में सहायता करेगा।
- बिल अंतर्देशीय जहाजों के लिए प्रटूषण नियंत्रण उपाय तैयार करेगा।
- यह राष्ट्रीय जलमार्गों को शामिल करके 'अंतर्देशीय जल' के दायरे का विस्तार करता है।

भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT):

- अब तक, देश में 4,000 किमी अंतर्देशीय जलमार्ग चालू हैं।
- देश में नदियों, बैकवाटर, नहरों, खाड़ियों आदि सहित लगभग 14,500 किमी नौगम्य जलमार्ग हैं।
- राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के अनुसार 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है।
- देश में अंतर्देशीय जल परिवहन लगभग 55 मिलियन टन कार्गो को ले जाने का एक ईंधन कुशल और पर्यावरण के अनुकूल तरीका है।
- राष्ट्रीय जलमार्ग 1 (NW-1): गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली (प्रयागराज-हल्दिया) जिसकी लंबाई 1620 किमी है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण:

- स्थापना: 27 अक्टूबर 1986
- मुख्यालय: नोएडा, उत्तर प्रदेश
- अध्यक्ष: अमिता प्रसाद
- मूल विभाग: बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय

स्रोत: द हिंदू

महत्वपूर्ण समाचार: विश्व

भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया

चर्चा में क्यों?

- भारत को कजाकिस्तान, अफगानिस्तान और ओमान के साथ एशिया-प्रशांत राज्यों की श्रेणी में **2022-24** की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) के लिए चुना गया है।

प्रमुख बिंदु

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) के बारे में:

- ECOSOC** संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है, जो संगठन के आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है।
- इसकी स्थापना 26 जून 1945 को हुई थी।
- परिषद में 54 सदस्य राज्य शामिल हैं।

नोट:

- भारत वर्तमान में 2021-22 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में सेवा कर रहा है और अगस्त 2021 में संयुक्त राष्ट्र के 15 देशों के अंग की अध्यक्षता ग्रहण करेगा।

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

G7: वैशिक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर

चर्चा में क्यों?

- G7 देशों के वित्त मंत्रियों ने वैशिक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर की स्थापना करते हुए एक ऐतिहासिक समझौते को अंतिम रूप दिया है।
- वैशिक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर के निर्णय पर जुलाई 2021 में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक में समझौते पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

वैशिक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर के बारे में:

- G7 देश कम-से-कम 15 प्रतिशत की वैशिक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर का समर्थन करेंगे और उन देशों में करों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये उपाय किये जाएंगे, जहाँ व्यवसाय संचालित होते हैं।
- कॉर्पोरेट कर अथवा निगम कर उस शुद्ध आय या लाभ पर लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है, जो उद्यम अपने व्यवसायों से लाभ कमाते हैं।

प्रयोज्यता:

- यह कंपनियों के विदेशी लाभ पर लागू होगा। ऐसे में यदि सभी देश वैशिक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर पर सहमत होते हैं, तब भी सरकारों द्वारा स्थानीय कॉर्पोरेट कर की दर स्वयं ही निर्धारित की जाएगी।
- किंतु यदि कंपनियाँ किसी विशिष्ट देश में कम दरों का भुगतान करती हैं, तो उनकी घरेलू सरकारें अपने करों को सहमत न्यूनतम दर पर ला सकती हैं, जिससे लाभ को टैक्स हेवन में स्थानांतरित करने का लाभ समाप्त हो जाता है।



Follow us on
Telegram



Gradeup
PCS & Other
State Exams



वैशिक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर की आवश्यकता:

- कर नुकसान की कमी
- कर एकरूपता

अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रयास:

- OECD (आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन) सीमा पार डिजिटल सेवाओं पर कर लगाने और वैशिक कॉर्पोरेट न्यूनतम कर सहित कर आधार क्षरण को रोकने के नियमों पर 140 देशों के बीच कर वार्ता का समन्वयन कर रहा है।

भारत का रुख़:

- भारत को वैशिक न्यूनतम 15 प्रतिशत कॉर्पोरेट कर दर समझौते से लाभ होने की संभावना है, क्योंकि भारत की प्रभावी घरेलू कर दर, 15 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा से अधिक है, और इस तरह भारत अधिक निवेश आकर्षित करता रहेगा।
- सितंबर 2019 में सरकार ने कंपनियों के लिये कॉर्पोरेट कर की दर को घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया था। इसके अलावा नई विनिर्माण फर्मों के लिये 15 प्रतिशत की दर की पेशकश की गई थी।
- भारतीय घरेलू कंपनियों के लिये प्रभावी कर दर, अधिभार और उपकर सहित, लगभग 25.17 प्रतिशत है।

G7 के बारे में तथ्यः

- यह एक अंतर सरकारी संगठन है।
- स्थापना: 1975
- सदस्यः यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली
- सभी G7 देश और भारत G20 का हिस्सा हैं।

स्रोतः द हिंदू

लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए वैशिक डेटाबेस I-Familia (आई-फैमिलिया) शुरू किया गया

चर्चा में क्यों?

- इंटरपोल ने परिवार के DNA (डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड) के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने और सदस्य देशों के जटिल मामलों को सुलझाने में पुलिस की मदद करने के लिये I-Familia (आई-फैमिलिया) नामक एक नया वैशिक डेटाबेस लॉन्च किया है।

प्रमुख बिंदु

I-Familia के बारे मेंः

- I-Familia अंतर्राष्ट्रीय DNA नातेदारी संबंधों के आधार पर लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिये इस प्रकार का पहला वैशिक डेटाबेस है।
- इंटरपोल की I-Familia सेवा लापता व्यक्तियों के DNA डेटा की वैशिक स्तर पर तुलना करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय तंत्र प्रदान करती है।
- I-Familia स्मार्ट रिसर्च द्वारा विकसित एक फोरेंसिक DNA मिलान सॉफ्टवेयर सिस्टम, बोनापार्ट द्वारा संचालित है।

इंटरपोल के बारे मेंः

- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से जाना जाता है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है।

मुख्यालय: ल्योन, फ्रांस
अध्यक्ष: किम जॉंग यांग
स्थापना: 7 सितंबर 1923

स्रोत: द हिंदू

वीवाटेक का 5वां संस्करण

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीवाटेक 2021 के 5वें संस्करण में मुख्य भाषण दिया।

प्रमुख बिंदु

वीवाटेक के बारे में:

- विवा टेक यूरोप में सबसे बड़ी डिजिटल और स्टार्टअप आयोजनों में एक है। इसका आयोजन 2016 के बाद से हर वर्ष पेरिस में किया जाता है।
- इसका आयोजन संयुक्त रूप एक प्रमुख विज्ञापन और विपणन समूह पब्लिसिज ग्रुप और अग्रणी फ्रांसीसी मीडिया समूह लेस इकोस द्वारा किया जाता है।
- यह प्रौद्योगिकी नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम के हितधारकों को एक साथ लाता है। इस आयोजन में प्रदर्शनियां, पुरस्कार, पैनल चर्चा और स्टार्टअप प्रतियोगिताएं शामिल की जाती हैं।

भाषण के मुख्य बिंदु:

- इन्फोसिस फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट के लिए तकनीक समर्थन उपलब्ध करा रही है और एटस, कैपाजेमिनी जैसी फ्रांस की कंपनियों के साथ सहयोग कर रही है, वहीं भारत की TCS और विप्रो दुनिया भर की कंपनियों व नागरिकों की सेवा करने वाली दोनों देशों की IT प्रतिभा का उदाहरण हैं।
- भारत की यूनिवर्सल और विशेष बायो मीट्रिक डिजिटल पहचान प्रणाली - आधार- ने गरीबों को समयबद्ध वित्तीय समर्थन उपलब्ध कराने में सहायता की।
- विद्यार्थियों की मदद के लिए दो सरकारी डिजिटल शिक्षा कार्यक्रमों- स्वयं और दीक्षा के संचालन में सक्षम हुए हैं।
- स्वदेशी IT प्लेटफॉर्म आरोग्य सेतु ने प्रभावी संपर्क अनुरेखण को सक्षम बनाया है।
- COWIN डिजिटल प्लेटफॉर्म से पहले ही करोड़ों लोगों को वैक्सीन सुनिश्चित करने में मदद मिल चुकी है।
- प्रधानमंत्री ने अत्याधुनिक सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना, 1.56 लाख ग्राम परिषदों को जोड़ने के लिए 5.23 लाख किलोमीटर लंबे फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, देश भर में सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क जैसी पहलों का उल्लेख किया।
- अटल नवाचार मिशन के अंतर्गत देश में 7,500 स्कूलों में अत्याधुनिक नवाचार प्रयोगशालाएं हैं।

13वें BRICS शिखर सम्मेलन के भाग के रूप में IIT बॉम्बे ने BRICS नेटवर्क विश्वविद्यालयों की कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया

चर्चा में क्यों?

- IIT बॉम्बे ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विषय पर BRICS (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) नेटवर्क विश्वविद्यालयों के तीन दिवसीय वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया।



Follow us on
Telegram



- 13वें BRICS शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता के दौरान शिक्षा स्ट्रीम के तहत भारत द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के 18 विशेषज्ञ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विभिन्न पहलुओं जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड वाहन, लिथियम-आयन बैटरी के साथ-साथ ई-मोबिलिटी और आजीविका के बीच संबंध के बारे में बात किये।

BRICS नेटवर्क विश्वविद्यालय के बारे में:

- BRICS नेटवर्क विश्वविद्यालय पांच BRICS सदस्य देशों के उच्च शिक्षा संस्थानों का एक संघ है। इसका गठन शैक्षिक सहयोग, विशेष रूप से अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में, बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है।
- BRICS नेटवर्क विश्वविद्यालय के लिए IIT बॉम्बे भारत का प्रमुख संस्थान है।
- नोट: 13 वां BRICS शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की अध्यक्षता के तहत आयोजित किया जाएगा, और 2012 और 2016 के बाद तीसरी बार भारत BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
- 2021 के लिए भारत की अध्यक्षता का विषय 'BRICS @ 15: इंट्रा- BRICS कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेन्सस' होगा।
- BRICS के बारे में तथ्य:
 - स्थापना: 2009
 - देश: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका

SIPRI रिपोर्ट: चीन, भारत, पाकिस्तान ने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार किया

चर्चा में क्यों?

- स्वीडिश थिंक टैंक, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) ने SIPRI ईयरबुक 2021, जो हथियारों, निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की वर्तमान स्थिति का आकलन करता है, के निष्कर्षों को लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

- 2021 की शुरुआत में भारत के पास अनुमानित 156 परमाणु हथियार हैं पिछले साल की शुरुआत में 150 की तुलना में।
- पाकिस्तान- 165 परमाणु हथियार
- चीन- 350 परमाणु हथियार
- रूस- 6255 परमाणु हथियार
- USA- 5550 परमाणु हथियार
- 2021 की शुरुआत में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, पाकिस्तान, भारत, इज़राइल और उत्तर कोरिया के पास अनुमानित 13,080 परमाणु हथियार थे।
- अमेरिका और रूस के पास कुल मिलाकर 90% से अधिक वैश्विक परमाणु हथियार हैं।



Follow us on
Telegram



नोट:

- भारत, सऊदी अरब, मिस्र, चीन और ऑस्ट्रेलिया 2016 और 2020 के बीच दुनिया में प्रमुख हथियारों के पांच सबसे बड़े आयातक थे।
- सऊदी अरब की हिस्सेदारी 11 प्रतिशत और भारत की 9.5 प्रतिशत के वैश्विक आयात इस समयावधि में प्रमुख हथियारों में थी।

परमाणु प्रसार और परीक्षण को रोकने वाली संधियाँ:

- आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि (PTBT)
- व्यापक परमाणु परीक्षण-प्रतिबंध संधि (CTBT)
- परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि (TPNW)
- परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि (NTP)

भारत का परमाणु हथियार कार्यक्रम:

- भारत ने मई 1974 में अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण किया।
- हालाँकि भारत का अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ एक सुविधा-विशिष्ट सुरक्षा उपाय समझौता है और उसे परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) से छूट मिली है जो इसे वैश्विक नागरिक परमाणु प्रौद्योगिकी वाणिज्य में भाग लेने की अनुमति देता है।
- भारत को 2016 में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR) और 2017 में वासेनर अरेंजमेंट में सदस्य के रूप में शामिल किया गया था।

HIV/AIDS की रोकथाम पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75 वां सत्र

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 75वें सत्र को संबोधित किया।
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने UNGA प्रस्ताव 75/260 पर बात की जो HIV/AIDS पर प्रतिबद्धता की घोषणा और HIV/AIDS पर राजनीतिक घोषणाओं के कार्यान्वयन से संबंधित है।

प्रमुख बिंदु

संबोधन के मुख्य बिंदु:

- भारत में, HIV और AIDS रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम, 2017, संक्रमित तथा प्रभावित आबादी के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए एक कानूनी और सक्षम ढांचा प्रदान करता है।
- भारत का विशिष्ट HIV रोकथाम मॉडल 'सोशल कॉन्ट्रैक्टिंग' की अवधारणा के इर्द-गिर्द केंद्रित है, जिसके जरिए सिविल सोसाइटी की मदद से 'लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम' लागू किया जाता है।
- कार्यक्रम का उद्देश्य व्यवहार परिवर्तन, संचार, आउटरीच, सेवा वितरण, काउंसलिंग एवं जांच करना और HIV स्वास्थ्य सेवा के साथ इनका मेल सुनिश्चित करना है।
- भारत करीब 14 लाख लोगों को मुफ्त एंटी-रेट्रो-वायरल उपचार मुहैया करा रहा है।
- अफ्रीका में HIV से पीड़ित लाखों लोगों तक भी भारतीय दवाएं पहुंच रही हैं।

भारत के राष्ट्रीय AIDS नियंत्रण कार्यक्रम:

- NACO (राष्ट्रीय AIDS नियंत्रण संगठन), 1992 में स्थापित भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक प्रभाग है जो 35 HIV/AIDS रोकथाम और नियंत्रण समितियों के माध्यम से भारत में HIV/AIDS नियंत्रण कार्यक्रम को नेतृत्व प्रदान करता है।
- भारत के राष्ट्रीय इस नियंत्रण कार्यक्रम को दुर्गम और जोखिम वाली आबादी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संशोधित, पुनर्जीवित और परिवर्तित किया गया है।

SDG (सतत विकास लक्ष्य) और HIV/AIDS: HIV प्रतिक्रिया से संबंधित कई SDG हैं:

- SDG 3: स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करें और सभी उम्र के लोगों के लिए भलाई को बढ़ावा दें।
- लक्ष्य 3.3: 2030 तक AIDS को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करना
- SDG 4: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
- SDG 5: लैंगिक समानता
- SDG 10: असमानताओं में कमी
- SDG 16: शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं

अन्य पहलें:

- लाल रिबन
- परियोजना सूर्योदय
- 90-90-90
- GFATM (AIDS, तपेदिक और मलेरिया से लड़ने के लिए वैशिक कोष)

HIV (ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस):

- ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस (HIV) एक संक्रमण है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है, विशेष रूप से सफेद रक्त कोशिकाओं को जिसे CD 4 कोशिकाएं कहा जाता है।
- HIV इन CD4 कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिससे तपेदिक और कुछ कैंसर जैसे संक्रमणों के खिलाफ व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है।

स्रोत: PIB

47वां G7 लीडर्स समिट 2021

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 47वां G7 लीडर्स समिट 2021 को संबोधित किया।
- 47वां G7 शिखर सम्मेलन 11-13 जून 2021 को यूनाइटेड किंगडम के कॉर्नवाल में आयोजित किया गया था, और इसने G7 की अध्यक्षता की थी।
- भारत के अलावा, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को भी "अतिथि देशों" के रूप में शिखर सम्मेलन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था।
- नोट: इससे पहले, G7 के वित्त मंत्री वैशिक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर निर्धारित करने वाले एक ऐतिहासिक समझौते पर पहुंचे थे।

प्रमुख बिंदु

बिल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड (B3W) प्रोजेक्ट:

- B3W परियोजना सामूहिक रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों (एशिया और अफ्रीका में) के लिए सैकड़ों अरबों के बुनियादी ढांचे के निवेश को उत्प्रेरित करेगी और G7 के साथ एक मूल्य-संचालित, उच्च-मानक और पारदर्शी साझेदारी की पेशकश करेगी।

लोकतंत्र 11:

- G7 और अतिथि देशों द्वारा "खुले समाज" पर एक संयुक्त बयान (डेमोक्रेसी 11) पर हस्ताक्षर किए गए, जो लोकतंत्र की रक्षा करने वाली स्वतंत्रता के रूप में, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल्यों की पुष्टि और प्रोत्साहित करता है।
- यह बयान राजनीतिक रूप से प्रेरित इंटरनेट शटडाउन को स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए खतरों में से एक के रूप में भी संदर्भित करता है।

कार्बिस बे घोषणा:

- G7 ने कार्बिस बे घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य भविष्य की महामारियों को रोकना है।
- G7 ने गरीब देशों के लिए 1 बिलियन से अधिक कोरोना वायरस वैक्सीन खुराक का भी वादा किया, जिसमें से आधा संयुक्त राज्य अमेरिका से और 100 मिलियन ब्रिटेन से आयेगा।

जलवायु परिवर्तन:

- 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने का संकल्प लिया।

भारत का रुखः

- सत्तावाद, आतंकवाद और हिंसक चरमपंथ, दुष्प्रचार और आर्थिक दबाव से उत्पन्न खतरों से साझा मूल्यों की रक्षा करने में भारत G7 देशों के लिए एक स्वाभाविक सहयोगी है।
- इसने COVID-19 टीकों के लिए पेटेंट सुरक्षा को उठाने के लिए समूह का समर्थन मांगा।
- ग्रह के वातावरण, जैव विविधता और महासागरों को सिलोस में काम करने वाले देशों द्वारा संरक्षित नहीं किया जा सकता है, और जलवायु परिवर्तन पर सामूहिक कार्रवाई का आहवान किया।
- भारत एकमात्र G-20 देश है जो अपनी पेरिस प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की राह पर है।

G7 के बारे में तथ्यः

- यह एक अंतर सरकारी संगठन है।
- स्थापना:** 1975
- सदस्य:** यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और इटली
- स्रोत:** इंडियन एक्सप्रेस

अल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला पहला देश बना

चर्चा में क्यों?

- अल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है।
- कानूनी निविदा के रूप में इसका उपयोग 90 दिनों में शुरू होगा, बाजार द्वारा निर्धारित बिटकॉइन-डॉलर विनिमय दर के साथ।

प्रमुख बिंदु

- बिटकॉइन का उपयोग व्यक्तियों के लिए वैकल्पिक होगा और इससे उपयोगकर्ताओं को कोई जोखिम नहीं होगा।



Follow us on
Telegram



- बिटकॉइन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है, अल सल्वाडोर की कम बैंकिंग प्रवेश दर का मुकाबला करने में मदद कर सकता है और एक वर्ष में \$ 6 बिलियन के प्रेषण के लिए तेजी से हस्तांतरण की सुविधा प्रदान कर सकता है।

बिटकॉइन के बारे में:

- यह एक केंद्रीय बैंक या एकल प्रशासक के बिना एक विकेन्द्रीकृत डिजिटल मुद्रा है जिसे बिचौलियों की आवश्यकता के बिना पीयर-टू-पीयर बिटकॉइन नेटवर्क पर उपयोगकर्ता से उपयोगकर्ता को भेजा जा सकता है।

अल सल्वाडोर के बारे में तथ्य:

- राष्ट्रपति:** नायब बुकेले
- राजधानी:** सैन सल्वाडोर
- मुद्रा:** यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर (USD)

स्रोत: द हिंदू

FAO (खाद्य एवं कृषि संगठन) सम्मेलन का 42वां सत्र

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने FAO सम्मेलन के 42वें सत्र को संबोधित किया।
- भारत FAO का संस्थापक सदस्य है और इसकी स्थापना के बाद से भारत ने विभिन्न वैधानिक निकायों और समितियों के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

प्रमुख बिंदु

COVID 19 महामारी के दौरान खाद्य सुरक्षा के लिए भारत के प्रयास:

- भारत में कृषि क्षेत्र ने गंभीर COVID-19 महामारी के दौरान भी अच्छा प्रदर्शन किया और 305 मिलियन टन खाद्यान्न का सर्वकालिक उच्च उत्पादन दर्ज किया साथ ही उनके निर्यात ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा में योगदान दिया।
- प्रशीतन सुविधाओं के साथ विशेष पार्सल ट्रेनों "किसान रेल" को भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया।
- भारत सरकार ने "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज" का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 81 करोड़ हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया।
- किसानों को आय सहायता प्रदान करने के लिए "PM किसान" योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 1,37,000 करोड़ रुपये से अधिक भेजे गए हैं।

जलवायु परिवर्तन और कृषि योजनाएं:

- हरित भारत मिशन
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
- कृषि वानिकी पर उप-मिशन
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड
- परम्परागत कृषि विकास योजना
- पूर्वतर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट

- भारत ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के लिए कृषि को लचीला बनाने के लिए तकनीकों के विकास, प्रदर्शन और प्रसार के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया है।
- हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नील क्रांति के साथ-साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली और किसानों के लिए मूल्य समर्थन प्रणाली।

खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के बारे में तथ्य:

- स्थापना:** 16 अक्टूबर 1945
- मुख्यालय:** रोम, इटली
- मूल संगठन:** संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद
- महानिदेशक:** कव डॉग्यू

नोट:

- 16 अक्टूबर 2020 को FAO के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत और FAO के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को मनाने के लिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक विशेष 75 रूपये का स्मारक सिक्का जारी किया था।

स्रोत: PIB

8वीं ASEAN डिफ़ेस मिनिस्टर्स मीटिंग-प्लस

चर्चा में क्यों?

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 जून, 2021 को 8वीं ASEAN डिफ़ेस मिनिस्टर्स मीटिंग (ADMM) प्लस को संबोधित करते हुए राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के आधार पर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक खुली और समावेशी व्यवस्था का आह्वान किया।
- ब्रुनेई 2021 में ADMM प्लस फोरम की अध्यक्षता कर रहा है।

प्रमुख बिंदु

ASEAN डिफ़ेस मिनिस्टर्स मीटिंग (ADMM) प्लस के बारे में:

- ADMM प्लस 10 ASEAN देशों और उसके आठ वार्ता सहयोगियों - ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस और अमेरिका के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक है।

दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन (ASEAN) के बारे में तथ्य:

- ASEAN के 10 सदस्य देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फ़िलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया हैं।
- मुख्यालय:** जकार्ता, इंडोनेशिया
- स्थापना:** 8 अगस्त 1967

बैठक के मुख्य बिंदु:

- भारत हिंद-प्रशांत के लिए साझा व्हिट्कोण के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में ASEAN के नेतृत्व वाले तंत्र के उपयोग का समर्थन करता है।



Follow us on
Telegram



- भारत ने संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी (UNCLOS) के अनुसार अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में सभी के लिए नौवहन की स्वतंत्रता, समुद्री क्षेत्र में उड़ान और बेरोकटोक व्यापार की आजादी सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर दिया।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र की शांति, स्थिरता, समृद्धि और विकास के लिए संचार के समुद्री क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं।
- नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित 'एक्ट इंस्ट पॉलिसी' पर इस नीति के प्रमुख तत्वों का उद्देश्य आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर निरंतर जुड़ाव के माध्यम से हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ रणनीतिक संबंध विकसित करना है।
- वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) के सदस्य के तौर पर भारत वित्तीय आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।
- मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) अभियानों के द्वारा भारत अपने करीबी तथा दूर स्थित पड़ोसी देशों में संकट के समय सबसे पहले सहायता देने वाले देशों में से एक है।
- हेडस ऑफ एशियन कोस्टगार्ड एर्जेंसीज मीटिंग (HACGAM) के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत समुद्री खोज और बचाव के क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से क्षमता निर्माण को बढ़ाना चाहता है।

स्रोत: PIB

G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने 22 जून, 2021 को G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया।
- इस बैठक की मेजबानी इटली ने मिश्रित रूप में की।

प्रमुख बिंदु

- G20 शिक्षा मंत्रियों ने विशेष रूप से COVID-19 के संदर्भ में शैक्षणिक गरीबी और असमानताओं के खिलाफ लड़ाई में प्रगति पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
- शिक्षा मंत्रियों ने मिश्रित शिक्षा के माध्यम से शिक्षा विधियों की निरंतरता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए COVID-19 के दौरान कार्यान्वित नवीन अनुभवों को साझा करने का भी संकल्प लिया।
- मिश्रित शिक्षा एक ऐसा दृष्टिकोण है जो ऑनलाइन शैक्षणिक सामग्री और पारंपरिक स्थान-आधारित कक्षा विधियों के साथ ऑनलाइन बातचीत के अवसरों को जोड़ती है।

भारत में शिक्षा:

- भारत के प्रयास:** स्कूलों की प्रवेश क्षमता बढ़ाना; स्कूल न जाने वाले बच्चों पर नज़र रखना; कमज़ोर छात्रों के सीखने के परिणामों की निगरानी करना; बच्चों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए मध्याह्न भोजन; बाल अधिकारों के उल्लंघन के लिए शारीरिक सुरक्षा और जीरो टॉलरेंस सुनिश्चित करना; विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सक्षम तंत्र; सीखने और मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए कई मार्गों को बढ़ावा देना।
- दीक्षा, स्वयं जैसे विभिन्न ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर डिजिटल शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई गई है,** जिसे कोई भी, किसी भी समय और कहाँ भी इसका लाभ हासिल कर सकता है।
- पारंपरिक शिक्षा में स्वीकृत ऑनलाइन कम्पोनेंट** को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है।



Follow us on
Telegram



- प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा को सहायता देने के लिए NEP 2020 के तहत एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना की जा रही है।
- सरकार मनोरंजन और अन्य परामर्श कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को दूर करने पर भी विशेष ध्यान दे रही है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020** का उद्देश्य है कि 2025 तक स्कूल और उच्च शिक्षा व्यवस्था के कम से कम 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा मिल जाए।
- एक राष्ट्रीय कौशल पात्रता फ्रेमवर्क के माध्यम से व्यावसायिक विषयों से जुड़े विद्यार्थियों के लिए व्यापक बदलाव सुनिश्चित किया जा रहा है।
- इस फ्रेमवर्क के तहत स्टैंडर्ड्स को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीय मानक वर्गीकरण के अनुरूप बनाया जाएगा।

G20 के बारे में तथ्य:

स्थापन: 26 सितंबर 1999

सदस्य: 20 (अर्जीटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ)

स्रोत: PIB

G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में घोषणा और रोजगार कार्य समूह (EWG) प्राथमिकताओं पर मंत्रिस्तरीय भाषण दिया।
- भारत श्रम शक्ति भागीदारी में लैंगिक अंतर कम करने के लिए सामूहिक प्रयास कर रहा है।

प्रमुख बिंदु

चर्चा के मुद्दे:

- रोजगार कार्य समूह (EWG) ने महिलाओं के रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और दूरदराज के कामकाज सहित प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।
- बैठक का विषय श्रम बाजारों और समाजों की समावेशी, टिकाऊ और लचीली वसूली को बढ़ावा देना है।
- वर्ष 2014 में G20 के नेताओं ने ब्रिसबेन में श्रम शक्ति भागीदारी दरों में पुरुषों और महिलाओं के बीच के अंतर को **2025 तक 25 प्रतिशत** कम करने का संकल्प किया था।

भारत द्वारा की गई पहल:

- देश शिक्षा, कौशल, प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास और समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित कर रहा है।
- मजदूरी पर नई संहिता, 2019** से मजदूरी, भर्ती और रोजगार की शर्तों में लिंग आधारित भेदभाव कम होगा।
- सर्वैतनिक मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई है।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) में महिला उद्यमियों को छोटे उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई है। इस योजना में लगभग 70 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं। इस योजना के तहत 9 हजार बिलियन रुपये के जमानत मुक्त ऋण वितरित किए गए हैं।



Follow us on
Telegram



Gradeup
State PCS



- सामाजिक सुरक्षा संबंधी नई संहिता में अब स्वरोजगार और कार्य बल के अन्य सभी वर्गों को भी सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में शामिल किया जा सकता है।
- ब्रिस्बेन लक्ष्य की ओर और उससे आगे के G20 रोडमैप को हमारे श्रम बाजारों के साथ-साथ सामान्य रूप से समाजों में महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अवसर और परिणाम प्राप्त करने के लिए विकसित किया गया है।

श्रम शक्ति भागीदारी:

- श्रम शक्ति भागीदारी दर कामकाजी उम के सभी लोगों के प्रतिशत को इंगित करती है जो कार्यरत हैं या सक्रिय रूप से काम की तलाश कर रहे हैं।
- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, 2018-19 के अनुसार, भारत में 15 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं में महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) ग्रामीण क्षेत्रों में 26.4 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 20.4 प्रतिशत है।
- ILO के अनुमानों के अनुसार, 2019 में, COVID-19 महामारी से पहले, भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी 23.5% थी।

नोट: G20 लीडर्स समिट 2021 का आयोजन अक्टूबर 2021 में रोम इटली में होगा। 2021 के लिए, इटैलियन प्रेसीडेंसी के तहत G20, कार्रवाई के तीन व्यापक, परस्पर जुड़े स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करेगा: लोग, ग्रह और समृद्धि।

स्रोत: PIB

महत्वपूर्ण समाचार: अर्थव्यवस्था

विश्व बैंक: भारतीय अर्थव्यवस्था 2021 में 8.3% बढ़ेगी

चर्चा में क्यों?

- विश्व बैंक ने अप्रैल 2021 में अनुमानित 10.1 प्रतिशत से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने 2021-22 GDP विकास अनुमान को घटाकर 8.3 प्रतिशत कर दिया।

प्रमुख बिंदु

भारत के लिए:

- वाशिंगटन स्थित वैशिक ऋणदाता ने जून 2021 के वैशिक आर्थिक संभावनाओं के अपने नवीनतम अंक में कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 8.3%, 2022-23 के लिए 7.5% और 2023-24 के लिए 6.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है।

विश्व के लिए:

- वैशिक अर्थव्यवस्था 2021 में 5.6 प्रतिशत तक विस्तार करने के लिए तैयार है - 80 वर्षों में इसकी सबसे मजबूत मंदी के बाद की गति।

भारत द्वारा उठाए गए कदम:

- सरकार ने घोषणा की कि स्वास्थ्य संबंधी खर्च दोगुने से अधिक होगा और महामारी की आर्थिक विरासत को संबोधित करने के उद्देश्य से एक संशोधित मध्यम अवधि के राजकोषीय मार्ग को निर्धारित करेगा।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम फर्मों को तरलता प्रावधान का समर्थन करने के लिए और गैर-निष्पादित ऋणों के प्रावधान पर नियामक आवश्यकताओं को कम करने के लिए और उपायों की घोषणा की।

विश्व बैंक के बारे में:

- विश्व बैंक की स्थापना 1944 के ब्रेटन वुडस सम्मेलन में हुई थी।
- इसमें दो संस्थान शामिल हैं: पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD), और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA)।
- विश्व बैंक विश्व बैंक समूह का एक घटक है।

विश्व बैंक समूह के पांच अंतर्राष्ट्रीय संगठन:

- पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD)
- अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA)
- अंतर्राष्ट्रीय वित निगम (IFC)
- बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (MIGA)
- वेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICSID)

सदस्यता

- 189 देश (IBRD)
- 173 देश (IDA)

प्रमुख रिपोर्ट:

- विश्व विकास रिपोर्ट



Follow us on
Telegram



- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
- मानव पूंजी सूचकांक
- वैश्विक आर्थिक संभावनाएं
- प्रवासन और विकास संक्षिप्त

स्रोत: द हिंदू

भारत FDI प्रवाह का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता: UNCTAD रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

- संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD) के द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार, भारत ने 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में 64 बिलियन डॉलर प्राप्त किया, जिससे यह दुनिया में 5वां सबसे बड़ा अंतर्वाह का प्राप्तकर्ता बन गया है।

प्रमुख बिंदु

- वैश्विक FDI प्रवाह महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ है और 2020 में 35 प्रतिशत गिरकर 2019 में 1.5 ट्रिलियन डॉलर से 1 ट्रिलियन डॉलर हो गया है।
- **2020 में FDI अंतर्वाह:**
 - रैंक 1: US
 - रैंक 2: चीन
 - रैंक 5: भारत
- **2020 में FDI बहिर्वाह:**
 - रैंक 1: चीन
 - रैंक 2: लक्ज़मर्बर्ग
 - रैंक 18: भारत

भारत का FDI:

- भारत में, FDI 2019 में 51 बिलियन डॉलर से 2020 में 27 प्रतिशत बढ़कर 64 बिलियन डॉलर हो गया, जिसे ICT (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) उद्योग में अधिग्रहण से आगे बढ़ाया गया।
- महामारी ने वैश्विक स्तर पर डिजिटल बुनियादी ढांचे और सेवाओं की मांग को बढ़ावा दिया।
- भारत FDI बहिर्वाह के लिए दुनिया की शीर्ष 20 अर्थव्यवस्थाओं में से 18वें स्थान पर है, 2019 में 13 बिलियन डॉलर की तुलना में 2020 में देश से 12 बिलियन डॉलर का बहिर्वाह दर्ज किया गया।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD) के बारे में:

- UNCTAD एक स्थायी अंतरसरकारी निकाय है। यह व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दों से संबंधित है।
- **मूल संगठन:** संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA); संयुक्त राष्ट्र सचिवालय
- **मुख्यालय:** जिनेवा, स्विटजरलैंड
- **स्थापना:** 30 दिसंबर 1964

FDI को बढ़ावा देने के लिए सरकारी उपाय:

- FDI से जुड़े नीतिगत सुधारों, निवेश को सुविधाजनक बनाने और कारोबार करने में आसानी सुनिश्चित करने के मोर्चों पर किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप देश में FDI प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।
- निवेश को आकर्षित करने वाली योजनाओं का शुभारंभ, जैसे, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना आदि, और विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मानिर्भर भारत के तहत पहल शामिल है।

स्रोत: द हिंदू

महत्वपूर्ण समाचार: रक्षा

अपतटीय गश्ती पोत 'सजग' को भारतीय तटरक्षक में कमीशन किया गया

चर्चा में क्यों?

- राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपतटीय गश्ती पोत (OPV) 'सजग' को भारतीय तटरक्षक (ICG) में शामिल कर समुद्री हितों की रक्षा के लिए इसे राष्ट्र को समर्पित किया।

प्रमुख बिंदु

- सजग मेक इन इंडिया नीति के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पांच अपतटीय गश्ती पोतों में से तीसरा है।
- OPV सजग का निर्माण मेसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है।
- अन्य चार OPV भारतीय तटरक्षक पोत (ICGS) सक्षम, ICGS सचेत, ICGS सुजीत और ICGS सार्थक हैं।

भारतीय तटरक्षक के बारे में:

- भारतीय तटरक्षक भारत की एक समुद्री कानून प्रवर्तन और खोज और बचाव एजेंसी है, जिसका क्षेत्राधिकार इसके सन्निहित क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र सहित अपने क्षेत्रीय जल पर है।
- भारतीय तटरक्षक को भारत की संसद के तटरक्षक अधिनियम, 1978 द्वारा स्थापित किया गया था।
- यह रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है।
- एक बहु-आयामी तटरक्षक के लिए खाका दूरदर्शी रुस्तमजी समिति द्वारा तैयार किया गया था।

नोट: सरकार के 'मेक इन इंडिया' के विजय के अनुरूप निजी यार्ड सहित देश के भीतर विभिन्न शिपयार्डों में ICG जहाजों का निर्माण किया जा रहा है।

- ICG के बेडे में कुल 160 जहाज और 62 विमान हैं।

दूसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची

चर्चा में क्यों?

- रक्षा मंत्रालय (MoD) ने 108 वस्तुओं की 'दूसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची' अधिसूचित की है।

प्रमुख बिंदु

दूसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची के बारे में:



Follow us on
Telegram



- रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सभी 108 वस्तुओं की खरीद स्वदेशी स्रोतों से की जाएगी।

- इस दूसरी सूची को दिसंबर 2021 से दिसंबर 2025 तक उत्तरोत्तर लागू किए जाने की योजना है।
- इससे आत्मनिर्भरता हासिल करने और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के साथ स्वदेशीकरण को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।

नोट: अगस्त 2020 में, 101 वस्तुओं वाली 'पहली सकारात्मक स्वदेशीकरण' सूची को अधिसूचित किया गया था।

रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP 2020) के बारे में:

- रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP 2020), जो रक्षा खरीद प्रक्रिया 2016 (DAP 2016) का स्थान लेती है, पूँजी खरीद प्रक्रिया में सुधार के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा एक ईमानदार प्रयास है।

रक्षा उपकरण का घरेलू उत्पादन बढ़ाने की अन्य पहल:

- रक्षा औद्योगिक कॉरीडोर: प्रमुख "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए भारत ने दो रक्षा औद्योगिक कॉरीडोर, तमिलनाडु में एक और दूसरा उत्तर प्रदेश में उट्टघाटन किया।
- घरेलू क्षेत्र के लिए पूँजीगत अधिग्रहण बजट बढ़ाया
- केंद्र सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 से बढ़ाकर 74% और सरकारी मार्ग से 74% से अधिक कर दी है।
- रक्षा भारत स्टार्टअप चुनौती
- आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण

नोट: रक्षा मंत्रालय द्वारा 'रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति (DPEPP) 2020' का अंतिम संस्करण भी जारी करने की उम्मीद है।

इंडो-थाई समन्वित गश्त (CORPAT) 2021

चर्चा में क्यों?

- भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच भारत-थाईलैंड समन्वित गश्त (इंडो-थाई CORPAT) का 31 वां संस्करण दिनांक 09 से 11 जून 2021 के बीच आयोजित किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- भारतीय नौसेना का स्वदेशी निर्मित नौसैनिक अपतटीय गश्ती पोत जहाज (INS) सरयू एवं थाईलैंड का अपतटीय गश्ती पोत हिज मजेस्टीस थाइलैंड शिप (HTMS) कर्बी तथा दोनों नौसेनाओं के डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान- CORPAT में भाग ले रहे हैं।

CORPAT के बारे में:

- दोनों नौसेनाएं 2005 से अपनी अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) पर CORPAT का द्वि-वार्षिक आयोजन कर रही हैं।
- CORPAT नौसेनाओं के बीच समझ और अंतरसंचालनीयता निर्मित करती है और अवैध असूचित अनियमित मछली पकड़ना, मादक पदार्थों की तस्करी, समुद्री आतंकवाद, सशस्त्र डैकेती और समुद्री डैकेती जैसी गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने और खत्म करने के उपायों के ढांचे को सुविधा प्रदान करता है।

SAGAR के बारे में:

- SAGAR (सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फँड इन द रीजन) के भारत सरकार के वृष्टिकोण के एक भाग के तौर पर, भारतीय नौसेना क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रही है।
- ऐसा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभ्यासों, समन्वित गश्ती, संयुक्त EEZ निगरानी और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत (HADR) अभियानों के माध्यम से किया गया है।

iDEX - DIO के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में नवाचार

चर्चा में क्यों?

- रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अगले पांच वर्षों के लिए रक्षा उत्कृष्टता में नवाचार (iDEX)-रक्षा नवाचार संगठन (DIO) के लिए नवाचार हेतु 498.8 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता को मंजूरी दे दी है।
- इससे पहले, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साल 2020 में रक्षा मंत्रालय की ओर से किए गए प्रमुख सुधारों पर प्रकाश डालते हुए '20 रिफॉर्म्स इन 2020' शीर्षक से एक ई-बुकलेट जारी की।

प्रमुख बिंदु

- अगले पांच वर्षों के लिए 498.8 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता वाली इस योजना का उद्देश्य DIO फ्रेमवर्क के तहत लगभग 300 स्टार्ट-अप्स/MSME/व्यक्तिगत नवोन्मेषकों और 20 साझेदार इनक्यूबेटर को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- रक्षा उत्कृष्टता में नवाचार (iDEX) अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था।
- रक्षा उत्पादन विभाग (DDP) द्वारा iDEX के निर्माण और DIO की स्थापना का उद्देश्य MSME, स्टार्ट-अप्स, व्यक्तिगत नवोन्मेषकों, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और शिक्षाजगत समेत उद्योगों को शामिल करके रक्षा और एयरोस्पेस में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक ईको सिस्टम का निर्माण करना है।
- रक्षा भारत स्टार्ट-अप चैलेंज (DISC) को सशस्त्र बलों और OFB/DPSU से समस्या वक्तव्यों (PS) के साथ नवप्रवर्तकों द्वारा समाधान के लिए लॉन्च किया गया है।

नवीन प्रौद्योगिकियों की खरीद के लिए अन्य चैनल:

- प्रौद्योगिकी विकास कोष योजना
- सेवाओं द्वारा स्वदेशी विकास

अन्य संबंधित पहलें:

- रक्षा ऑटोग्राफ गलियारा
- रक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
- सामरिक साझेदारी मॉडल

स्रोत: PIB

2021 NATO शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

- उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) का 2021 ब्रुसेल्स शिखर सम्मेलन 14 जून 2021 को बेल्जियम के ब्रुसेल्स में आयोजित, NATO के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों की 31 वीं औपचारिक बैठक थी।

नोट: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने अपने पहले व्यक्तिगत NATO शिखर सम्मेलन में भाग लिया।



Follow us on
Telegram



Gradeup
PCS & Other
State Exams



प्रमुख बिंदु

- NATO नेताओं ने 2021 ब्रसेल्स शिखर सम्मेलन में कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें NATO 2030 पहल के मुख्य विषय शामिल हैं: गठबंधन की एकता को कैसे मजबूत किया जाए, सुरक्षा के लिए अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाया जाए और नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की सुरक्षा में योगदान दिया जाए।

नोट: NATO नेताओं ने चीन को वैशिक सुरक्षा चुनौती घोषित किया।

NATO (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) के बारे में:

- NATO, जिसे उत्तरी अटलांटिक गठबंधन भी कहा जाता है, 30 यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों के बीच एक अंतर-सरकारी सैन्य गठबंधन है। संगठन उत्तरी अटलांटिक संधि को लागू करता है जिस पर 4 अप्रैल 1949 को हस्ताक्षर किए गए थे।

स्रोत: द हिंदू

भारतीय नौसेना - यूरोपीय संघ नौसैनिक बल (IN-EUNAVFOR) अभ्यास

चर्चा में क्यों?

- समुद्री डैकेती रोधी अभियानों के लिए तैनात भारतीय नौसेना का जहाज त्रिकंद 18 और 19 जून को एडन की खाड़ी में IN-EUNAVFOR संयुक्त नौसैनिक अभ्यास के लिए पहली बार भाग लिया।

प्रमुख बिंदु

- इस अभ्यास में चार नौसेनाओं (भारत, इटली, स्पेन और फ्रांस) के कुल पांच युद्धपोतों ने भाग लिया है।
- अभ्यास का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत बल के रूप में अपने युद्धकौशल और उनकी क्षमता को बढ़ाना और निखारना था।

महत्व:

- भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसैनिक बल विश्व खाद्य कार्यक्रम चार्टर (UN WFP) के तहत तैनात समुद्री डैकेती अभियानों और जहाजों की सुरक्षा सहित अनेक मुद्दों पर साथ काम करते हैं।
- भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसैनिक बल बहरीन में सालाना आयोजित SHADE (शेयर्ड अवेयरनेस एंड डी-कोन्फिलक्शन) बैठकों के माध्यम से नियमित बातचीत भी करते हैं।
- इसके साथ ही भारतीय नौसेना इन्फॉर्मेशन फ्यूज़न सेंटर-हिंद महासागर क्षेत्र और मेरीटाइम सिक्यूरिटी सेंटर- हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बीच एक आभासी ढंग से एक "सूचना साझा करने का अभ्यास" भी आयोजित किया गया था।

प्रमुख भारतीय समुद्री अभ्यास:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| • JIMEX: | जापान |
| • SLINEX: | श्रीलंका |
| • बोंगोसागर और IN-BN CORPAT: | बांग्लादेश |
| • नसीम-अल-बहर: | ओमान |
| • इंद्र: | रूस |
| • समुद्र शक्ति: | इंडोनेशिया |
| • ज़ेर-अल-बहर: | कतर |
| • इंडो-थाई CORPAT: | थाईलैंड |
| • IMCOR: | मलेशिया |
| • AUSINDEX: | ऑस्ट्रेलिया |

- मालाबार अभ्यास:
 - SIMBEX:
- जापान और अमेरिका
सिंगापुर

स्रोत: PIB

विज्ञान और तकनीक

कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस- “ऐम्बिटैग”

चर्चा में क्यों?

- पंजाब में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़ (IIT रोपड़) ने अपनी तरह की पहली अत्याधुनिक IoT डिवाइस- ऐम्बिटैग का विकास किया है, जो खराब होने वाले उत्पादों, वैक्सीन और यहां तक कि शरीर के अंगों व रक्त की ढुलाई के दौरान उनके आसपास का रियल टाइम तापमान दर्ज करती है।

प्रमुख बिंदु

“ऐम्बिटैग” के बारे में

- USB के आकार की डिवाइस, ऐम्बिटैग एक बार रिचार्ज होकर पूरे 90 दिन के लिए किसी भी टाइम जोन में -40 से +80 डिग्री तक के वातावरण में निरंतर तापमान दर्ज करती है।
- डिवाइस को प्रौद्योगिकी नवाचार हब – AWaDH (कृषि एवं जल तकनीकी विकास हब) और उसके स्टार्टअप स्क्रैचनेस्ट के तहत विकसित किया गया है।
- AWaDH भारत सरकार की एक परियोजना है।
- यह डिवाइस ISO 13485:2016, EN 12830:2018, CE और ROHS से प्रमाणित है।

नोट: ऐसी डिवाइसों को भारत में सिंगापुर, हॉन्गकॉन्ग, आयरलैंड और चीन जैसे दूसरे देशों से बड़ी मात्रा में आयात किया जा रहा है।

IFFCO ने "दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड" लॉन्च किया

चर्चा में क्यों?

- इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (IFFCO) ने पारंपरिक यूरिया के विकल्प के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने के लिए एक पोषक तत्व "दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड" लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

नैनो यूरिया के बारे में:

- फसलों के पोषक तत्वों की दक्षता में सुधार के लिए नैनो-प्रौद्योगिकी से उत्पादित यूरिया को नैनो यूरिया कहा जाता है।
- नैनो यूरिया लिक्विड को पारंपरिक यूरिया को बदलने के लिए विकसित किया गया है और यह इसकी आवश्यकता को कम से कम 50% तक कम कर सकता है।



Follow us on
Telegram



- परंपरागत यूरिया पौधों को नाइट्रोजन देने में 30-40 प्रतिशत प्रभावी है, जबकि नैनो यूरिया लिक्विड की प्रभावशीलता 80 प्रतिशत से अधिक है।

WHO ने भारत में पाए जाने वाले पहले COVID -19 वेरिएंट का नाम 'कप्पा' और 'डेल्टा' के रूप में दिया

चर्चा में क्यों?

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने घोषणा की कि भारत में पहली बार पहचाने गए COVID-19 के B.1.617.1 और B.1.617.2 वेरिएंट को क्रमशः 'कप्पा' और 'डेल्टा' नाम दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- वे मौजूदा वैज्ञानिक नामों को प्रतिस्थापित नहीं करेंगे, लेकिन उनका उद्देश्य वेरिएंट ऑफ कंसन्स (VOCs) एंड वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट (VOIs) की सार्वजनिक चर्चा में मदद करना है।

अन्य COVID-19 वेरिएंट:

- B.1.1.7 COVID-19 स्ट्रेन जिसका पहली बार UK में पता चला था, उसे 'अल्फा' के नाम से जाना जाएगा।
- अमेरिका में पाए गए COVID-19 स्ट्रेन 'एप्सिलॉन' और 'आईओटा' हैं।
- दक्षिण अफ्रीका में पाए गए B.1.351 वेरिएंट को अब 'बीटा' कहा जाता है।
- P.1 वेरिएंट जो सबसे पहले ब्राजील में पाया गया वह 'गामा' है और P.2 वेरिएंट 'जेटा' है।

NASA ने शुक्र (वीनस) के लिए 2 मिशनों की घोषणा की

चर्चा में क्यों?

- NASA (नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी) ने शुक्र की खोज के लिए 2 मिशन चुने हैं।

प्रमुख बिंदु

चयनित मिशन:

- DAVINCI+** (डीप एटमॉस्फियर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैस, केमिस्ट्री, और इमेजिंग): यह शुक्र के वायुमंडल की संरचना को मापने के लिए यह समझाने के लिए कि यह कैसे बना और विकसित हुआ, साथ ही यह निर्धारित करेगा कि क्या ग्रह पर कभी महासागर था।
- VERITAS** (वीनस एमिसिविटी, रेडियो साइंस, इनसार, टोपोग्राफी, और स्पेक्ट्रोस्कोपी): यह ग्रह के भूगर्भिक इतिहास को निर्धारित करने के लिए शुक्र की सतह को मैप करेगा और यह समझेगा कि यह पृथ्वी से इतना अलग क्यों विकसित हुआ।
- मिशन के 2028-2030 की समय सीमा में लॉन्च होने की उम्मीद है।

शुक्र के बारे में:

- शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है। इसका नाम प्रेम और सुंदरता की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है।
- शुक्र सौरमंडल के चार स्थलीय ग्रहों में से एक है, जिसका अर्थ है कि यह पृथ्वी की तरह एक चट्टानी पिंड है। यह आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान है, और इसे अक्सर पृथ्वी की "बहन" या "जुड़वां" के रूप में वर्णित किया जाता है।

नोट: भारत ने 2024 में शुक्रयान शुक्र मिशन लॉन्च करने के लिए योजना बनाई है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस



Follow us on
Telegram



IIT रोपड ने देश का पहला विद्युत मुक्त CPAP उपकरण 'जीवन वायु' विकसित किया

चर्चा में क्यों?

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड ने एक उपकरण 'जीवन वायु' विकसित किया है जिसे CPAP (कंटीन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर) मशीन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
- हालांकि, यह देश का पहला ऐसा उपकरण है जो बिना बिजली के भी काम करता है और अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर व ऑक्सीजन पाइपलाइन जैसी दोनों प्रकार की ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों के लिए अनुकूलित है।
- ये प्रावधान अन्य मौजूदा CPAP मशीनों में उपलब्ध नहीं हैं।

प्रमुख बिंदु

'जीवन वायु' के बारे में:

- इसमें एयर एंट्रेनमेंट छोर पर एक इनबिल्ट वायरल फिल्टर है, जिसकी वायरल प्रभावशीलता 99.99 फीसदी है।
- वायरल फिल्टर यह सुनिश्चित करता है कि हवा, वातावरण से बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु को नहीं लाती है।
- इस उपकरण को 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके बनाया गया है और इसका यांत्रिक परीक्षण भी किया गया है।

'जीवन वायु' की आवश्यकता:

- वर्तमान COVID महामारी के दौरान यह मशीन समय की जरूरत थी जब वैटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसे चिकित्सा उपकरणों के सहारे लोगों के जीवन को बचाने के लिए विद्युत की आपूर्ति प्रमुख चिंता का विषय है।

स्रोत: PIB

विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह न्यूजीलैंड से लांच होगा

चर्चा में क्यों?

- यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) ने विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह, वीसा वुडसैट (WISA Woodsat), पृथ्वी की कक्षा में लांच करने के लिए योजना बनाई है।

प्रमुख बिंदु

वीसा वुडसैट के बारे में:

- इसे न्यूजीलैंड के माहिया प्रायद्वीप प्रक्षेपण परिसर से रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट के साथ 2021 के अंत तक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा।
- मिशन उपग्रह अंतरिक्ष यान संरचनाओं में प्लाईवुड जैसी लकड़ी की सामग्री की प्रयोज्यता का परीक्षण करना है।
- फिनलैंड में डिजाइन और निर्मित उपग्रह, लगभग ध्रुवीय सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा में लगभग 500-600 किमी की ऊँचाई पर परिक्रमा करेगा।

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के बारे में:

- यह अंतरिक्ष की खोज के लिए समर्पित 22 सदस्य देशों का एक अंतर-सरकारी संगठन है।
- मुख्यालय:** पेरिस, फ्रांस



Follow us on
Telegram



- स्थापना: 30 मई 1975
- CEO: जोहान-डिट्रिच वोर्नर

स्रोत: द हिंदू

चीन ने अंतरिक्ष यान शेनझोउ-12 को लांच किया

चर्चा में क्यों?

- चीन ने तीन महीने के मिशन के लिए अपने अंतरिक्ष यान शेनझोउ-12 को तीन अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अपने अंतरिक्ष स्टेशन के कोर मॉड्यूल तियान्हे में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है।

प्रमुख बिंदु

- शेनझोउ-12 अंतरिक्ष यान को उत्तर पश्चिमी चीन के गोबी रेगिस्तान में जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया।
- यह अंतरिक्ष में चीन का सातवां क्रू मिशन है और चीन के अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के दौरान पहला है।
- यह 2016 में देश के अंतिम मानवयुक्त मिशन के बाद लगभग पांच वर्षों में पहला है।
- यह 2021 में नियोजित दो मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशनों में से पहला है।

चीन का अंतरिक्ष स्टेशन:

- चीन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भागीदार नहीं है।
- अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) एक मॉड्यूलर अंतरिक्ष स्टेशन (रहने योग्य कृत्रिम उपग्रह) लो अर्थ ऑर्बिट में है। यह एक बहुराष्ट्रीय सहयोगी परियोजना है जिसमें पांच भाग लेने वाली अंतरिक्ष एजेंसियां शामिल हैं: NASA (संयुक्त राज्य अमेरिका), Roscosmos (रूस), JAXA (जापान), ESA (यूरोप), और CSA (कनाडा)।

नोट: पूर्व सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद चीन तीसरा देश है जिसने अपने दम पर एक मानव मिशन को अंजाम दिया।

स्रोत: द हिंदू

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए बायोटेक-किसान कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) ने अपने मिशन कार्यक्रम "बायोटेक-कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क (बायोटेक-किसान)" के एक हिस्से के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) के लिए एक विशेष आहवान जारी किया है।
- बायोटेक किसान कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसानों की स्थानीय समस्याओं को समझा कर उनका वैज्ञानिक रूप से समाधान करना है।

प्रमुख बिंदु

बायोटेक-किसान के बारे में:

- यह कृषि नवाचार के लिए 2017 में शुरू की गई एक वैज्ञानिक-किसान साझेदारी योजना है, जिसका उद्देश्य खेतों के स्तर पर लागू किए जाने वाले नवीन समाधानों और प्रौद्योगिकियों का पता लगाने के लिए विज्ञान प्रयोगशालाओं को किसानों से जोड़ना है।



Follow us on
Telegram



- इस योजना के तहत, अब तक देश के सभी 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों और 110 आकांक्षी जिलों को कवर करते हुए 146 बायोटेक-किसान हब स्थापित किए जा चुके हैं।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) के बारे में:

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) कृषि, पशु विज्ञान, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण और उद्योग में इसके विकास और अनुप्रयोग के माध्यम से भारत में जैव प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ाने के साथ ही उसमें सुधार के लिए काम करता है।

वर्तमान आहवान के बारे में:

- वर्तमान आहवान विशेष रूप से देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर केंद्रित है क्योंकि यह क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि प्रधान है और कृषि कार्यों में इस क्षेत्र की 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि और संबद्ध क्षेत्र में आजीविका के लिए लगी हुई है।
- यह क्षेत्र देश के खाद्यान्न का केवल 1.5 प्रतिशत उत्पादन करता है और घरेलू खपत के लिए भी खाद्यान्न का शुद्ध आयातक बना हुआ है।

कृषि जैव प्रौद्योगिकी के बारे में:

- कृषि जैव प्रौद्योगिकी, जिसे एग्रीटेक के रूप में भी जाना जाता है, कृषि विज्ञान का एक क्षेत्र है जिसमें जीवित जीवों: पौधे, जानवर और सूक्ष्मजीव को संशोधित करने के लिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग, आणविक निदान, आणविक मार्कर, टीके और ऊतक संस्कृति सहित वैज्ञानिक उपकरणों और तकनीकों का उपयोग शामिल है।

स्रोत: PIB

पर्यावरण

जयंती: स्पाइडर क्रिकेट (झींगुर) की एक नई प्रजाति

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के प्राणी विज्ञान विभाग के डॉ रंजना जैसवारा के नेतृत्व में प्राणीविदों की एक टीम ने छत्तीसगढ़ की कुर्रा गुफाओं में स्पाइडर क्रिकेट की एक नई प्रजाति की खोज की है।
- देश के प्रमुख गुफा खोजकर्ताओं में से एक, प्रोफेसर जयंत बिस्वास के नाम पर नई उपजाति का नाम जयंती रखा गया।

प्रमुख बिंदु

न्यू स्पाइडर क्रिकेट के बारे में:

- जयंती, जीनस अरकोनोमिमस सॉस्योर, 1897 के तहत पहचाने गए क्रिकेट की बारहवीं उपजातियां या प्रजाति बन गई हैं।
- नए जयंती नर ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकते और उनकी मादाओं के कान नहीं होते।
- नए खोजे गए उपजाति, इंडिमिमस, पुरुष जननांग संरचना के कारण, दो उपजातियों, अरकोनोमिमस और यूराकनोमिमस से अलग हैं।
- कीड़ों में एक लॉक-एंड-की मॉडल जननांग संरचना होती है जो प्रत्येक उपजाति के लिये अद्वितीय होती है।

खोज का महत्व:

- नई प्रजातियां गुफा की दीवारों पर अपने पेट या शरीर के किसी अन्य अंग को पीटकर संचार कर सकती हैं।
- कंपन संचार सिग्नल ट्रांसमिशन के सबसे नरम लेकिन सबसे तेज़ तरीकों में से एक है।
- कंपन संचार के उनके कौशल पर आगे के अध्ययन से मनुष्यों के लिए श्रवण यंत्रों को डिजाइन करने में मदद मिल सकती है जो सबसे शांत संकेतों को पकड़ सकते हैं और एक श्रव्य श्रवण सीमा तक बढ़ा सकते हैं।
- जयंती की खोज के बाद अरकोनोमिमस जाति अब कुल 12 प्रजातियों के नाम से जाना जाएगी। इन प्रजातियों का वितरण (ब्राजील से लेकर मलेशिया तक) बहुत व्यापक है।
- भारत में स्पाइडर क्रिकेट की विविधता अभी भी अस्पष्ट है। यह देखते हुए कि भारत में चार जैव विविधता हॉटस्पॉट और सभी हॉटस्पॉट में खाली गुफाएँ होने के कारण यहाँ कई और महत्वपूर्ण खोजों की गुंजाइश है।

रायमोना असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान बना

चर्चा में क्यों?

- कोकराझार जिले में रायमोना असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है।
- कोकराझार जिले में 422 वर्ग फुट का वन्यजीव निवास स्थान मानस टाइगर रिजर्व के सबसे पश्चिमी बफर से जुड़ा हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- कोकराझार जिले में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (BTR) के तहत रायमोना आरक्षित वन, भूटान की सीमा से लगा, को राज्य के छठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में उन्नयन किया गया है।



Follow us on
Telegram



Gradeup
PCS & Other
State Exams



- यह सुनहरे लंगूर, एशियाई हाथियों, बाघों, बादल वाले तेंदुए, भारतीय गौर, जंगली भैंस, चित्तीदार हिरण, हॉर्नबिल, तितलियों की 150 से अधिक प्रजातियों, पक्षियों की 170 प्रजातियों और पौधों और ऑर्किड की 380 किस्मों का घर है।

नोट:

- राज्य के अन्य पांच राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू-सैखोवा हैं।
- भारत में राष्ट्रीय उद्यान IUCN श्रेणी II संरक्षित क्षेत्र हैं।
- भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे अब जिम कॉर्बट नेशनल पार्क, उत्तराखण्ड के नाम से जाना जाता है।
- 1972 में, भारत ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को संरक्षण निर्भर प्रजातियों के आवासों की सुरक्षा के लिए अधिनियमित किया।

स्रोत: द हिंदू

'देहिंग पटकाई' असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान

चर्चा में क्यों?

- असम के देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया।
- पश्चिमी असम के कोकराझार ज़िले में रायमोना आरक्षित वन को 5 जून, 2021 को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने के तुरंत बाद यह घोषणा हुई।

प्रमुख बिंदु

देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान के बारे में:

- 111.942 वर्ग किमी देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य (2004 में अधिसूचित) बड़े देहिंग पटकाई हाथी रिजर्व के अंदर स्थित है, जो ऊपरी असम के डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और शिवसागर ज़िलों में फैला हुआ है - जो कोयले और तेल से भरपूर है।
- यह क्षेत्र हूलॉक गिब्बन, हाथी, स्लो लॉरिस, बाघ, क्लाउडेड तेंदुआ, सुनहरी बिल्ली, फिशिंग कैट, मार्बल कैट, सांभर, हॉग डियर, स्लॉथ बियर, तथा लुप्तप्राय राज्य पक्षी सफेद पंख वाली बत्तख सहित कई पक्षी प्रजातियों का घर है।

असम में राष्ट्रीय उद्यान:

- असम के सात राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा, नामेरी, ओरंग, मानस, डिब्रू-सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकाई हैं।
- असम अब मध्य प्रदेश के 11 के बाद देश में दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या वाला राज्य है।
- केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार में नौ राष्ट्रीय उद्यान हैं।

नोट: काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान UNESCO की विश्व धरोहर स्थल हैं।

स्रोत: PIB

संयुक्त राष्ट्र की 'मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे पर उच्च स्तरीय संवाद'

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की 'मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे पर उच्च स्तरीय संवाद' में अपना मुख्य संबोधन दिया।



Follow us on
Telegram



- उन्होंने मरुस्थलीकरण से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCCD) के सभी पक्षों के 14वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में प्रारंभिक सत्र को संबोधित किया।

प्रमुख बिंदु

भूमि क्षरण के मुद्दे से निपटने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम:

- भारत भूमि क्षरण तटस्थता (सतत विकास लक्ष्य लक्ष्य 15.3) की अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को प्राप्त करने की राह पर है।
- 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक प्राप्त करने के लिए 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को पूर्व अवस्था में ले जाने का लक्ष्य है।
- पिछले 10 वर्षों में, भारत में करीब 3 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाया गया, जिससे संयुक्त वन क्षेत्र बढ़कर देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग एक चौथाई हो गया है।
- प्रधानमंत्री ने गुजरात के कच्छ के रण में बन्नी क्षेत्र का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया कि कैसे भूमि की बहाली से मिट्टी के अच्छे स्वास्थ्य, भूमि की उत्पादकता में वृद्धि, खाद्य सुरक्षा और बेहतर आजीविका का एक अच्छा चक्र शुरू हो सकता है।
- भूमि क्षरण के मुद्दों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए भारत में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है।

भूमि क्षरण के बारे में:

- भूमि क्षरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भूमि पर कार्य करने वाली मानव-प्रेरित प्रक्रियाओं के संयोजन से जैव-भौतिक पर्यावरण का मूल्य प्रभावित होता है।
- भूमि क्षरण कई ताकतों के कारण होता है, जिसमें चरम मौसम की स्थिति, विशेष रूप से सूखा शामिल है।

परिणाम

भूमि निम्नीकरण और उसके आसपास के पर्यावरण पर उसके प्रभाव को देखने के चार मुख्य तरीके हैं:

- भूमि की उत्पादक क्षमता में अस्थायी या स्थायी गिरावट
- मानव आजीविका के लिए संसाधन उपलब्ध कराने के लिए भूमि की क्षमता में कार्रवाई
- जैव विविधता का नुकसान
- पारिस्थितिक जोखिम को स्थानांतरित

भूमि क्षरण की जांच के लिए वैशिक प्रयास:

- यूनाइटेड नेशंस कन्वेशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन (UNCCD)
- UNCCD के 14वें CoP द्वारा हस्ताक्षरित 2019 की दिल्ली घोषणापत्र में भूमि पर बेहतर पहुंच और प्रबंधन का आहवान किया गया।
- बॉन चैलेंज
- ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव
- सूखे की पहल
- भूमि क्षरण तटस्थता कार्यक्रम

भूमि क्षरण को रोकने के लिए भारत के प्रयास:

- द नेशनल एक्शन प्रोग्राम फॉर कोम्बटिंग डेजर्टिफिकेशन इन 2001
- एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना)
- हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन



Follow us on
Telegram



- राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
- नदी घाटी परियोजना के जलग्रहण क्षेत्र में मृदा संरक्षण

कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम

स्रोत: PIB

योजनायें

युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा (YUVA) - प्रधानमंत्री योजना

चर्चा में क्यों?

- शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा (YUVA) - प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

युवा -YUVA (युवा, आगामी और बहुमुखी लेखक) योजना के बारे में:

- यह युवा और नवोदित लेखकों (30 वर्ष से कम आयु) को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है, जिससे पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके व वैशिक स्तर पर भारत और भारतीय लेखन को प्रदर्शित किया सके।
- **युवा, भारत@75 परियोजना** (आजादी का अमृत महोत्सव) का एक हिस्सा है। यह योजना विस्मृत नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों, अज्ञात और भूले हुए स्थानों और राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका और अन्य विषय वस्तुओं पर लेखकों की युवा पीढ़ी के वृष्टिकोण को एक अभिनव व रचनात्मक तरीके से सामने लाने के लिए है।

कार्यान्वयन और निष्पादन:

- शिक्षा मंत्रालय के तहत नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत योजना की कार्यान्वयन एजेंसी होगी।
- इस योजना के तहत तैयार की गई पुस्तकों का प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत करेगा।
- 1 जून से 31 जुलाई, 2021 तक आयोजित होने वाली अखिल भारतीय प्रतियोगिता के जरिए कुल 75 लेखकों का चयन किया जाएगा।
- विजेताओं की घोषणा 15 अगस्त, 2021 को की जाएगी।
- युवा लेखकों को प्रख्यात लेखक/संरक्षक प्रशिक्षित करेंगे।
- संरक्षण के तहत, पांडुलिपियों को प्रकाशन के लिए 15 दिसंबर, 2021 तक पढ़ा जाएगा।
- प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन 12 जनवरी, 2022 को राष्ट्रीय युवा दिवस (युवा दिवस) के अवसर पर किया जाएगा।
- संरक्षण योजना के तहत छह महीने की अवधि के लिए प्रत्येक लेखक को 50,000 रुपये प्रति माह की समेकित छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा।

MDM योजना के तहत DBT के माध्यम से मौद्रिक सहायता

चर्चा में क्यों?



- शिक्षा मंत्रालय ने एक विशेष कल्याण उपाय के तौर पर मध्याहन-भोजन (MDM) योजना के सभी पात्र बच्चों के लिए खाना पकाने की लागत घटक के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से मौद्रिक सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- यह निर्णय बच्चों के पोषण स्तर को सुरक्षित रखने में मदद करेगा और इस चुनौतीपूर्ण महामारी के समय में उनकी प्रतिरक्षा को बनाए रखने में मदद करेगा।
- यह भारत सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) के तहत लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम की दर से निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की घोषणा के अतिरिक्त है।
- केंद्र सरकार इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को लगभग 1200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रदान करेगी।
- केंद्र सरकार के इस एक बार के विशेष कल्याणकारी उपाय से देश भर के 11.20 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले लगभग 11.8 करोड़ बच्चे लाभान्वित होंगे।

मध्याहन भोजन योजना (MDM) के बारे में:

- यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसको **1995** में शुरू किया गया था।
- मध्याहन भोजन योजना भारत में एक स्कूली भोजन कार्यक्रम है जिसे देश भर में स्कूली उम्र के बच्चों की पोषण स्थिति को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह कार्यक्रम सरकारी सहायता प्राप्त, स्थानीय निकाय, शिक्षा गारंटी योजना, और सर्व शिक्षा अभियान के तहत समर्थित मदरसा और मकतब, और श्रम मंत्रालय द्वारा संचालित, सरकारी राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कूलों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के बच्चों के लिए कार्य दिवसों पर मुफ्त लंच की आपूर्ति करता है।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT):

- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण **1 जनवरी 2013** को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सब्सिडी के हस्तांतरण के तंत्र को बदलने का एक प्रयास है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को सीधे उनके बैंक खातों के माध्यम से सब्सिडी हस्तांतरित करना है।

DBT से जुड़ी अन्य योजनाएं:

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, PM KISAN (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना), स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, राष्ट्रीय आयुष मिशन, अटल पैशन योजना।

'PM-केयर्स फॉर चिल्ड्रन' योजना

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COVID19 के कारण अनाथ बच्चों के लिए 'PM-केयर्स फॉर चिल्ड्रन' योजना की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

- COVID19 के कारण माता-पिता दोनों या माता-पिता में से जीवित बचे या कानूनी अभिभावक/दत्तक माता-पिता को खोने वाले सभी बच्चों को 'PM-केयर्स फॉर चिल्ड्रन' योजना के तहत सहायता दी जाएगी।



Follow us on
Telegram



'PM-केयर्स फॉर चिल्डन' योजना के बारे में:

- ऐसे बच्चों को 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर मासिक वित्तीय सहायता और 23 वर्ष की आयु पूरी करने पर PM केयर्स से 10 लाख रुपये की राशि मिलेगी
- COVID 19 के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी
- ऐसे बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण दिलाने में सहायता की जाएगी और PM केयर्स उस ऋण पर लगने वाले ब्याज का भुगतान करेगा
- ऐसे बच्चों को आयुष्मान भारत योजना (PM-JAY) के तहत 18 वर्ष की आयु तक 5 लाख रुपये का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा और प्रीमियम का भुगतान PM केयर्स द्वारा किया जाएगा

PM केयर्स फंड के बारे में:

- COVID-19 महामारी जैसी किसी भी तरह की आपातकालीन या संकट की स्थिति से निपटने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक समर्पित राष्ट्रीय निधि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और उससे प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए 'आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (PM केयर्स फंड)' के नाम से एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया गया है।
- प्रधानमंत्री, PM CARES कोष के पदेन अध्यक्ष और भारत सरकार के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, निधि के पदेन ट्रस्टी होते हैं।
- PM-केयर्स फंड में दान दी गई रकम पर इनकम टैक्स से 100 फीसदी छूट मिलेगी। यह राहत इनकम टैक्स कानून के सेक्षण 80G के तहत मिलेगी।
- PM-केयर्स फंड में दान भी कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) व्यय के रूप में गिना जाएगा।
- PM केयर्स फंड को भी FCRA के तहत छूट मिली है और विदेशों से दान प्राप्त करने के लिए एक अलग खाता खोला गया है।

केरल की स्मार्ट किचन योजना

चर्चा में क्यों?

- केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने घोषणा की है कि सचिव स्तर की समिति 10 जुलाई, 2021 तक 'स्मार्ट किचन योजना' के कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें और दिशानिर्देश तैयार करने के लिए तैयार हैं।

प्रमुख बिंदु

स्मार्ट किचन योजना के बारे में:

- इसका उद्देश्य महिलाओं के घरेलू श्रम के काम के बोझ को कम करना है।
- महिलाओं को किंशत योजनाओं में कम ब्याज दर के साथ उनकी रसोई के नवीनीकरण के लिए सरकार द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा।

NHA के IT प्लेटफॉर्म पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं के डिजिटल संस्करण

चर्चा में क्यों?

- केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के IT फ्लेटफार्म पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) और राष्ट्रीय आरोग्य निधि (RAN) की कई योजनाओं और स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान (HMDG) को लॉन्च किया।



*Follow us on
Telegram*



Gradeup
PCS & Other
State Exams



प्रमुख बिंदु

- यह कदम पूरी प्रक्रिया को पेपरलैस बनाकर इन योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की निर्बाध पहुंच को सक्षम बनाएगा।
- अब सभी योजनाएं कैशलेस, पेपरलेस और नागरिक केंद्रित हो गई हैं।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) के बारे में:

- CGHS, जोकि सेवारत कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों आदि और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य योजना है, को पिछले सात सालों के दौरान 72 शहरों में विस्तार देकर इसमें 38 लाख से अधिक लाभार्थियों को शामिल किया है।

राष्ट्रीय आरोग्य निधि (RAN) के बारे में:

- इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले और गंभीर जानलेवा बीमारियों से पीड़ित रोगियों को किसी भी सुपर स्पेशियलिटी सरकारी अस्पताल / संस्थान में चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए 15 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान (HMDG) के बारे में:

- HMDG के तहत उन मरीजों को 1,25,000 रुपये की अधिकतम राशि प्रदान की जाती है, जिनकी वार्षिक आमदनी 1,25,000 रुपये से अधिक नहीं हैं ताकि सरकारी अस्पताल में भर्ती होने/इलाज पर होने वाले खर्च के एक हिस्से का भुगतान कर सके।

स्रोत: PIB

PMAY-U के तहत करीब 3.61 लाख आवासों के निर्माण के प्रस्तावों को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने प्रधानमंत्री आवास योजना -शहरी (PMAY-U) के तहत करीब 3.61 लाख आवासों के निर्माण के 708 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी।
- इस संबंध में फैसला नई दिल्ली में PMAY-U के तहत केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 54वीं बैठक में लिया गया।
- इसके अलावा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 'PMAY-U अवार्ड्स 2021 - 100 डेज चैलेंज' भी लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

'PMAY-U अवार्ड्स 2021 - 100 डेज चैलेंज' के बारे में:

- इसके तहत, मिशन के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों (UT), शहरी स्थानीय निकायों (ULB) और लाभार्थियों द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान और प्रदर्शन को पहचानने और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं।
- उल्लेखनीय है कि आज की तिथि तक, PMAY-U के तहत स्वीकृत घरों की कुल संख्या 112.4 लाख है जिनमें से अब तक 82.5 लाख घरों के निर्माण के लिए आधार तैयार किए जा चुके हैं और इनमें से भी 48.31 लाख पूरे/ वितरित किए जा चुके हैं।
- इसके लिए कुल निवेश 7.35 लाख करोड़ रुपये तय है जिसमें 1.81 लाख रुपये की राशि केंद्रीय सहायता के तौर पर दी जानी है। इस राशि में से 96,067 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

छह लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स (LHPs) के बारे में:

- LHPs की आधारशिला जनवरी, 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी।
- LHP का निर्माण अगरतला, चेन्नई, लखनऊ, रांची, राजकोट और इंदौर में किया जा रहा है।
- इस कार्यक्रम में टेक्नोग्राही पर एक ई-मॉड्यूल भी लॉन्च किया गया, जिसमें ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज-इंडिया के तहत चुनी गई अभिनव निर्माण प्रौद्योगिकियों को सीखने के उपकरण शामिल हैं और जिनका छह LHP में इस्तेमाल किया जा रहा है।
- मंत्रालय के सचिव ने हरियाणा के पंचकुला में एक नवनिर्मित प्रदर्शन आवास परियोजना का भी उद्घाटन किया, जिसका उपयोग किराए पर, एक कामकाजी महिला छात्रावास के रूप में किया जाएगा।
- PMAY-U के प्रौद्योगिकी उप मिशन के तहत, अब तक 6 प्रदर्शन आवास परियोजनाएं (DHP) पूरी की जा चुकी हैं और देश के विभिन्न हिस्सों में 7 अन्य का निर्माण किया जा रहा है।

प्रदर्शन आवास परियोजनाओं (DHP) के बारे में:

- DHP नई/वैकल्पिक तकनीक के साथ निर्मित मॉडल हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जिसका उपयोग न सिर्फ प्रौद्योगिकी के क्षेत्रीय स्तर के अनुप्रयोग को प्रदर्शित करता है बल्कि जिसका उपयोग ऐसी तकनीक के अनुप्रयोग और उपयोग पर आवास क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों और छात्रों को साइट पर अनुकूलन और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मंच के रूप में भी किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के बारे में:

- यह भारत सरकार की एक पहल है जिसमें 31 मार्च 2022 तक 2 करोड़ (20 मिलियन) किफायती घर बनाने के लक्ष्य के साथ शहरी गरीबों को किफायती आवास प्रदान किया जाएगा।
- इसके दो घटक हैं: शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (PMAY-U) और ग्रामीण गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (PMAY-G)।

स्रोत: PIB

"मिशन कर्मयोगी" के लिए विशेष प्रयोजन वाहन (SPV)

चर्चा में क्यों?

- पूर्व इनफोसिस के CEO (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) एस डी शिवू लाल को एक 3 सदस्यीय कार्यबल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
- कार्यबल महत्वाकांक्षी "मिशन कर्मयोगी" के माध्यम से प्रमुख नौकरशाही सुधारों को लाने में सरकार की मदद करेगा
- अन्य सदस्यों में गोविंद अच्यर और पंकज बंसल हैं।

प्रमुख बिंदु

- केंद्र ने हाल ही में देश में सभी सिविल सेवाओं की भूमिका-आधारित क्षमता विकास के लिए नियम आधारित प्रशिक्षण से परिवर्तनकारी बदलाव को प्रभावित करने के लिए 'सिविल सेवा क्षमता निर्माण' के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम - मिशन कर्मयोगी' को मंजूरी दी है।
- इस मिशन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV), अर्थात् कर्मयोगी भारत, को एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में स्थापित किया जाएगा।
- इसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत 100% सरकारी स्वामित्व वाली इकाई के रूप में स्थापित किया जाएगा।

- विशेष प्रयोजन वाहन डिजिटल प्लेटफॉर्म और बुनियादी ढांचे को डिजाइन करने, लागू करने, बढ़ाने और प्रबंधित करने, योग्यता मूल्यांकन सेवाओं का प्रबंधन और वितरण करने और टेलीमेट्री डेटा के शासन का प्रबंधन करने और निगरानी और मूल्यांकन के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- टास्क फोर्स अपने विज़न, मिशन और कार्यों को संरेखित करते हुए SPV की संगठनात्मक संरचना पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

'मिशन कर्मयोगी' के बारे में:

सिविल सेवा क्षमता निर्माण के माध्यम से शासन को बढ़ाने के उद्देश्य से सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCSCB) - "मिशन कर्मयोगी" शुरू किया गया है।

मिशन कर्मयोगी में निम्नलिखित छह स्तंभ होंगे:

- नीति ढांचा
- योग्यता ढांचा
- संस्थागत ढांचा
- डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क (इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी प्लेटफॉर्म (iGOT-कर्मयोगी))
- निगरानी और मूल्यांकन ढांचा।
- इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (e-HRMS)

स्रोत: NDTV

पुरस्कार और सम्मान

नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य कुमार सेन को स्पेन का प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया

चर्चा में क्यों?

- भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य कुमार सेन को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन का प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- अमर्त्य सेन को अकाल पर उनके शोध और मानव विकास के उनके सिद्धांत, कल्याण अर्थशास्त्र और गरीबी के अंतर्निहित तंत्र ने अन्याय, असमानता, बीमारी और अज्ञानता के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया।
- इस पुरस्कार में 50,000 यूरो का नकद पुरस्कार, सहित जोआन मिरो की प्रतिमा, एक डिप्लोमा और प्रतीक चिन्ह शामिल है।

नोट:

- अमर्त्य सेन ने 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता।
- उन्हें 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।

गोपाल रत्न पुरस्कारों का शुभारंभ और उमंग प्लेटफॉर्म के साथ ई-गोपाल ऐप का एकीकरणचर्चा में क्यों?

- मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने विश्व दुर्घट दिवस के अवसर पर गोपाल रत्न पुरस्कारों के शुभारंभ और उमंग प्लेटफॉर्म के साथ ई-गोपाल ऐप के एकीकरण की घोषणा की।
- हर साल पहली जून को विश्व दुर्घट दिवस के रूप में मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु

गोपाल रत्न पुरस्कार के बारे में:

- गोपाल रत्न पुरस्कार मवेशी और डेयरी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हैं।
- पुरस्कार की तीन श्रेणियां हैं - i) सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, ii) सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (AIT) और (iii) सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी/दुर्घट उत्पादक कंपनी/FPO।

उमंग (UMANG) प्लेटफॉर्म के बारे में:

- यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (UMANG), एक मोबाइल ऐप है, जो केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं तक पहुंच के लिए भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक डिजिटल इंडिया पहल है।
- ऐप को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन के साथ विकसित किया गया था और नवंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था।

ई-गोपाल ऐप के बारे में:

- ई-गोपाल ऐप (उत्पादक पशुधन के माध्यम से धन का सृजन), एक व्यापक नस्ल सुधार बाजार और किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए सूचना पोर्टल, को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2020 में लॉन्च किया गया था।

डेयरी क्षेत्र से जुड़ी अन्य पहल:



Follow us on
Telegram



- राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम
- डेयरी विकास पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2022
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन
- पाशु-आधार

ऑपरेशन फ्लड (श्वेत क्रांति) के बारे में:

- ऑपरेशन फ्लड, 13 जनवरी 1970 को शुरू किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम और भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) की एक ऐतिहासिक परियोजना।
- ऑपरेशन फ्लड वह कार्यक्रम है जिसके कारण "श्वेत क्रांति" हुई।
- वर्गीज कुरियन को भारत में "श्वेत क्रांति के जनक" के रूप में जाना जाता है।

नोट: भारत डेयरी देशों में एक वैश्विक लीडर है और 2019-20 के दौरान 198.4 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया। वर्तमान में, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, जिसका वैश्विक उत्पादन 22% है।

WHO ने हर्षवर्धन को 'WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार' से सम्मानित किया

चर्चा में क्यों?

- विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्ष वर्धन को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए 'WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार' से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- श्री वर्धन को ई-सिगरेट और गर्म तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के लिए पुरस्कार दिया गया।
- उनके नेतृत्व ने ई-सिगरेट और गर्म तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के लिए 2019 के राष्ट्रीय कानून में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- WHO ने मध्य प्रदेश स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ और उत्तर प्रदेश तंबाकू नियंत्रण कक्ष को दक्षिण पूर्व क्षेत्र श्रेणी में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार से भी सम्मानित किया है।

नोट: विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 31 मई 2021 को मनाया गया।

असम भारत रत्न, पद्म पुरस्कार की तर्ज पर नागरिक सम्मान प्रदान करेगा

चर्चा में क्यों?

- असम सरकार ने राज्य में प्रतिष्ठित व्यक्तियों और प्राप्तकर्ताओं के लिए नकद पुरस्कार और कई अन्य लाभ प्रदान करते हुए भारत रत्न और पद्म वार्षिक पुरस्कारों की तर्ज पर राज्य पुरस्कारों की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

नए घोषित पुरस्कारों के बारे में:

- असम ने एक असम रत्न, तीन असम विभूषण, पांच असम भूषण और दस असम श्री पुरस्कार हर साल देने की घोषणा की।
- पुरस्कारों में क्रमशः ₹ 5 लाख, ₹ 3 लाख, ₹ 2 लाख और ₹ 1 लाख नकद दिए जाएंगे।
- पुरस्कारों में गंभीर बीमारी का मुफ्त चिकित्सा उपचार, असम भवनों में मुफ्त प्रवास, ASTC बसों में मुफ्त यात्रा आदि जैसे लाभ भी शामिल होंगे।

स्रोत: NDTV



Follow us on
Telegram



अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021: डेविड डियोप पहले फ्रांसीसी विजेता बने

चर्चा में क्यों?

- फ्रांसीसी उपन्यासकार डेविड डियोप ने 'एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक' के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 जीता।

प्रमुख बिंदु

- पुस्तक का अनुवाद अन्ना मोस्कोवाकिस ने किया था।
- विजेता पुस्तक पहली बार 2018 में फ्रांसीसी शीर्षक 'फ्रेरे डी' एमे' के साथ प्रकाशित हुई थी।
- इसे पुश्किन प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में

- अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिसे पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में जाना जाता था, 2005 से प्रदान किया जाता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

2021 पुलित्जर पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

- पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड द्वारा 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों को 2020 कैलेंडर वर्ष के दौरान 11 जून, 2021 को काम के लिए प्रदान किया गया।
- पत्रकारिता, किताबें, नाटक और संगीत में 2021 के पुलित्जर पुरस्कार विजेताओं की 105 वीं क्लास की घोषणा की गई।

प्रमुख बिंदु

- पुरस्कारों ने उस वर्ष अमेरिका में COVID-19 महामारी, नस्लीय अशांति और अन्य प्रमुख कहानियों के कवरेज पर प्रकाश डाला।
- द अटलांटिक और बज़फ़िड न्यूज सहित कई प्रकाशनों ने अपना पहला पुलित्जर प्राप्त किया।
- बज़फ़िड न्यूज से भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन ने मुसलमानों को हिरासत में लेने के लिए चीन के विशाल बुनियादी ढांचे को उजागर करने के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता।

मुख्य 2021 पुलित्जर पुरस्कार विजेता:

श्रेणी	विजेता
पत्रकारिता	
लोक सेवा	द न्यू यॉर्क टाइम्स
ब्रेकिंग रिपोर्टिंग	न्यूज स्टाफ ऑफ द स्टार ट्रिब्यून, मिनियापोलिस, मिन

ਖੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ	ਮੈਟ ਰੋਸੇਲੂ, ਵਰਨਲ ਕੋਲਮੈਨ, ਲੌਰਾ ਕ੍ਰਿਮਾਲਡੀ, ਇਵਾਨ ਏਲਨ ਔਰ ਬ੍ਰੇਂਡਨ ਮੈਕਾਰਥੀ ਆਂਫ ਦ ਬੋਸ਼ਟਨ ਗਲੋਬ
ਏਕਸਾਲੋਨੇਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ	ਏਂਡ੍ਰ੍ਯੂ ਚੁੰਗ, ਲਾਰੋਸ ਹਲੰਕ, ਏਂਡ੍ਰਿਆ ਜਨੁਤਾ, ਜੈਮੀ ਡੋਡੇਲ ਔਰ ਜੈਕੀ ਬੱਟਸ ਸਟਾਫ ਆਂਫ ਰੱਧਟਸ
ਲੋਕਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ	ਕੈਥਲੀਨ ਮੈਕਗ੍ਰੋਰੀ ਔਰ ਨੀਲ ਬੇਦੀ ਆਂਫ ਟੈਮਪਾ ਬੇ ਟਾਇਮਸ
ਨੇਸ਼ਨਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ	ਸਟਾਫ ਆਂਫ ਦ ਮਾਰਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਜੋਕਟ; AL.com, ਬਰਮਿੰਘਮ; ਇੰਡੀਸਟਾਰ, ਇੰਡਿਆਨਾਪੋਲਿਸ; ਔਰ ਇਨਵਿਜਿਬਲ ਇੰਸਟੀਟਯੂਟ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ
ਇੰਟਰਨੇਸ਼ਨਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ	ਮੇਘਾ ਰਾਜਗੋਪਾਲਨ, ਏਲਿਸਨ ਕਿਲਿੰਗ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋ ਬੁਸ਼ਚੇਕ ਆਂਫ ਬੱਜਾਫਿਡ ਨ੍ਯੂਜ
ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ	ਵੇਸਲੇ ਮੋਰਿਸ ਆਂਫ ਦ ਨ੍ਯੂਯਾਰਕ ਟਾਇਮਸ
ਸੰਪਾਦਕੀਯ ਲੇਖਨ	ਰੱਬਾਟ ਗੀਨ ਆਂਫ ਲੋਸ ਏਂਜਿਲਸ ਟਾਇਮਸ
ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨ੍ਯੂਜ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ	ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਟਾਫ ਆਂਫ ਏਸੋਸਿਏਟੇਡ ਪ੍ਰੇਸ
ਬੁਕਸ, ਡਾਮਾ ਔਰ ਮ੍ਯੂਜਿਕ	
ਫਿਕ਼ਸ਼ਨ	ਲੁਈਸ ਏਂਡ੍ਰਿੱਚ ਦਵਾਰਾ ਦ ਨਾਇਟ ਵੱਚਮੈਨ
ਡਾਮਾ	ਕਟੋਰੀ ਹੱਲ ਦਵਾਰਾ ਦ ਹੱਟ ਵਿੰਗ ਕਿੰਗ
ਹਿਸਟੀ	ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼: ਦ ਗੋਲਡਨ ਆਰਚਸ ਇਨ ਬਲੈਕ ਅਮੇਰਿਕਾ ਦਵਾਰਾ ਮਾਰਿਂਗ ਚੇਟੇਲੇਨ

पोएट्री	नताली डियाज़ द्वारा पोस्टकोलोनियल लव पोएम
विशेष उद्धरण	डार्नला फ्रैज़ियर, वह किशोरी जिसने जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या को रिकॉर्ड किया था
संगीत	तानिया लियोन द्वारा स्ट्राइड

स्रोत: Pulitzer.org

संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021

चर्चा में क्यों?

- राजस्थान के जलवायु कार्यकर्ता श्याम सुंदर ज्याणी के पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा, पारिवारिक वानिकी (Familial Forestry) ने संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 जीता है।

प्रमुख बिंदु

- समाजशास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर श्याम सुंदर ज्याणी 15 वर्षों से अधिक समय से पारिवारिक वानिकी के लिए अभियान चला रहे हैं।

पुरस्कार के बारे में:

- UNCCD COP (पार्टियों का सम्मेलन) 10, 2011 में मैं शुरू किया गया, इस पुरस्कार को भूमि संरक्षण और बहाली के संबंध में दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है।
- इसने सतत विकास लक्ष्य (SDG) 15: "भूमि पर जीवन", विशेष रूप से लक्ष्य 15.3 भूमि क्षरण तटस्थिता (LDN) को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

पारिवारिक वानिकी के बारे में:

- पारिवारिक वानिकी का अर्थ है पेड़ों और पर्यावरण की देखभाल को स्थानांतरित करना ताकि एक पेड़ परिवार की चेतना का हिस्सा बन जाए।
- पिछले 15 वर्षों में 25 लाख से अधिक पौधे मरुस्थल-प्रवण उत्तर-पश्चिम राजस्थान के 15,000 से अधिक गांवों के दस लाख से अधिक परिवारों ने लगाए हैं।

मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCCD) के बारे में:

- UNCCD की स्थापना 1994 में हुई थी। यह पर्यावरण और विकास को संयुक्त राष्ट्र के तहत स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।
- UNCCD तीन रियो सम्मेलनों में से एक है; अन्य दो जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCBD) और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) हैं।

स्रोत: द हिंदू

पूर्व केरल स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा CEU ओपन सोसायटी पुरस्कार 2021 से सम्मानित

चर्चा में क्यों?



- पूर्व स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा को प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी (CEU) ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

पुरस्कार के बारे में:

- ओपन सोसाइटी पुरस्कार, विश्वविद्यालय द्वारा सर्वोच्च नागरिक मान्यता, प्रतिवर्ष असाधारण विशिष्ट व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो एक ओपन सोसाइटी के आदर्शों की सेवा करते हैं।

नोट: नोबेल पुरस्कार विजेता स्वेतलाना एलेक्सीविच ने 2020 में ओपन सोसाइटी पुरस्कार प्राप्त किया था।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारतीय-अमेरिकी सुमिता मित्रा ने यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 जीता

चर्चा में क्यों?

- भारतीय-अमेरिकी रसायनज्ञ सुमिता मित्रा ने 'गैर-EPO' देशों की श्रेणी में यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 जीता है।

प्रमुख बिंदु

- सुमिता मित्रा को दंत चिकित्सा में नैनो तकनीक के उनके अनुप्रयोग के लिए यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया।
- मित्रा ने पहली बार नैनो तकनीक को दंत सामग्री में सफलतापूर्वक एकीकृत करने के लिए मजबूत और अधिक सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन फिलिंग का उत्पादन किया, जो अब दुनिया भर के दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाता है।

पुरस्कार के बारे में:

- पुरस्कार, यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित नवाचार पुरस्कारों में से एक, EPO (यूरोपीय पेटेंट कार्यालय) द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है ताकि यूरोप और उससे बाहर के उत्कृष्ट आविष्कारकों को पहचाना जा सके जिन्होंने समाज, तकनीकी प्रगति और आर्थिक विकास में असाधारण योगदान दिया है।

स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स

जमशेदजी एन टाटा पिछली सदी के दुनिया के शीर्ष परोपकारी बने

चर्चा में क्यों?

- हुरुन रिसर्च एंड एडेलगिव फाउंडेशन द्वारा संकलित 50 वैश्विक दानदाताओं की सूची के अनुसार, भारत के अग्रणी उद्योगपति और टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी एन टाटा पिछली सदी के दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति हैं।
- कुल वैश्विक दान पिछली सदी में 832 बिलियन डॉलर था।
- हुरुन रिसर्च एंड एडेलगिव फाउंडेशन ने 2021 एडेलगिव हुरुन फिलेंथ्रोपिस्ट्स ऑफ द सेंचुरी रिपोर्ट जारी की, जो पिछली सदी के दुनिया के सबसे उदार व्यक्तियों की रैंकिंग है। यह रैंकिंग का पहला साल है।

प्रमुख बिंदु

- रैंक 1:** जमशेदजी एन टाटा (102.4 बिलियन डॉलर)
- रैंक 2:** बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रैंच गेट्स (74.6 बिलियन डॉलर)
- रैंक 3:** हेनरी वेलकम (56.7 बिलियन डॉलर)



Follow us on
Telegram



Gradeup
PCS & Other
State Exams



- **रैंक 12:** अजीम प्रेमजी (22 बिलियन डॉलर)

नोट: अमेरिका 38 अरबपतियों के साथ सूची सबसे ऊपर, उसके बाद ब्रिटेन (5), चीन (3), भारत (2) और पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड एक-एक हैं।

स्रोत: द हिंदू

पुस्तकें और लेखक

क्रिकेट के दिग्गज रवि शास्त्री की किताब 'स्टारगेजिंग: द प्लेयर्स इन माई लाइफ'

चर्चा में क्यों?

- क्रिकेट के दिग्गज, कमेटेटर और टीम इंडिया के सबसे सफल कोचों में से एक, रवि शास्त्री ने 'स्टारगेजिंग: द प्लेयर्स इन माई लाइफ' नामक एक किताब लिखी है।

प्रमुख बिंदु

पुस्तक के बारे में: 'स्टारगेजिंग: द प्लेयर्स इन माई लाइफ' रवि शास्त्री और खेल पत्रकार अयाज मेमन द्वारा सह-लिखित है और इसके 2021 में जारी होने की उम्मीद है।

- पुस्तक में, शास्त्री दुनिया भर से मिले लगभग 60 असाधारण प्रतिभाओं के बारे में लिखते हैं जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया है।
- इसे हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित किया जाएगा।

सलमान रुश्दी की पुस्तक "लैंगवेज ऑफ ड्रुथः एसेज 2003-2020"

चर्चा में क्यों?

- सलमान रुश्दी ने "लैंगवेज ऑफ ड्रुथः एसेज 2003-2020" नामक एक नई किताब लिखी है।

प्रमुख बिंदु

पुस्तक के बारे में:

- अपनी नई पुस्तक, "लैंगवेज ऑफ ड्रुथः एसेज 2003-2020" में, रुश्दी एक रक्षात्मक कास्टिंग चाल करने का प्रयास करते हैं।
- उनका सुझाव है कि उनके काम को गलत समझा गया है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है क्योंकि साहित्यिक संस्कृति ब्रियो से भरे कल्पनाशील लेखन से "ऑटोफिक्शन" के विनम्र प्रसन्नता की ओर बदल गई है, जैसा कि ऐलेना फेरेटे और कार्ल ओवे नोसगार्ड के काम का उदाहरण दिया गया है।

लेखक के बारे में:

- सलमान रुश्दी एक ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार और निबंधकार हैं। उनके दूसरे उपन्यास, 'मिडनाइट्स चिल्ड्रन' (1981) ने 1981 में बुकर पुरस्कार जीता। उनके अधिकांश उपन्यास भारतीय उपमहाद्वीप पर आधारित हैं।

'होम इन द वर्ल्ड': अमर्त्य सेन का संस्मरण

चर्चा में क्यों?

- नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने 'होम इन द वर्ल्ड' शीर्षक से अपना संस्मरण लिखा है।
- पुस्तक का प्रकाशन जुलाई 2021 में पेंगुइन रैम्डम हाउस द्वारा किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- 'होम इन द वर्ल्ड' में, सेन अपने जीवन से विवरण साझा करते हैं और 'घर' के विचार की खोज करते हैं।
- उन्हें 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार और 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।

स्रोत: TOI

अमिताभ घोष की नई किताब 'द नटमेगस कर्स'

चर्चा में क्यों?

- जानपीठ पुरस्कार से सम्मानित और प्रसिद्ध लेखक अमिताभ घोष की नई किताब 'द नटमेगस कर्स: पैरेबल्स फॉर ए प्लैनेट इन क्राइसिस' जल्द ही रिलीज होने के लिए तैयार है।

प्रमुख बिंदु

- 'द नटमेगस कर्स' में, घोष चर्चा करते हैं कि नटमेग की अपने मूल बांदा द्वीपों से यात्रा मानव जीवन और पर्यावरण के शोषण की व्यापक औपनिवेशिक मानसिकता पर प्रकाश डालती है, जो आज भी मौजूद है।
- पुस्तक का प्रकाशन जॉन मर्र ने किया है।

स्रोत: TOI



Follow us on
Telegram



महत्वपूर्ण दिवस

29 मई, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक अंतर्राष्ट्रीय दिवस

चर्चा में क्यों?

- विश्व संगठन के काम में अपने अमूल्य योगदान के लिए वर्दीधारी और नागरिक कर्मियों को श्रद्धांजलि देने और संयुक्त राष्ट्र ध्वज के तहत अपनी जान गंवाने वाले शांति सैनिकों को सम्मानित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 29 मई को मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- 2021 का विषय "द रोड टू ए लास्टिंग पीस: लेवरेजिंग द पॉवर ऑफ यूथ फॉर पीस एंड सिक्योरिटी" है।
- संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2002 में महासभा द्वारा स्थापित किया गया था।

डैग हैम्मरस्कजोल्ड मेडल पुरस्कार:

- संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर तीन भारतीय शांति रक्षक (कॉर्पोरल युवराज सिंह, दो नागरिक शांति रक्षक - इवान माइकल पिकार्ड और मूलचंद यादव) को मरणोपरांत डैग हैम्मरस्कजोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया।

नोट: भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में वर्दीधारी कर्मियों का पांचवां सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, जिसमें 5,500 से अधिक सैन्य और पुलिस शांति अभियानों में कार्यरत हैं।

31 मई, विश्व तंबाकू निषेध दिवस

चर्चा में क्यों?

- तंबाकू के उपयोग से जुड़े जोखिम को उजागर करने के लिए हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 का विषय "कमिट टू किट" है।
- दुनिया भर में हर साल 31 मई को मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सदस्य राज्यों द्वारा तंबाकू महामारी और इससे होने वाली रोकथाम योग्य मृत्यु और बीमारी की ओर वैशिक ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाया गया था।

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) के बारे में:

- भारत सरकार ने वर्ष 2007-08 में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) शुरू किया।

05 जून विश्व पर्यावरण दिवस

चर्चा में क्यों?

- विश्व पर्यावरण दिवस (WED) जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है।



Follow us on
Telegram



Gradeup
PCS & Other
State Exams



प्रमुख बिंदु

- विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का विषय 'इकोसिस्टम रीस्टोरेशन' है।

इतिहास:

- विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना 1972 में संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन (5-16 जून, 1972) में की गई थी। दो साल बाद 1974 में पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया।
- पाकिस्तान विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का वैशिक मेजबान था।

पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में:

- एक पारिस्थितिकी तंत्र पौधों और जानवरों का एक समुदाय है जो किसी दिए गए क्षेत्र में एक दूसरे के साथ और उनके निर्जीव वातावरण के साथ बातचीत करता है। निर्जीव वातावरण में मौसम, पृथ्वी, सूर्य, मिट्टी, जलवायु और वातावरण शामिल हैं।

पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के बारे में:

- पारिस्थितिक तंत्र की बहाली का मतलब है कि उन पारिस्थितिक तंत्रों की वसूली में सहायता करना जो कि खराब या नष्ट हो चुके हैं, साथ ही उन पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण करना जो अभी भी बरकरार हैं।

भारत की पहल:

- विश्व पर्यावरण दिवस 2021 पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में इथेनॉल के उत्पादन और पूरे देश में वितरण के लिए महत्वाकांक्षी ई-100 पायलट परियोजना का शुभारंभ किया।
- सरकार ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य प्राप्त करने का समय कम करके 2025 करने का संकल्प लिया है। इससे पहले इस लक्ष्य की प्राप्ति का समय 2030 तय किया गया था जिसे 5 वर्ष कम कर दिया गया है।

अन्य पहलें:

- राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना
- राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम
- हरित भारत राष्ट्रीय मिशन

स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड

07 जून, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस

चर्चा में क्यों?

- विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल 7 जून को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य जागरूकता फैलाना, खाद्य जनित जोखिमों का पता लगाना और उन्हें रोकना, खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि, कृषि, बाजार पहुंच, पर्यटन और सतत विकास में योगदान देना है।

प्रमुख बिंदु

- विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 का विषय "सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमारो" है।

इतिहास

- 2018 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की कि हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाएगा।



Follow us on
Telegram



- खाद्य और कृषि संगठन (FAO) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा संयुक्त रूप से पालन की सुविधा प्रदान की जाती है।

नोट:

- 2020 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने खाद्य सुरक्षा और खाद्य जनित रोगों को नियंत्रित करने के लिए दुनिया भर में प्रयासों को मजबूत करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया।
- 2030 तक, खाद्य जनित बीमारियों के सालाना 150 से 177 मिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, असुरक्षित भोजन हर साल अनुमानित 420,000 लोगों की जान लेता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

08 जून, विश्व महासागर दिवस 2021

चर्चा में क्यों?

- विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है।
- विश्व स्तर पर लोगों के रोजमर्रा के जीवन में महासागर एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
- प्रमुख बिंदु**
- विश्व महासागर दिवस 2021 का विषय 'द ओशन: लाइफ एंड लाइवलीहुड' है।

इतिहास

- 2008 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फैसला किया कि 8 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा "विश्व महासागर दिवस" के रूप में नामित किया जाएगा।

नोट:

- तीन अरब से अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए समुद्र पर निर्भर हैं।
- समुद्र का केवल एक प्रतिशत ही कानूनी रूप से संरक्षित है।
- हम जिस ऑक्सीजन में सांस लेते हैं उसका लगभग 70 प्रतिशत महासागरों द्वारा निर्मित होता है।
- समुद्री प्रजातियों का विश्व रजिस्टर (WoRMS) के अनुसार, वर्तमान में कम से कम 236,878 नामित समुद्री प्रजातियां हैं।
- सभी ज्वालामुखीय गतिविधियों का 90 प्रतिशत महासागरों में होता है।

स्रोत: NDTV

17 जून, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस

चर्चा में क्यों?

- विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस एक संयुक्त राष्ट्र पहल है जो हर साल 17 जून को मनाया जाता है।
- इसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण और सूखे की उपस्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना, मरुस्थलीकरण को रोकने और सूखे से उबरने के तरीकों पर प्रकाश डालना है।

प्रमुख बिंदु

- 2021 के लिए विषय "रेस्टोरेशन. लैंड. रिकवरी. वी बिल्ड बैंक बेटर विथ हेल्थी लैंड" है।

इतिहास:

- इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा 30 जनवरी, 1995 को घोषित किया गया था, उस दिन के बाद जब यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन (UNCCD) का ड्राफ्ट तैयार किया गया था।

नोट: भारत 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर खराब भूमि को बहाल करने की दिशा में काम कर रहा है और साथी विकासशील देशों को भूमि-पुनर्स्थापन रणनीति विकसित करने में सहायता कर रहा है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

21 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

चर्चा में क्यों?

- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IDY) प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इस दिन का विचार योग और इसके कई लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

प्रमुख बिंदु

- ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वेद के पवित्र ग्रंथ में सबसे पहले 'योग' शब्द का उल्लेख किया गया था।
- 2021 का विषय 'योग फॉर वेल-बींग' है।

इतिहास:

- संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की बैठक में 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार प्रस्तावित किया गया था।

UNGA ने 11 दिसंबर, 2014 को मंजूर किए गए अपनी प्रस्ताव में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था। 2015 से दुनिया भर में बड़ी संख्या में प्रतिभागी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते आ रहे हैं।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

खेल सम्बंधित खबरें

एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021

चर्चा में क्यों?

- एशियन एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का 31 वां संस्करण 24 से 31 मई 2021 तक दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- भारत 2 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य पदक के साथ 4वें स्थान पर रहा।

पदक तालिका

रैंक	राष्ट्र	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
1	कजाकिस्तान	8	6	2	16
2	उज्बैकिस्तान	7	6	5	18
3	मंगोलिया	3	0	5	8
4	भारत	2	5	8	15

नोट:

- भारत की मैरी कॉम ने 2021 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता।
- एशियन चैंपियनशिप में मैरी कॉम के लिए यह दूसरा रजत है, जिन्होंने 2008 में रजत के अलावा पांच मौकों - 2003, 2005, 2010, 2012 और 2017 में खिताब जीता है।

फ्रैंच ओपन 2021

- फ्रैंच ओपन 2021 आउटडोर क्ले कोर्ट पर खेला जाने वाला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है।
- यह 30 मई से 13 जून 2021 तक पेरिस, फ्रांस में स्टेड रोलेंड गैरोस में आयोजित किया गया था।

विजेताओं की सूची:

पुरुष एकल	महिला एकल	पुरुष युगल	महिला युगल	मिश्रित युगल



Follow us on
Telegram



विजेता- नोवाक जोकोविच (सर्बिया)	विजेता- बारबोरा क्रेजसिकोवा (चेक गणराज्य)	विजेता- पियरे-ह्यूग्स हर्बर्ट (फ्रांस), निकोलस माहुत (फ्रांस)	विजेता- बारबोरा क्रेजसिकोवा (चेक गणराज्य), कैटरीना सिनियाकोवा (चेक गणराज्य)	विजेता- देसिरा क्राविज्क (अमेरिका), जो सैलिसबरी (ब्रिटेन)
उपविजेता- स्टेफानोस सितसिपास (ग्रीस)	उपविजेता- अनास्तासिया पाव्लुचेनकोवा (रूस)	उपविजेता- अलेक्जेंडर बुब्लिक (कजाखस्तान), एंड्री गोलूबेव (कजाखस्तान)	उपविजेता- बेथानी माटेक-सैंड्स (अमेरिका), इगा स्वियातेक (पोलैंड)	उपविजेता- एलेना वेस्नीना (रूस), असलान करात्सेव (रूस)

- नोट: नोवाक जोकोविच (सर्बिया) ने अपना दूसरा फ्रैंच ओपन खिताब और 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता।
- स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

F1 फ्रैंच ग्रैंड प्रिक्स 2021

- मैक्स वेरस्टापेन (रेड बुल) ने फ्रांस के पॉल रिकार्ड सर्किट में आयोजित F1 फ्रैंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता।
- लुईस हैमिल्टन (मर्सिडीज) ने दूसरा स्थान और सर्जियो पेरेज़ (रेड बुल) ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

रिपोर्ट और अनुक्रमणिका

स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट 2021: UN

चर्चा में क्यों?

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट, प्रकृति-आधारित समाधानों में निवेश प्रवाह का विश्लेषण करती है और जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और भूमि क्षरण संकटों को पूरा करने के लिए आवश्यक भविष्य के निवेश की पहचान करती है।
- रिपोर्ट संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP), विश्व आर्थिक मंच (WEF) और भूमि क्षरण के अर्थशास्त्र (ELD) द्वारा तैयार की गई थी।

प्रमुख बिंदु

'प्रकृति आधारित समाधान' के बारे में:

- प्रकृति-आधारित समाधान सामाजिक-पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए स्थायी प्रबंधन और प्रकृति के उपयोग को संदर्भित करता है। चुनौतियों में जलवायु परिवर्तन, जल सुरक्षा, जल प्रदूषण, खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, जैव विविधता हानि और आपदा जौखिम प्रबंधन जैसे मुद्दे शामिल हैं।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- 8.1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की प्रकृति में कुल निवेश अब और 2050 के बीच आवश्यक है - जबकि वार्षिक निवेश 2050 तक 536 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच जाना चाहिए।
- रिपोर्ट में पाया गया है कि प्रकृति-आधारित समाधानों में वार्षिक निवेश को 2030 तक तिगुना करना होगा और वर्तमान निवेश से 133 बिलियन अमरीकी डॉलर के प्रकृति-आधारित समाधानों में 2050 तक चार गुना बढ़ाना होगा (2020 को आधार वर्ष के रूप में उपयोग करते हुए)।

शीर्ष खर्च करने वाले:

- इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के खर्च में अमेरिका और चीन का वर्चस्व है, इसके बाद जापान, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का स्थान है।
- भारत, ब्राजील और सऊदी अरब जैसे देश भी बड़ी मात्रा में पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय डेटा की रिपोर्ट नहीं करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के बारे में:

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रतिक्रियाओं के समन्वय के लिए जिम्मेदार है।
- मुख्यालय:** नैरोबी, केन्या
- स्थापना:** जून 1972

विश्व आर्थिक मंच (WEF) के बारे में:

- विश्व आर्थिक मंच एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है।
- मुख्यालय:** कोलोन, स्विट्जरलैंड
- स्थापना:** जनवरी 1971

भूमि क्षरण के अर्थशास्त्र (ELD) के बारे में पहल:

- ELD पहल एक वैश्विक पहल है जिसे 2011 में यूनाइटेड नेशन कन्वेशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय और यूरोपीय आयोग द्वारा स्थापित किया गया था। यह ज्ञान के विविध क्षेत्रों में भागीदारों के व्यापक नेटवर्क द्वारा समर्थित है।

स्रोत: unep.org

परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) 2019-20

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय शिक्षा मंत्री, रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) 2019-20 जारी किया।
- PGI: 2019-20 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए तीसरा प्रकाशन है।

प्रमुख बिंदु

कार्यान्वयन एजेंसी

- यह योजना स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSEL) द्वारा शुरू की गई है।

परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) के बारे में

- PGI राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कमी की तरफ इंगित करने में मदद देगा और उसी के अनुसार कार्यक्रम के क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो कि स्कूली शिक्षा प्रणाली सभी स्तरों पर मजबूत है।
- सरकार ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव को उत्प्रेरित करने के लिए 70 मानकों के एक सेट के साथ प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स की शुरुआत की है।

नोट:

- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए PGI पहली बार 2019 में 2017-18 के संदर्भ में प्रकाशित हुआ था।

समग्र परिणाम और निष्कर्ष

- पंजाब, तमिलनाडु, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और केरल ने 2019-20 के लिए उच्चतम स्कोर (ग्रेड I++) प्राप्त किया।

ग्रेड (स्कोर)	राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के नाम
स्तर I (951 - 1000)	शून्य
स्तर II (901 - 950), ग्रेड I++	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, पंजाब, केरल, तमिलनाडु
स्तर III (851 - 900) ग्रेड I+	दादरा और नगर हवेली, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पुडुचेरी, राजस्थान
स्तर IV (801-850) ग्रेड I	आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दमन और दीव, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश

स्तर V (751 - 800) ग्रेड II	गोवा, उत्तराखण्ड, झारखण्ड, लक्षद्वीप, मणिपुर, सिक्किम, तेलंगाना
लेवल VI (701 - 750) ग्रेड III	असम, बिहार, मध्य प्रदेश, मिजोरम
लेवल VII (651 - 700) ग्रेड IV	अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागालैंड
लेवल VIII (601 - 650) ग्रेड V	मेघालय
लेवल XI (551 - 600) ग्रेड VI	शून्य
लेवल X (0 - 550) ग्रेड VII	लद्दाख

- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, पंजाब तथा तमिलनाडु ने समग्र PGI स्कोर में 10 प्रतिशत का सुधार किया है यानी 100 या अधिक अंक।

स्रोत: PIB

भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021

चर्चा में क्यों?

- भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार, 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDG) पर भारत की स्थिति पिछले वर्ष से दो स्थान फिसलकर 117 पर आ गई है।
- रिपोर्ट सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE), नई दिल्ली, भारत द्वारा जारी की गई है।
- 2020 में भारत की रैंक 115 थी।

प्रमुख बिंदु

- भारत का समग्र SDG स्कोर 100 में से 61.9 है।
- भारत चार दक्षिण एशियाई देशों-भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल से नीचे था।
- 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों द्वारा 2030 के एजेंडे के हिस्से के रूप में SDG लक्ष्यों को अपनाया गया था।

रैंक में गिरावट का कारण

- इसका कारण देश में भूख को समाप्त करना और खाद्य सुरक्षा (SDG 2) प्राप्त करना, लैंगिक समानता (SDG 5) प्राप्त करना और लचीला बुनियादी ढांचे का निर्माण, समावेशी और स्थाई औद्योगीकरण को बढ़ावा देना और नवाचार को बढ़ावा देना (SDG 9) जैसी प्रमुख चुनौतियां हैं।

राज्यवार तैयारी



- भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2021 के अनुसार, केरल, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ सर्वश्रेष्ठ समग्र स्कोर के साथ SDG प्राप्त करने के पथ पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं।
- वर्ष 2030 तक SDG को पूरा करने के लिए बिहार और झारखंड सबसे कम तैयार हैं।

स्रोत: हिन्दू

ILO: वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुकः ट्रैंडेस 2021

चर्चा में क्यों?

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुकः ट्रैंडेस 2021 (WESO ट्रैंडेस) जारी किया है।
- रिपोर्ट दुनिया भर में श्रम बाजार पर संकट के प्रभाव का विश्लेषण करती है।

प्रमुख बिंदु

निष्कर्षः

- द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुकः ट्रैंडेस 2021 में वैश्विक संकट से प्रेरित 'नौकरियों का अंतर' 2021 में 75 मिलियन तक पहुंच जाएगा, जो 2022 में 23 मिलियन तक गिर जाएगा।
- वैश्विक बेरोजगारी की दर 2022 में 5.7%, 2021 में 6.3% हो जाएगा।
- वैश्विक बेरोजगारी 2022 में 205 मिलियन लोगों को होने की उम्मीद है।
- काम के घंटों में संबंधित अंतराल, जिसमें नौकरियों का अंतर और कम घंटे शामिल हैं, 2021 में 100 मिलियन पूर्णकालिक नौकरियों और 2022 में 26 मिलियन पूर्णकालिक नौकरियों के बराबर है।
- संकट ने महिलाओं को भी असमान रूप से प्रभावित किया है। उनके रोजगार में 2020 में पुरुषों के 3.9 प्रतिशत की तुलना में 5 प्रतिशत की गिरावट आई है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के बारे मेंः

- यह एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जिसका जनादेश अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करके सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाना है।

मुख्यालयः जिनेवा, स्विट्जरलैंड

महानिदेशकः गाइ राइडर

स्थापना: 11 अप्रैल 1919

- ILO में 187 सदस्य राज्य हैं।
- भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का संस्थापक सदस्य है।

नोटः

भारत ने 2020 में ILO के शासी निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की है।

स्रोतः ILO

UN ग्लोबल कॉम्पेक्ट के CEO वाटर मैंडेट

चर्चा में क्यों?

- NTPC लिमिटेड प्रतिष्ठित UN ग्लोबल कॉम्पेक्ट के CEO वाटर मैंडेट का हस्ताक्षरकर्ता बन गया है।

प्रमुख बिंदु



Follow us on
Telegram



Gradeup
PCS & Other
State Exams



- NTPC जल नीति को लागू करने के माध्यम से जल स्थिरता के मुद्दों को सक्रिय रूप से संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो जल प्रबंधन रणनीतियों, प्रणालियों, प्रक्रियाओं, प्रथाओं और अनुसंधान पहलों की स्थापना के लिए एक निर्देश के रूप में काम करेगा।
- NTPC विद्युत उत्पादन की अपनी मुख्य व्यावसायिक गतिविधि को अंजाम देते हुए जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए 3 R (रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल) को और अधिक बढ़ावा देगा।

CEO वाटर मैंडेट के बारे में:

- CEO वाटर मैंडेट एक संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल है जो पानी, स्वच्छता और सतत विकास लक्ष्यों पर बिजनेस लीडर्स को एकजुट करती है।

मैंडेट के छह प्रतिबद्धता क्षेत्र:

- प्रत्यक्ष संचालन
- आपूर्ति शृंखला और वाटरशेड प्रबंधन
- सामूहिक कार्रवाई
- सार्वजनिक नीति
- सामुदायिक जुड़ाव
- पारदर्शिता

संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के बारे में:

- संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट एक गैर बाध्यकारी संयुक्त राष्ट्र स्थायी और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नीतियों को अपनाने के लिए, और उनके कार्यान्वयन पर रिपोर्ट करने के लिए दुनिया भर में व्यवसायों और कंपनियों को प्रोत्साहित करने की संधि है।
- भारत UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट का भी हिस्सा है।

NTPC लिमिटेड के बारे में:

- यह, जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, भारत सरकार का बिजली बोर्ड है जो बिजली उत्पादन और संबद्ध गतिविधियों के व्यवसाय में लगा हुआ है।
- NTPC को मई 2010 में भारत सरकार द्वारा महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया था।

पर्यावरण संरक्षण के लिए अन्य पहल:

- रेस टू जीरो कैपेन
- औद्योगिक डीप डीकार्बनाइजेशन पहल

स्रोत: PIB

QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022

चर्चा में क्यों?

- QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के शीर्ष -200 स्थानों में तीन भारतीय विश्वविद्यालयों ने अपनी जगह बनायी है।
- IISc बंगलुरु अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व में प्रथम स्थान पर है।

प्रमुख बिंदु

भारतीय संस्थान:

- QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में तीन भारतीय विश्वविद्यालयों को शीर्ष -200 में स्थान दिया गया है, जिसमें IIT-बॉम्बे 177 वें स्थान पर, IIT-दिल्ली 185 वें स्थान पर और IISc-बैंगलुरु 186 वें स्थान पर है।
- भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) बैंगलोर ने विश्लेषण में साइटेशन पर फैकल्टी (CPF) मीट्रिक के लिए 100 में से 100 का सही स्कोर प्राप्त किया है।

वैश्विक रैंकिंग:

- अमेरिका स्थित मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) ने लगातार 10वें वर्ष में नंबर एक के रूप में रिकॉर्ड-विस्तार हासिल किया।
- ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, 2006 के बाद से पहली बार के लिए दूसरे स्थान पर पहुंचा गया, जबकि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की हिस्सेदारी तीसरे स्थान पर है।

QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में:

- लंदन स्थित QS क्वाक्वेरेली साइमंडस, वैश्विक उच्च शिक्षा विश्लेषकों ने विश्व की अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय रैंकिंग का 18वां संस्करण जारी किया है।
- QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के लिए, संस्थानों और विश्वविद्यालयों को छह संकेतकों शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा, प्रति संकाय उद्धरण, संकाय / छात्र अनुपात, अंतर्राष्ट्रीय संकाय अनुपात और अंतर्राष्ट्रीय छात्र अनुपात पर आंका गया।

शिक्षा के लिए संबंधित भारतीय पहल:

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020: NEP का उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली में स्कूल से लेकर कॉलेज स्तर तक कई बदलाव लाना और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है।
- इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस (IoE) योजना: IoE 20 संस्थानों (सार्वजनिक क्षेत्र से 10 और निजी क्षेत्र से 10) को विश्व स्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों के रूप में स्थापित करने या अपग्रेड करने के लिए नियामक वास्तुकला प्रदान करने की एक योजना है जिसे 'इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस' कहा जाता है।
- उच्चतर आविष्कार योजना (UAY): UAY की घोषणा एक उच्च क्रम के नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी जो सीधे उद्योग की जरूरतों को प्रभावित करता है और इस तरह भारतीय विनिर्माण के प्रतिस्पर्धात्मक किनारे में सुधार करता है।
- इंप्रिंटिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी (IMPRINT): यह प्रमुख इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी चुनौतियों को हल करने के लिए एक नई शिक्षा नीति और अनुसंधान के लिए रोडमैप विकसित करने के लिए अपनी तरह का पहला पैन-IIT और IISc संयुक्त पहल है।

स्रोत: TOI

उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE) 2019-20 रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE) 2019-20 रिपोर्ट को जारी करने की मंजूरी दी।
- यह रिपोर्ट देश में उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर प्रमुख प्रदर्शन संकेतक प्रदान करती है।
- उच्च शिक्षा विभाग की प्रत्येक साल जारी अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) की श्रृंखला में यह 10वीं रिपोर्ट है।



Follow us on
Telegram



Gradeup
PCS & Other
State Exams



प्रमुख बिंदु

AISHE 2019-20 रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं:

- 2015-16 से 2019-20 तक पिछले पांच वर्षों में छात्र नामांकन में 11.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
- उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 2019-20 में 3.85 करोड़ रहा है। 2018-19 में यह 3.74 करोड़ था। इसमें 11.36 लाख (3.04 प्रतिशत) की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2014-15 में कुल नामांकन 3.42 करोड़ रहा था।
- उच्च शिक्षा में लैंगिक समानता सूचकांक (GPI) 2018-19 में 1.00 के मुकाबले 2019-20 में 1.01 रहा। यह पात्र आयु समूह में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा में सापेक्ष पहुंच में सुधार के संकेत हैं।
- सकल नामांकन दर (GER), 2019-20 में उच्च शिक्षा में नामांकित पात्र आयु वर्गों के छात्रों का प्रतिशत 27.1 प्रतिशत था। 2018-19 में यह 26.3 प्रतिशत और 2014-15 में 24.3 प्रतिशत था।
- 2019-20 में उच्च शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात 26 है।
- 2019-20 में: विश्वविद्यालय: 1,043(2 प्रतिशत); कॉलेज: 42,343 (77 प्रतिशत) और स्वचालित संस्थान: 11,779 (21 प्रतिशत)।
- 3.38 करोड़ छात्रों ने स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रमों में नामांकन लिया। इनमें से लगभग 85 प्रतिशत छात्र (2.85 करोड़) मानविकी, विज्ञान, वाणिज्य, इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकी, चिकित्सा विज्ञान और IT व कंप्यूटर जैसे छह प्रमुख विषयों में नामांकित थे।
- शिक्षकों की कुल संख्या 15,03,156 है, जिसमें 57.5 प्रतिशत पुरुष और 42.5 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं।
- इस अवधि के दौरान उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में 18.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

हाल की पहल:

- शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग के संवर्धन के लिए योजना (SPARC)
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020
- प्रधानमंत्री अनुसंधान फैलोशिप (PMRF)
- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)

स्रोत: PIB

ILO, UNICEF रिपोर्ट: बाल श्रम बढ़कर 160 मिलियन हुआ - दो दशकों में पहली बार वृद्धि

चर्चा में क्यों?

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) और UNICEF की रिपोर्ट के अनुसार 'बाल श्रम: वैश्विक अनुमान 2020, रुझान और आगे की राह', दुनिया भर में बाल श्रम में बच्चों की संख्या बढ़कर 160 मिलियन हो गई है, जिसमें पिछले चार वर्षों में 8.4 मिलियन बच्चों की वृद्धि हुई है।

प्रमुख बिंदु

- 'बाल श्रम: वैश्विक अनुमान 2020, रुझान और आगे की राह' रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि बाल श्रम को समाप्त करने की प्रगति 20 वर्षों में पहली बार रुकी हुई है, पिछली गिरावट की प्रवृत्ति को उलटते हुए, जिसमें 2000 और 2016 के बीच बाल श्रम में 94 मिलियन की गिरावट देखी गई थी।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- रिपोर्ट बाल श्रम में 5 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की ओर इशारा करती है, जो अब कुल वैशिक आंकड़े का आधा हिस्सा है।
- खतरनाक काम में आयु वर्ग के 5 से 17 साल के बच्चों की संख्या 2016 के बाद से 6.5 मिलियन बढ़कर 79 मिलियन हो गयी है।
- रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि वैशिक स्तर पर, नौ मिलियन अतिरिक्त बच्चों को महामारी के परिणामस्वरूप 2022 के अंत तक बाल श्रम में धकेलने का खतरा है।
- कृषि क्षेत्र में 70 प्रतिशत बच्चे बाल श्रम (112 मिलियन) में हैं, इसके बाद सेवाओं में 20 प्रतिशत (31.4 मिलियन) और उद्योग में 10 प्रतिशत (16.5 मिलियन) हैं।
- 5 से 11 वर्ष की आयु के लगभग 28 प्रतिशत बच्चे और 12 से 14 वर्ष की आयु के 35 प्रतिशत बच्चे बाल श्रम में स्कूल से बाहर हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों (14 प्रतिशत) में बाल श्रम की व्यापकता शहरी क्षेत्रों (5 प्रतिशत) की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है।

स्थिति में सुधार के उपाय:

- सार्वभौमिक बाल लाभ सहित सभी के लिए पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा।
- निःशुल्क और अच्छी गुणवत्ता वाली स्कूली शिक्षा पर खर्च में वृद्धि और सभी बच्चों को स्कूल में वापस लाना - जिनमें वे बच्चे भी शामिल हैं जो COVID-19 से पहले स्कूल से बाहर थे।
- वयस्कों के लिए अच्छे काम को बढ़ावा देना, ताकि परिवारों को पारिवारिक आय उत्पन्न करने में मदद करने वाले बच्चों का सहारा न लेना पड़े।
- बाल श्रम को प्रभावित करने वाले हानिकारक लिंग मानदंडों और भेदभाव का अंत।
- बाल संरक्षण प्रणालियों, कृषि विकास, ग्रामीण सार्वजनिक सेवाओं, बुनियादी ढांचे और आजीविका में निवेश।

भारत सरकार की पहल:

- बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986
- बाल श्रम राष्ट्रीय नीति (1987)
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
- ऑपरेशन स्माइल, ऑपरेशन मुस्कान जैसी पहल

नोट: चाइल्डफंड, बचपन बचाओ आंदोलन, केयर इंडिया, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन आदि जैसे कई गैर सरकारी संगठन देश में बाल श्रम को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं।

स्रोत: ilo.org

भारत 2020 और 2050 के बीच 311 लाख करोड़ रुपए मूल्य के लॉजिस्टिक ईंधन की बचत कर सकता है: NITI आयोग, RMI इंडिया रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

- NITI आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट (RMI) और RMI इंडिया की नई रिपोर्ट, 'भारत में फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट: स्वच्छ और लागत प्रभावी माल परिवहन के लिए एक रोडमैप', भारत के लिए अपनी लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है।

प्रमुख बिंदु



- वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती मांग के कारण, भविष्य में माल परिवहन की मांग तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।
- यद्यपि माल परिवहन आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है लेकिन यह ऊंची लॉजिस्टिक लागत से ग्रस्त है और CO₂ में वृद्धि तथा शहरों में वायु प्रदूषण में इसका योगदान रहता है।

रिपोर्ट के अनुसार भारत में निम्नलिखित क्षमताएं हैं:

- अपनी लॉजिस्टिक लागत में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 4 प्रतिशत तक कमी लाने की क्षमता।
- 2020-2050 के बीच संचयी CO₂ के 10 गीगाटन बचाने की क्षमता।
- 2050 तक नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) और कण पदार्थ क्रमशः 35 प्रतिशत और 28 प्रतिशत तक घटाने की क्षमता।

माल परिवहन को लागत प्रभावी बनाने की आवश्यकता:

- माल परिवहन भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था की प्रमुख रीढ़ है और अब पहले से कहीं अधिक इस परिवहन प्रणाली को अधिक लागत सक्षम, कुशल और स्वच्छ बनाना महत्वपूर्ण है।
- कुशल माल परिवहन में इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत तथा डिजिटल इंडिया जैसे सरकार के वर्तमान पहलों को हासिल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- भारत की माल परिवहन गतिविधि 2050 तक पांच गुनी हो जाएगी और लगभग 400 मिलियन नागरिक शहरों की ओर जाएंगे। ऐसे में संपूर्ण प्रणाली में परिवर्तन ही माल ढुलाई क्षेत्र को ऊपर उठा सकता है।
- इस परिवर्तन को कुशल रेल आधारित परिवहन, लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला के अधिकतम उपयोग तथा बिजली और अन्य स्वच्छ ईंधन वाहनों में बदलाव जैसे अवसरों का लाभ उठा कर परिभाषित किया जाएगा।

सिफारिशें:

- रेल नेटवर्क की क्षमता बढ़ाना
- वेयरहाउसिंग और ट्रक परिचालन व्यवहारों में सुधार
- इंटरमोडल परिवहन को बढ़ावा देना
- नीतिगत उपायों और स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए पायलट परियोजनाएं
- ईंधन अर्थव्यवस्था के कठोर मानक

हाल की पहल:

- डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर
- भारत चरण VI मानदंड
- FAME योजना
- कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता विनियम
- फास्टैग के साथ ई-वे बिल का एकीकरण

स्रोत: PIB

EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021

चर्चा में क्यों?

- न्यूजीलैंड के ऑक्लैंड ने EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।

प्रमुख बिंदु

ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स बारे में:

- ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU), द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक मूल्यांकन है जो शहरी जीवन की गुणवत्ता के लिए 140 वैश्विक शहरों की रैंकिंग करता है।
- इंडेक्स 30 से अधिक गुणात्मक और मात्रात्मक पांच व्यापक श्रेणियों में फैले कारकों: स्थायित्व (25%), स्वास्थ्य सेवा (20%), संस्कृति और पर्यावरण (25%), शिक्षा (10%), और आधारभूत अवसंरचना (20%) के आधार पर तैयार किया जाता है।

2021 में 3 सबसे अधिक रहने योग्य शहर:

- ऑक्लैंड, न्यूजीलैंड
- ओसाका, जापान
- एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया

2021 में 3 सबसे कम रहने योग्य शहर:

- दमिश्क, सीरिया
- लागोस, नाइजीरिया
- पोर्ट मोरेस्बी, पापुआ न्यू गिनी

नोट: ऑस्ट्रिया का वियना, 2018 और 2019 दोनों में नंबर एक, COVID से अत्यधिक प्रभावित होने के बाद पूरी तरह से शीर्ष 10 से बाहर हो गया है, और अब 12 वें स्थान पर है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

WGI 2021 ने भारत को दुनिया का 14वां सबसे धर्मार्थ (चैरिटेबल) देश घोषित किया

चर्चा में क्यों?

- वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 (WGI) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अब दुनिया के सबसे धर्मार्थ देश के रूप में 14 वें स्थान पर है।
- इंडेक्स में इंडोनेशिया इस सूची में सबसे ऊपर है और उसके बाद केन्या है।

प्रमुख बिंदु

- भारत को दुनिया भर में शीर्ष 20 सबसे उदार देशों में मान्यता दी गई है, जो इसके पहले के 10 साल के वैश्विक रैंक 82 से एक सुधार है।
- रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 61 प्रतिशत भारतीयों ने अजनबियों की मदद की, 34 प्रतिशत ने अच्छे काम के लिए स्वेच्छा से मदद की, जबकि 36 प्रतिशत ने पैसे दान किए।

नोट: रिपोर्ट बताती है कि COVID-19 महामारी ने दुनिया भर में 'देने' के चलन को और बढ़ा दिया है।

वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स (WGI) के बारे में:

- WGI एक वैश्विक सर्वेक्षण है जिसने 2009 से अब तक 1.6 मिलियन से अधिक लोगों का साक्षात्कार लिया है।
- यह तीन प्रश्न पूछकर सर्वेक्षण करता है: क्या उन्होंने हाल के महीनों में किसी अजनबी की मदद की है, पैसे दिए हैं, या किसी अच्छे कारण के लिए स्वेच्छा से काम किया है।
- यह चैरिटी एड फाउंडेशन (CAF) द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें गैलप द्वारा एकत्र किए गए डेटा का उपयोग किया जाता है और दुनिया के देशों को वे कितने धर्मार्थ हैं, के अनुसार रैंक करते हैं।



Follow us on
Telegram



- पहली रिपोर्ट 2010 में तैयार की गई थी और इस साल WGI की 10वीं वर्षगांठ है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारत ने IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में 43वाँ स्थान बनाए रखा

चर्चा में क्यों?

- IMD (इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट) द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में भारत ने 43वाँ स्थान बनाए रखा।
- IMD ने 2021 में दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर COVID-19 के प्रभाव की जांच की।

प्रमुख बिंदु

- रैंक 1: स्विट्जरलैंड
- रैंक 2: स्वीडन
- रैंक 3: डेनमार्क
- रैंक 43: भारत

भारत का प्रदर्शन:

- BRICS** देशों में भारत, चीन (16वें) के बाद दूसरे (43वें) स्थान पर है, इसके बाद रूस (45वें), ब्राज़ील (57वें) और दक्षिण अफ्रीका (62वें) का स्थान है।
- भारत ने पिछले तीन वर्षों से अपनी स्थिति बनाए रखी है, लेकिन 2021 में, सरकारी दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ।
- सरकारी दक्षता कारक में भारत के सुधार ज्यादातर अपेक्षाकृत स्थिर सार्वजनिक वित्त और सरकार द्वारा निजी कंपनियों को प्रदान की जाने वाली सब्सिडी के कारण हैं।

अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए भारत द्वारा हाल ही में उठाए गए कदम:

- भारत के विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और निर्यात के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन लिंक प्रोत्साहन (PLI) योजना।
- 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के पांच स्तंभ अर्थव्यवस्था, प्रणाली, बुनियादी ढांचा, जीवंत जनसांख्यिकी और मांग हैं।

विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग के बारे में:

- IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता ईयरबुक, जो एक व्यापक वार्षिक रिपोर्ट और देशों की प्रतिस्पर्धा पर विश्वव्यापी संदर्भ बिंदु है, पहली बार 1989 में प्रकाशित हुई।
- ईयरबुक 64 अर्थव्यवस्थाओं का व्यापक कवरेज प्रदान करता है।
- रैंकिंग आर्थिक साहित्य, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्रोतों और सरकारी एजेंसियों, व्यावसायिक समुदाय और शिक्षाविदों से प्रतिक्रिया का उपयोग करके व्यापक शोध के परिणामस्वरूप चुने गए 334 प्रतिस्पर्धात्मकता मानदंडों पर आधारित है।

कारक:

रैंकिंग चार कारकों की जांच करके 64 देशों की समृद्धि और प्रतिस्पर्धा को मापती है:

- आर्थिक प्रदर्शन
- सरकारी दक्षता
- व्यापार दक्षता
- आधारभूत संरचना



Follow us on
Telegram



स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड

ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021: भारत 135 वें स्थान पर

चर्चा में क्यों?

- ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 के 15वें संस्करण के अनुसार, भारत को 163 देशों में 135वें स्थान पर रखा गया है, जो 'शांति' की कम स्थिति' को निर्दिष्ट करता है।

प्रमुख बिंदु

निष्कर्ष:

रैंक 1: आइसलैंड

रैंक 2: न्यूजीलैंड

रैंक 3: डेनमार्क

रैंक 135: भारत

- दुनिया के 10 सबसे शांतिपूर्ण देशों में से 8 यूरोप से हैं।
- अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है।
- रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक शांति के औसत स्तर में 0.07 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो पिछले तेरह वर्षों में नौवीं गिरावट है।

ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 के बारे में:

- यह ग्लोबल पीस इंडेक्स (GPI) का 15वां संस्करण है, जो शांति के स्तर के अनुसार 163 स्वतंत्र राज्यों और क्षेत्रों को रैंक करता है।
- इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP) द्वारा निर्मित, GPI वैश्विक शांति का विश्व का प्रमुख उपाय है।
- GPI अत्यधिक सम्मानित स्रोतों से 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतकों का उपयोग करते हुए दुनिया की 99.7 प्रतिशत आबादी को कवर करता है, और तीन डोमेन में शांति की स्थिति को मापता है: सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा का स्तर, चल रहे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की सीमा, और सैन्यीकरण की डिग्री।

स्रोत: economicsandpeace.org

NTPC भारत में 'कार्य करने के लिए महान स्थान' में शीर्ष 50 में

चर्चा में क्यों?

- NTPC विद्युत मंत्रालय के तहत एक महारत्न PSU है जिसे ग्रेट प्लेस टू वर्क (GPTW) संस्थान के द्वारा लगातार 15वें वर्ष भारत में कार्य करने के लिए महान स्थान में से एक के रूप में स्थान मिला है।
- NTPC भारत के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में लगातार शामिल होने वाला एकमात्र PSU है।
- इस वर्ष NTPC 38वें स्थान पर है, जो पिछले वर्ष 47वें स्थान पर था।

प्रमुख बिंदु

ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन (GPWC) के बारे में:

- ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन सबसे अहम 'नियोक्ता-की-पसंद' का प्रमाण है।



Follow us on
Telegram



Gradeup
State PCS



- इस सर्टिफिकेशन की दुनिया भर में कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा समान रूप से मान्यता प्राप्त है और इसके द्वारा बेहतरीन काम करने के माहौल, लोगों के उच्च विश्वास के मानकों पर परखने के कारण सर्टिफिकेशन को स्वर्ण मानक के रूप में भी मान्यता प्राप्त है।
- इसने राष्ट्र-निर्माताओं के बीच 2021 में भारत के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं में अपनी पहली पहचान भी हासिल की है।

नोट: NTPC ने मार्च 2021 में CII HR एक्सीलेंस रोल मॉडल अवार्ड भी जीता, जो देश में पीपुल मैनेजमेंट के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है।

स्रोत: PIB



Follow us on
Telegram



Gradeup
PCS & Other
State Exams



नयी नियुक्तियां

आश्रिता वी ओलेटी भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनीं

चर्चा में क्यों?

- भारतीय वायु सेना (IAF) की अधिकारी आश्रिता वी ओलेटी देश की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बन गई हैं।

प्रमुख बिंदु

- कर्नाटक की मूल निवासी आश्रिता वी ओलेटी ने पायलट स्कूल में एक साल का कोर्स पूरा करने के बाद 43वें फ्लाइट टेस्ट कोर्स के तहत स्नातक किया है।
- ओलेटी सशस्त्र बलों में शामिल होने से पहले विमान और हवाई प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होंगी।

नोट: मेडिकल विंग को छोड़कर जिसमें महिलाएं दशकों से सेवा कर रही हैं, सेना में 6,807 महिला अधिकारी हैं, IAF में 1,607 और नौसेना में 704 महिला अधिकारी हैं। प्रतिशत के संदर्भ में, महिलाएं अभी भी सेना का एक छोटा हिस्सा हैं- सेना का 0.56%, वायु सेना का 1.08% और नौसेना का 6.5%।

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा ने NHRC के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला

चर्चा में क्यों?

- न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा (सेवानिवृत्त) ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला।

प्रमुख बिंदु

- अरुण कुमार मिश्रा अगस्त 2020 में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए थे।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के बारे में: यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार 12 अक्टूबर 1993 को गठित एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है।

जगजीत पवाडिया अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित

चर्चा में क्यों?

- भारत के पूर्व नारकोटिक्स कमिश्नर जगजीत पवाडिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड (INCB) का अध्यक्ष चुना गया है।
- वह कॉर्नेलिस पी डी जॉनचेरे का स्थान लेंगी।

प्रमुख बिंदु

- जगजीत पवाडिया संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय हैं और इस पद को संभालने वाली दूसरी महिला हैं।
- वह 2015 से INCB की सदस्य हैं। वह 2016 में बोर्ड की पहली उपाध्यक्ष चुनी गई।

अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड (INCB) के बारे में:

- INCB एक स्वतंत्र, अर्ध-न्यायिक विशेषज्ञ निकाय है, जिसकी स्थापना 1961 के नारकोटिक ड्रग्स पर एकल कन्वेंशन द्वारा दो निकायों: स्थायी केंद्रीय नारकोटिक्स बोर्ड और ड्रग पर्यवेक्षी निकाय को मिलाकर की गई थी।



Follow us on
Telegram



Gradeup
PCS & Other
State Exams



- इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया है।

इसाक हर्जोग इज़राइल के राष्ट्रपति चुने गए

चर्चा में क्यों?

- वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ, इसाक हर्जोग, इज़राइल के 11वें राष्ट्रपति चुने गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- पूर्व लेबर नेता इसाक हर्जोग पहले इज़राइली राष्ट्रपति होंगे जो एक पूर्व राष्ट्रपति के बेटे हैं।
- हर्जोग वर्तमान में यहूदी एजेंसी के प्रमुख हैं - एक गैर-लाभकारी संस्था जो इज़राइल में आप्रवासन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के साथ काम करती है।

इज़राइल के बारे में तथ्य:

- प्रधानमंत्री: बैंजामिन नेतन्याहू
- राजधानी: यरुशलम
- मुद्रा: इज़राइली शेकेल

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

डॉ पैट्रिक अमोथ WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित

चर्चा में क्यों?

- केन्या के डॉ पैट्रिक अमोथ को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है।

प्रमुख बिंदु

- डॉ अमोथ केन्या के स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य के लिए कार्यवाहक महानिदेशक (DG) हैं।
- उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन की जगह ली जिन्होंने 02 जून को WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया।

WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन) के बारे में तथ्य:

- मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड
- स्थापना: 7 अप्रैल 1948
- महानिदेशक: डॉ टेड्रोस अदनोम घेब्रेयियस

स्रोत: द इकोनॉमिक टाइम्स

मालदीव के विदेश मंत्री UNGA के अध्यक्ष चुने गए

चर्चा में क्यों?

- मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया।

प्रमुख बिंदु

- अब्दुल्ला शाहिद तुर्की के राजनयिक वोल्कन बोजकिर का स्थान लेंगे जो 75वें सत्र के लिए UNGA के अध्यक्ष थे।
- क्षेत्रीय रोटेशन के स्थापित नियमों के अनुसार, महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष को एशिया-प्रशांत राज्यों के समूह से चुना जाना था।

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के बारे में:

- यह संयुक्त राष्ट्र (UN) के छह प्रमुख अंगों में से एक है, जो संयुक्त राष्ट्र के मुख्य विचार-विमर्श, नीति-निर्माण और प्रतिनिधि अंग के रूप में कार्य करता है।
- UNGA संयुक्त राष्ट्र के बजट, सुरक्षा परिषद में गैर-स्थायी सदस्यों की नियुक्ति, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अन्य भागों से रिपोर्ट प्राप्त करना और प्रस्तावों के माध्यम से सिफारिशें करने के लिए जिम्मेदार है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

रंजीत सिंह दिसाले विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त

चर्चा में क्यों?

- रंजीत सिंह दिसाले, ग्लोबल शिक्षक पुरस्कार 2020 प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शिक्षक, को जून 2021 से जून 2024 की अवधि के लिए विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।
- विश्व बैंक ने दुनिया भर से 12 सलाहकार नियुक्त किए हैं और डिसाले उनमें से एक भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

प्रमुख बिंदु

- रंजीत सिंह दिसाले महाराष्ट्र के सोलापुर के प्राथमिक शिक्षक हैं।
- डिसाले को लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और भारत में एक त्वरित प्रतिक्रिया (QR) कोडित पाठ्यपुस्तक क्रांति को गति प्रदान करने के उनके प्रयासों को मान्यता देने के लिए वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 का विजेता नामित किया गया था।

नोट:

- विश्व बैंक ने हाल ही में ग्लोबल कोच प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो एक नई पहल है जो देशों को सेवाकालीन शिक्षक पेशेवर विकास (TDP) कार्यक्रमों और प्रणालियों में सुधार करने में मदद करके सीखने में तेजी लाने पर केंद्रित है।

स्रोत: NDTV

अनूप चंद्र पाण्डेय ने नए चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला

चर्चा में क्यों?

- अनूप चंद्र पाण्डेय मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय निकाय में दूसरे चुनाव आयुक्त के रूप में भारत निर्वाचन आयोग में शामिल हुए।

प्रमुख बिंदु

- अनूप चंद्र पाण्डेय 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके हैं।
- भारत सरकार की प्रतिष्ठित सेवा के लगभग 37 वर्षों की अवधि के दौरान, श्री पाण्डेय ने केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों और उत्तर प्रदेश के अपने राज्य संवर्ग में काम किया है।

स्रोत: PIB

माइक्रोसॉफ्ट ने CEO सत्या नडेला को चेयरमैन नामित किया

चर्चा में क्यों?

- माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सत्या नडेला को अपना नया चेयरमैन नामित किया।

प्रमुख बिंदु

- सत्या नडेला, जॉन थॉम्पसन की जगह लेंगे, जो प्रमुख स्वतंत्र निदेशक की भूमिका में लौटेंगे।
- कंपनी के तीसरे CEO नडेला, गेट्स और थॉम्पसन के बाद माइक्रोसॉफ्ट के इतिहास में तीसरे चेयरमैन होंगे।

माइक्रोसॉफ्ट के बारे में तथ्य: माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है।

- स्थापना:** 4 अप्रैल, 1975
- संस्थापक:** बिल गेट्स, पॉल एलन
- मुख्यालय:** संयुक्त राज्य अमेरिका
- CEO:** सत्या नडेला

न्यायमूर्ति संजय यादव ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली

चर्चा में क्यों?

- उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के राजभवन में न्यायमूर्ति संजय यादव को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।
- इससे पहले जस्टिस यादव इलाहाबाद HC के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे।
- न्यायमूर्ति यादव ने मध्य प्रदेश के उप महाधिवक्ता के रूप में भी कार्य किया।
- न्यायमूर्ति यादव को 2 मार्च 2007 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और 15 जनवरी 2010 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

अमूल के आर एस सोढ़ी एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन अवार्ड से सम्मानित

चर्चा में क्यों?

- गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF या अमूल) के MD (प्रबंध निदेशक), आर एस सोढ़ी को APO (एशियाई उत्पादकता संगठन), टोक्यो, जापान से एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- पिछले 20 वर्षों में, यह पहली बार है जब किसी भारतीय को प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है।
- गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) के बारे में: यह भारतीय राज्य गुजरात में आणंद में स्थित एक भारतीय डेयरी सहकारी समिति है। इसे अमूल के नाम से भी जाना जाता है।

स्रोत: हिन्दू

नफ्ताली बेनेत इजरायल के नए प्रधानमंत्री

चर्चा में क्यों?



- दक्षिणपंथी यामिना पार्टी के नेता नफताली बेनेत ने इजरायल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।

प्रमुख बिंदु

- नफताली बेनेत बैंजामिन नेतन्याहू की जगह लेंगे, जिन्हें 12 साल बाद पद से हटने के लिए मजबूर किया गया था।
- सत्ता-साझाकरण सौदे के हिस्से के रूप में बेनेत सितंबर 2023 तक प्रधानमंत्री रहेंगे।
- इसके बाद वह दो साल के लिए मध्यमार्गी यश अतीद पार्टी के प्रमुख यायर लैपिड को सत्ता सौंपेंगे।

एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में फिर से निर्वाचित

चर्चा में क्यों?

- संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने एंटोनियो गुटेरेस को 1 जनवरी, 2022 से शुरू होकर 31 दिसंबर, 2026 को समाप्त होने वाले दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में नियुक्त किया।

प्रमुख बिंदु

नियुक्ति:

- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत, महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है।
- प्रत्येक महासचिव के पास दूसरे कार्यकाल का विकल्प होता है यदि वे सदस्य राज्यों से पर्याप्त समर्थन प्राप्त कर सकते हैं।

एंटोनियो गुटेरेस के बारे में:

- संयुक्त राष्ट्र के नौवें महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 1 जनवरी, 2017 को पदभार संभाला और उनका पहला कार्यकाल इस साल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है।
- पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री, श्री गुटेरेस ने जून 2005 से दिसंबर 2015 तक एक दशक तक संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया।

संयुक्त राष्ट्र के बारे में तथ्यः

- स्थापना:** 24 अक्टूबर 1945
- मुख्यालय:** न्यूयॉर्क, USA
- सदस्यता:** 193 सदस्य देश

संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंग हैं:

- आम सभा
- सुरक्षा परिषद
- आर्थिक और सामाजिक परिषद
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
- संयुक्त राष्ट्र सचिवालय
- न्यासी परिषद

निधि और कार्यक्रमः

- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)
- संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (UNICEF)



Follow us on
Telegram



- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UN Environment)
- विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP)
- संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती कार्यक्रम (UN-Habitat)

UNSC (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद) के बारे में तथ्य:

- स्थापना: 24 अक्टूबर 1945
- सदस्यता: 15 देश
- स्थायी सदस्य: 5 (चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका)
- अस्थायी सदस्य: भारत सहित 10

स्रोत: द हिंदू

ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी

चर्चा में क्यों?

- इब्राहिम रायसी को ईरान के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है।

प्रमुख बिंदु

- 60 वर्षीय, इब्राहिम रायसी अगस्त में पदभार ग्रहण करेंगे, भ्रष्टाचार से निपटने और निवर्तमान राष्ट्रपति हसन रुहानी के तहत ईरान द्वारा अनुभव की गई आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए खुद को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में पेश करेंगे।
- वे देश की न्यायपालिका के प्रमुख हैं, और अति-रुढ़िवादी राजनीतिक विचार रखते हैं।

स्रोत: द हिंदू

श्रद्धांजलियाँ

मॉरीशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन

चर्चा में क्यों?

- मॉरीशस के पूर्व प्रधानमंत्री, अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- सम्मान के रूप में, भारत सरकार ने पूरे देश में 05 जून 2021 को एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- 18 साल से अधिक के कार्यकाल के साथ अनिरुद्ध जगन्नाथ देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे।
- उन्हें 1980 के दशक के मॉरीशस आर्थिक चमत्कार का जनक माना जाता था।
- उन्होंने 2003-2012 तक मॉरीशस के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया।

नोट: अनिरुद्ध जगन्नाथ को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया था।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

असमिया साहित्यकार लक्ष्मी नंदन बोरा का निधन

चर्चा में क्यों?

- पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित और प्रसिद्ध असमिया साहित्यकार लक्ष्मी नंदन बोरा का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

प्रमुख बिंदु

- लक्ष्मी नंदन बोरा ने 1988 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता।
- 2008 में, उन्होंने केके बिड़ला फाउंडेशन से सरस्वती सम्मान जीता।
- लक्ष्मी नंदन बोरा को भारत सरकार द्वारा 2015 में चौथे सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया गया था।

स्रोत: द हिंदू

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक बुद्धदेव दासगुप्ता का निधन

चर्चा में क्यों?

- बंगाली फिल्म निर्माता और कवि, बुद्धदेव दासगुप्ता का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- बुद्धदेव दासगुप्ता ने कुल पांच बार सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था।
- उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध कार्यों में बाग बहादुर, लाल दरजा, कालपुरुष और तहदार कथा जैसे प्रोजेक्ट शामिल थे।

स्रोत: द हिंदू

एशियाई खेलों के स्वर्ण विजेता मुक्केबाज डिंग्को सिंह का निधन

चर्चा में क्यों?

- पूर्व एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज डिंग्को सिंह का 47 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- डिंग्को ने 1998 के बैंकॉक 13वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था।



Follow us on
Telegram



Gradeup
State PCS



- वह मणिपुर के पहले एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता भी थे।
- उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए, मणिपुरी मुक्केबाज को 1998 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2013 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया गया।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

पर्यावरणविद् और जैविक खेती के प्रस्तावक राधा मोहन का निधन

चर्चा में क्यों?

- प्रसिद्ध पर्यावरणविद् और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर राधा मोहन, जिन्होंने जैविक खेती तकनीकों को लोकप्रिय बनाने में मदद की, का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- राधा मोहन को उनकी बेटी साबरमती के साथ कृषि क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2020 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था।
- 1990 में, पिता-पुत्री की जोड़ी ने किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से एक सामाजिक संगठन 'संभव' की स्थापना की।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित डॉ अशोक पनगढ़िया का निधन

- प्रमुख न्यूरोलॉजिस्ट और पद्म श्री प्राप्तकर्ता डॉ अशोक पनगढ़िया का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- भारत के प्रमुख न्यूरोलॉजिस्टों में से एक, अशोक पनगढ़िया पद्म श्री और बी सी रॉय पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे।
- नोट:** अशोक पनगढ़िया के प्रकाशक ने घोषणा की कि उनका संस्मरण, "मौक इन ए मर्क" 28 जून, 2021 को जारी किया जाएगा।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

रामकृष्ण मठ और मिशन उपाध्यक्ष का निधन

- रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के उपाध्यक्ष स्वामी शिवमयानंद का निधन हो गया।
- शिवमयानंद का जन्म 20 दिसंबर 1934 को बिहार में हुआ था।
- वह 1959 में बेलूर मठ में शामिल हुए, 1969 में स्वामी वीरेश्वरानंद महाराज से "संन्यास दीक्षा" प्राप्त की।

स्रोत: द हिंदू

कन्नड अभिनेता संचारी विजय का निधन

- राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता संचारी विजय का निधन हो गया।
- विजय कुमार बसवराजैया को उनके मंच नाम संचारी विजय के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता थे जिन्हें कन्नड सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता था।
- 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में विजय को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता - दक्षिण के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड भी मिला।

स्रोत: द हिंदू

महान धावक मिल्खा सिंह का निधन

- मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय ट्रैक और फील्ड स्प्रिंटर (धावक) थे, जिन्हें भारतीय सेना में सेवा के दौरान खेल से परिचित कराया गया था।
- उन्होंने एशियाई खेलों में चार स्वर्ण पदक जीते थे। उन्होंने कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेलों में भी पदक स्वर्ण जीता था।
- उन्हें उनकी खेल उपलब्धियों के लिए पदम श्री सम्मानित से किया गया था।

स्रोत: द हिंदू

विविध घटनाक्रम

IBF इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के रूप में पुनर्नामित

चर्चा में क्यों?

- OTT सेगमेंट में अपने दायरे का विस्तार करने के लिए, ब्रॉडकास्टर्स के शीर्ष उद्योग निकाय इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (IBF) का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन (IBDF) किया गया।

प्रमुख बिंदु

- IBDF** सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के रूप में एक स्व-नियामक निकाय (SRB) बनाएगी।
- डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म के लिए स्व-नियामक निकाय का नाम डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल (**DMCRC**) है।
- DMCRC** अपीलीय स्तर पर एक द्वितीय स्तरीय तंत्र है और प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद (BCCC) के समान है, जिसे IBF ने 2011 में रैखिक प्रसारण क्षेत्र के लिए लागू किया था।

इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के बारे में: इसे भारत में टेलीविजन प्रसारकों के एकीकृत प्रतिनिधि निकाय के रूप में भी जाना जाता है। संगठन की स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी। 250 से अधिक भारतीय टेलीविजन चैनल इससे जुड़े हुए हैं। संगठन को भारत प्रसारण उद्योग के प्रवक्ता के रूप में श्रेय दिया जाता है।

OTT के बारे में: ओवर-द-टॉप (OTT) मीडिया सेवा इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों को सीधे दी जाने वाली मीडिया सेवा है। OTT केबल, ब्रॉडकास्ट और सैटेलाइट टेलीविजन प्लेटफॉर्म को दरकिनार कर देता है, उन कंपनियों के प्रकार जो परंपरागत रूप से ऐसी सामग्री के नियंत्रक या वितरक के रूप में कार्य करते हैं।

DG NCC मोबाइल ट्रेनिंग ऐप 2.0

चर्चा में क्यों?

- रक्षा सचिव डॉ अजय कुमार ने महानिदेशालय (DG) राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) मोबाइल प्रशिक्षण ऐप वर्जन 2.0 की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

DG NCC मोबाइल ट्रेनिंग ऐप 2.0 के बारे में:

- यह एप COVID-19 महामारी की स्थिति के दौरान NCC कैडेटों को देशव्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करने में सहायता करेगा।
- इसका उद्देश्य NCC से संबंधित बुनियादी जानकारी और संपूर्ण प्रशिक्षण सामग्री को एक मंच पर उपलब्ध कराना है।

नोट: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2020 में प्रशिक्षण के लिए **DG NCC मोबाइल ऐप वर्जन 1.0** को ऑनलाइन कैडेट प्रशिक्षण में सहायता के लिए शुरू किया था।

RDSO “एक राष्ट्र एक मानक” अभियान के तहत BIS का पहला संस्थान बना जिसे SDO घोषित किया गया है

चर्चा में क्यों?

- उपभोक्ता मामलों के विभाग के अंतर्गत आने वाले भारतीय रेल के संस्थान RDSO (रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑरगेनाइजेशन) को “एक राष्ट्र एक मानक” अभियान के तहत BIS (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स) का पहला SDO (स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन) संस्थान घोषित किया गया है।
- RDSO ने BIS SDO मान्यता योजना के तहत एक मानक विकास संगठन (SDO) के रूप में मान्यता प्राप्त करने की पहल की।

प्रमुख बिंदु

- रेल मंत्रालय का एकमात्र अनुसंधान एवं विकास संगठन RDSO, लखनऊ, देश के प्रमुख मानक तय करने वाले संस्थानों में से एक है और यह भारतीय रेल के लिए मानक तय करने का काम करता है।
- मान्यता 3 साल के लिए वैध है और वैधता अवधि पूरी होने के बाद नवीनीकरण की आवश्यकता होगी।

BIS SDO मान्यता योजना के बारे में:

- भारत सरकार की “एक राष्ट्र एक मानक” की परिकल्पना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय मानक संस्थान भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने एक योजना शुरू की है जिसके तहत किसी संस्थान को SDO की मान्यता दी जाती है।
- इस योजना के जरिए BIS का लक्ष्य, अपने विशिष्ट क्षेत्रों में मानकों के विकास के काम में लगे देश के विभिन्न संस्थानों में उपलब्ध मौजूदा क्षमताओं और विशिष्ट डोमेन में उपलब्ध सकल विशेषज्ञता को एकीकृत करना है और इस तरह देश में जारी सभी मानक विकास गतिविधियों को रूपांतरित कर “एक विषय पर एक राष्ट्रीय मानक” तैयार करना है।

BIS (भारतीय मानक ब्यूरो) के बारे में:

- भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में काम करने वाला भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। यह भारतीय मानक अधिनियम, 1986 द्वारा स्थापित किया गया जो 23 दिसंबर 1986 को प्रभाव में आया था।

BIS की अन्य पहलें:

- उपभोक्ता जु़ड़ाव के लिए पोर्टल
- BIS-केयर ऐप
- COVID-19 मानक
- गुणवत्ता नियंत्रण आदेश

प्रधानमंत्री ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 पर M-योग ऐप लॉन्च किया

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 'WHO M-योग' ऐप लॉन्च किया।
- प्रधानमंत्री ने कहा कि M-योग ऐप हमारे 'एक विश्व, एक स्वास्थ्य' के आदर्श वाक्य में मदद करेगा।

प्रमुख बिंदु

M-योग ऐप के बारे में:

- ऐप कई भाषाओं में सामान्य योग प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण और अभ्यास के वीडियो प्रदान करेगा।



Follow us on
Telegram



Gradeup
State PCS



- यह मोबाइल ऐप दुनिया भर के लोगों के बीच, विशेष रूप से चल रही महामारी के दौरान योग और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में बहद मददगार साबित होगा।

पृष्ठभूमि:

- आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने संयुक्त रूप से 2019 के मध्य में मोबाइल-योग पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक परियोजना शुरू की थी।
- इसमें 2030 तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के तहत 'स्वस्थ रहें, गतिशील रहें' की अवधारणा की परिकल्पना की गयी है।
- 'स्वस्थ रहें, गतिशील रहें' पहल WHO के नेतृत्व में एक वैश्विक साझेदारी है, जो गैर-संचारी रोगों (NCD) से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली के दायरे में गतिशील स्वास्थ्य (m-स्वास्थ्य) प्रौद्योगिकी के विस्तार का समर्थन करती है।

स्रोत: PIB

साइबर धोखाधड़ी के कारण वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 155260 और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म

चर्चा में क्यों?

- गृह मंत्रालय (MHA) ने साइबर धोखाधड़ी के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 155260 और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म का संचालन शुरू किया है।
- हेल्पलाइन को 01 अप्रैल, 2021 को सॉफ्ट लॉन्च किया गया था।

प्रमुख बिंदु

हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म के बारे में:

- हेल्पलाइन 155260 और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म को गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा संचालित किया जा रहा है।
- कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों एवं वित्तीय मध्यस्थों को एकीकृत करने के उद्देश्य से I4C द्वारा आतंरिक रूप से नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है।

नोट: अपनी लॉन्चिंग के बाद केवल दो माह की छोटी सी अवधि में ही हेल्पलाइन नंबर 155260 कुल 1.85 करोड़ रुपये से भी अधिक की रकम को रोकने में सफल रहा है।

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) योजना:

- सभी प्रकार के साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने के लिए अक्टूबर 2018 में I4C योजना को मंजूरी दी गई थी।

I4C योजना के घटक:

- राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई (TAU)
- राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल
- संयुक्त साइबर अपराध जांच दल के लिए मंच
- राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र (NCTC)
- राष्ट्रीय साइबर अपराध फोरेंसिक प्रयोगशाला (NCFL) पारिस्थितिकी तंत्र
- साइबर अपराध पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन इकाई



Follow us on
Telegram



Gradeup
PCS & Other
State Exams



- राष्ट्रीय साइबर अपराध अनुसंधान और नवाचार केंद्र

साइबर अपराध से निपटने के लिए अन्य पहल:

- भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-IN)
- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2018 का मसौदा
- साइबर स्वच्छता केंद्र

संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन:

- साइबर क्राइम पर कन्वेशन (बुडापेस्ट कन्वेशन) पहली अंतरराष्ट्रीय संधि है जो राष्ट्रीय कानूनों के सामंजस्य, जांच तकनीकों में सुधार और राष्ट्रों के बीच सहयोग बढ़ाकर इंटरनेट और कंप्यूटर अपराध को संबोधित करने की मांग कर रही है।

हस्ताक्षरकर्ता: 67

हस्ताक्षरित: 23 नवंबर 2001

प्रभावी: 1 जुलाई 2004

स्रोत: PIB

ગुજરात के લોથલ મેં રાષ્ટ્રીય સમુદ્રી વિરાસત પરિસર (NMHC)

ચર્ચા મें ક्यों?

- પત્તન, પોત પરિવહન ઔर જલમાર્ગ મંત્રાલય ઔર સંસ્કૃતિ મંત્રાલય ને ગુજરાત કે લોથલ મેં 'રાષ્ટ્રીય સમુદ્રી વિરાસત પરિસર (NMHC) કે વિકાસ મેં સહયોગ' કે લિએ એક સમઝૌતા જાપન પર હસ્તાક્ષર કિએ।

પ્રમુખ બિંદુ

- ગુજરાત કે અહુમાદાબાદ સે લગભગ 80 કિલોમીટર દૂર સ્થિત લોથલ કે ભારતીય પુરાતત્વ સર્વેક્ષણ (ASI) સ્થળ કે આસપાસ કે ક્ષેત્ર મેં એક વિશ્વ સ્તરીય સુવિધા રાષ્ટ્રીય સમુદ્રી વિરાસત પરિસર (NMHC) કો વિકસિત કિયા જાના હૈ।
- દેશ મેં NMHC કો ભારત કી સમુદ્રી વિરાસત કો સમર્પિત અપની તરહ કા પહ્લા વિરાસત પરિસર કે રૂપ મેં વિકસિત કિયા જાના હૈ।
- NMHC કો એક અંતરરાષ્ટ્રીય પર્યટન સ્થળ કે રૂપ મેં વિકસિત કિયા જાએગા, જહાં પ્રાચીન સે લેકર આધુનિક સમય તક કે ભારત કી સમુદ્રી વિરાસત કા પ્રદર્શન કિયા જાએગા ઔર નવીનતમ તકનીક કા ઉપયોગ કરકે એક શૈક્ષણિક દૃષ્ટિકોણ ભારત કી સમુદ્રી વિરાસત કે બારે મેં જાગરૂકતા ફેલાને કે લિએ અપનાયા જાએગા।

લોથલ કે બારે મેં:

- લોથલ સિંધુ ઘાટી સભ્યતા કા એક પ્રાચીન શહર થા, જો આધુનિક રાજ્ય ગુજરાત કે ભાલ ક્ષેત્ર મેં સ્થિત હૈ। શહર કા નિર્માણ લગભગ 2400 ઈસા પૂર્વ શુરૂ હુએ।
- લોથલ સાઇટ કો UNESCO કી વિશ્વ ધરોહર સ્થળ કે રૂપ મેં નામિત કિયા ગયા હૈ, ઔર ઇસકા આવેદન UNESCO કી અસ્થાયી સૂચી મેં લંબિત હૈ।

સ્રોત: PIB



Follow us on
Telegram



Monthly Current Affair Quiz



Attempt this Monthly Current Affair Quiz
for FREE on Gradeup App

Click Here

1. निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

i. हाल ही में, भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य कुमार सेन को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन का प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्र

रियस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है।

ii. अमर्त्य सेन ने 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता था।

- A. केवल i
- B. केवल ii
- C. i और ii दोनों
- D. न तो i न ही ii

2. विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है?

- A. 13 मई
- B. 3 मई
- C. 31 मई
- D. 24 मई

3. ब्रॉडकास्टर्स के शीर्ष उद्योग निकाय इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (IBF) का नाम बदलकर
....कर दिया गया।

- A. इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन
- B. इंडियन बोर्ड ऑफ डिजिटल फाउंडेशन
- C. इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल मीडिया
- D. इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल काउंसिल



Follow us on
Telegram



4. किस राज्य ने केंद्र और राज्य सरकार की नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए 'अभिभावक मंत्री' नियुक्त किया है?

- A. केरल
- B. उत्तर प्रदेश
- C. राजस्थान
- D. असम

5. संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है?

- A. 19 मई
- B. 29 मई
- C. 30 मई
- D. 23 मई

6. शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए YUVA)

- प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की। उन बिंदुओं की पहचान करें जो YUVA से सही ढंग से संबंधित हैं।

- i. YUVA का फुल फॉर्म यंग, अपकमिंग और वर्सटाइल ऑथर है।
- ii. यह युवा और नवोदित लेखकों (40 वर्ष से कम आयु) को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है।
- iii. शिक्षा मंत्रालय के तहत नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है।

- A. केवल ii और iii
- B. केवल i और iii
- C. i, ii, iii
- D. केवल i और ii

7. निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- i. हाल ही में, शिक्षा मंत्रालय ने मध्याह्न-भोजन योजना के खाना पकाने की लागत घटक के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से मौद्रिक सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

ii. मध्याहन-भोजन योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 2001 में शुरू किया गया था।

- A. केवल i
- B. केवल ii
- C. i और ii दोनों
- D. न तो i न ही ii

8. ऐम्बिटैग - कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस..... द्वारा विकसित किया गया है।

- A. IIT दिल्ली
- B. IIT रोपड़
- C. IIT रुड़की
- D. IIT बॉम्बे

9. हाल ही में शुरू किए गए बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम (CDP) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- i. इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है।
- ii. प्रायोगिक चरण में, कार्यक्रम को 49 बागवानी क्लस्टर में लागू किया जाएगा।
- iii. यह राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) द्वारा कार्यान्वित एक केंद्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम है।

- A. केवल iii
- B. केवल i और ii
- C. केवल i और iii
- D. केवल ii और iii

10. निम्नलिखित में से कौन सा कथन 'PM-केरस फॉर चिल्ड्रन' योजना के संबंध में सही नहीं है?

- A. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COVID19 के कारण अनाथ बच्चों के लिए 'PM-केरस फॉर चिल्ड्रन' योजना की शुरुआत की।
- B. बच्चों के 21 वर्ष के होने पर उन्हें घर, मोबाइल और लैपटॉप दिलाने में मदद की जाएगी।
- C. ऐसे बच्चों को 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर मासिक वित्तीय सहायता और 23 वर्ष की आयु पूरी करने पर P

M केर्यर्स से 10 लाख रुपये की राशि मिलेगी।

D. ऐसे बच्चों को आयुष्मान भारत योजना (PM-JAY) के तहत 18 वर्ष की आयु तक 5 लाख रुपये का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा और प्रीमियम का भुगतान P M केर्यर्स द्वारा किया जाएगा।

11. प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना किस नदी पर बनाई जाएगी?

- A. झेलम
- B. यमुना
- C. कावेरी
- D. सतलुज

12. किस संगठन ने ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल "बाल स्वराज (COVID-केयर)" लॉन्च किया है?

- A. केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड
- B. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
- C. राष्ट्रीय महिला आयोग
- D. राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

13. किस राज्य सरकार ने पेड़ लगाने के लिए नागरिकों को पुरस्कार देने के लिए 'अंकुर' योजना शुरू की है?

- A. बिहार
- B. उत्तर प्रदेश
- C. राजस्थान
- D. मध्य प्रदेश

14. भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है?

- A. आश्रिता वी ओलेटी
- B. भावना कान्त
- C. शिवांगी
- D. अवनी चतुर्वेदी

15. तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए 'WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार' से किसे सम्मानित किया गया है?

- A. पीयूष गोयल
- B. हर्षवर्धन
- C. नरेंद्र मोदी
- D. रविशंकर प्रसाद

16. स्पाइडर क्रिकेट की एक नई प्रजाति "जयंती" हाल ही में किस राज्य में खोजी गई थी?

- A. उत्तर प्रदेश
- B. छत्तीसगढ़
- C. कर्नाटक
- D. ओडिशा

17. निम्नलिखित में से किस संगठन ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया है?

- A. इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
- B. राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
- C. इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड
- D. गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड

18. सतत विकास लक्ष्य (SDG) इंडिया इंडेक्स 2020-21 के तीसरे संस्करण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

- i. NITI आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 का तीसरा संस्करण जारी किया है।
- ii. 75 के स्कोर के साथ हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- A. केवल i
- B. केवल ii
- C. i और ii दोनों

D. न तो i न ही ii

19.रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑरगेनाइजेशन (RDSO) SDO (स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गनाइजेशन) घोषित होने वाला पहला संस्थान बन गया है।

वे कौन से बिंदु हैं जो उपरोक्त कथन से सही रूप से संबंधित हैं?

- i. RDSO ने BIS SDO मान्यता योजना के तहत एक SDO के रूप में मान्यता प्राप्त करने की पहल की।
- ii. मान्यता 3 साल के लिए वैध है और वैधता अवधि पूरी होने के बाद नवीनीकरण की आवश्यकता होगी।
- iii. RDSO भारतीय मानक व्यूरो के "एक जिला एक उत्पाद" मिशन के तहत SDO घोषित होने वाला पहला संस्थान बन गया है।

A. केवल i

B. केवल ii और iii

C. केवल i और ii

D. i, ii, iii

20.WHO द्वारा भारत में सबसे पहले पहचाने गए COVID-19 वेरिएंट को कौन से नए नाम दिए गए हैं?

A. कप्पा और डेल्टा

B. कप्पा और अल्फा

C. बीटा और डेल्टा

D. गामा और जेटा

21.राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

A. दीपक मिश्रा

B. अरुण कुमार मिश्रा

C. मोहन शर्मा

D. अमिताभ कांत

22.विश्व पर्यावरण दिवस 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- i. विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है।
- ii. भारत विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का वैशिक मेजबान था।
- iii. विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना 1972 में संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन में की गई थी।
- A. केवल iii
- B. केवल i और ii
- C. केवल i और iii
- D. केवल ii और iii

23. हाल ही में उद्घाटन किए गए इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

- i. केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया।
- ii. इस योजना के तहत भारत सरकार प्रति मेगा फूड पार्क परियोजना 50.00 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- A. केवल i
- B. केवल ii
- C. i और ii दोनों
- D. न तो i न ही ii

24. हाल ही में, भारत ने पेट्रोल के साथ अपने 20% इथेनॉल-मिश्रण को तक पुनः लक्षित किया।

- A. 2025
- B. 2028
- C. 2024
- D. 2029

25. नासा ने किस ग्रह पर VERITAS और DAVINCI+ मिशन भेजने की घोषणा की है?

- A. मंगल
- B. बृहस्पति
- C. शनि
- D. शुक्र

26. इसाक हर्जोंग किस देश के 11वें राष्ट्रपति बने हैं?

- A. अर्जेंटीना
- B. ब्राजील
- C. इज़राइल
- D. फिनलैंड

27. हाल ही में शुरू की गई SAGE (सीनियरकेयर एंजिंग ग्रोथ इंजन) पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

- i. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने SAGE पहल की शुरुआत की।
- ii. चालू वित वर्ष यानी 2021-22 में SAGE पहल के लिए 25 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- A. केवल i
- B. केवल ii
- C. i और ii दोनों
- D. न तो i न ही ii

28. भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 किस संगठन ने जारी की?

- A. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट
- B. द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टिट्यूट
- C. वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर
- D. NITI आयोग

29. किसने 'एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक' के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 जीता?

- A. जेम्स पैटरसन
- B. हामिद इस्माइलोव
- C. डेविड डियोप
- D. जॉन ग्रिशम

30. विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है?

- A. 06 मई
- B. 05 जून
- C. 07 मई
- D. 07 जून

31. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

- i. भारत को एशिया-प्रशांत राज्यों की श्रेणी में 2022-24 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) के लिए चुना गया है।
- ii. भारत वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में 2021-22 के कार्यकाल की सेवा कर रहा है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- A. केवल i
- B. केवल ii
- C. i और ii दोनों
- D. न तो i न ही ii

32. निम्नलिखित में से किसे असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान नामित किया गया है?

- A. रायमोना
- B. सोनितपुर
- C. नागांव

D. जोरहाट

33.भारत से विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- A. शुवाजीत पायने
- B. विनीता गर्ग
- C. रंजीतसिंह दिसाले
- D. अनमोल सिंह

34.संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है?

- A. अब्दुल्ला शाहिद
- B. पैट्रिक अमोथ
- C. मार्टिन ग्रिफिथ्स
- D. ज़लमई रसूल

35.QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

i. क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में 9 भारतीय विश्वविद्यालयों ने शीर्ष -200 स्थान हासिल किए हैं।

ii. IIT-बॉम्बे भारत का शीर्ष रैंक वाला संस्थान है।

iii. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दूसरा स्थान हासिल किया है।

- A. केवल iii
- B. केवल i और ii
- C. केवल ii और iii
- D. केवल i और iii

36.वैशिक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

i. G20 के वित्त मंत्रियों ने वैशिक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर की घोषणा की है।

ii. न्यूनतम वैशिक कर की दर कम से कम 15 प्रतिशत होगी।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- A. केवल i
- B. केवल ii
- C. i और ii दोनों
- D. न तो i न ही ii

37.भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा?

- A. केरल
- B. गुजरात
- C. ओडिशा
- D. महाराष्ट्र

38.“I-Familia” (आई-फैमिलिया) नामक वैशिक डेटाबेस किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है?

- A. CBI
- B. IMF
- C. DRDO
- D. Interpol

39.CBSE ने किस कंपनी के सहयोग से छात्रों के लिए कोडिंग और डेटा साइंस को एक विषय के रूप में प्रस्तावित किया है?

- A. HCL
- B. TCS
- C. माइक्रोसॉफ्ट
- D. विप्रो

40.जून 2021 में, किसने भारत के नए चुनाव आयुक्त (EC) के रूप में पदभार ग्रहण किया?

- A. अनूप चंद्र पाण्डेय
- B. सुनील मिश्रा
- C. विवेक त्रिपाठी
- D. रमेश चंद्र

41. असम के राष्ट्रीय उद्यानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- i. असम के देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 5वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया।
 - ii. असम अब देश का दूसरा सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है।
 - iii. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान UNESCO की विश्व धरोहर स्थल हैं।
- A. केवल ii
- B. केवल i
- C. केवल i और iii
- D. केवल ii और iii

42. जून 2021 में, विश्व बैंक ने 2021-

22 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था को _____ प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया।

- A. 6.3
- B. 8.3
- C. 7.5
- D. 9.2

43. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बुद्धदेव दासगुप्ता का हाल ही में निधन हो गया। वह एक थे।

- A. संगीतकार
- B. शिक्षक
- C. एथलीट
- D. फिल्म निर्माता

44. किस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने वर्ष 2030 तक AIDS को समाप्त करने के लिए एक राजनीतिक घोषणा को अपनाया है?

- A. WHO
- B. UNGA
- C. World Bank
- D. UNEP

45. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली?

- A. संजय यादव
- B. वी के मिश्रा
- C. राजीव मिश्रा
- D. अरविंद माथुर

46. एशियाई उत्पादकता संगठन से 'एशिया प्रशांत उत्पादकता चैंपियन' के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कार से किसे सम्मा नित किया गया?

- A. अनीश बंसल
- B. आर एस सोढ़ी
- C. आचार्य व्रत
- D. एच के चंद्रा

47. डिंग्को सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े थे?

- A. कुश्ती
- B. हॉकी
- C. बैडमिंटन
- D. बॉक्सिंग

48. G7 लीडर्स समिट 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- i. यह 47वां G7 लीडर्स समिट था।
 - ii. यह यूनाइटेड किंगडम के कॉर्नवाल में आयोजित किया गया था।
 - iii. चीन को "अतिथि देशों" के रूप में शिखर सम्मेलन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था।
- A. केवल iii
 - B. केवल ii
 - C. केवल ii और iii
 - D. केवल i और ii

49. किस भारतीय मूल के पत्रकार ने मुसलमानों को हिरासत में लेने के लिए चीन के विशाल बुनियादी ढांचे को उजागर करने के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता?

- A. रिया विनोना
- B. मेघा राजगोपालन
- C. अयाना कीर्तन
- D. योगिता निमाया

50. इज़राइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं?

- A. रूवेन रिवलिन
- B. नफताली बेनेत
- C. इसाक हज़ोंग
- D. बैंजामिन नेतन्याहू

51. हाल ही में रक्षा मंत्री ने iDEX को अगले पांच वर्षों के लिए 498.8 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता को मंजूरी दी है। iDEX का क्या अर्थ है?

- A. इनोवेशन्स फॉर डिफेन्स एक्सीलेंस
- B. इनोवेशन्स फॉर डिफेन्स एक्सरसाइज
- C. इनफार्मेशन फॉर डिफेन्स एक्सीलेंस
- D. इनिशिएटिव फॉर डिफेन्स एक्सीलेंस

52. ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है?

- A. ओसाका
- B. ऑकलैंड
- C. एडिलेड
- D. लागोस

53. बिटकॉइन को कानूनी निविदा (लीगल टेंडर) के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है?

- A. हंगरी
- B. जर्मनी
- C. अल सल्वाडोर
- D. अल्बानिया

54.फ्रैंच ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है?

- A. राफेल नडाल
- B. निकोला मेक्टिक
- C. स्टेफानोस सितसिपास
- D. नोवाक जोकोविच

55.फ्रैंच ओपन 2021 महिला एकल का खिताब किसने जीता है?

- A. अनास्तासिया पाव्लुचेनकोवा
- B. बारबोरा क्रेजसिकोवा
- C. कैटरीना सिनियाकोवा
- D. आर्य सबलेंका

56. ASEAN डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग (ADMM) प्लस का कौन सा संस्करण 16 जून, 2021 को आयोजित किया गया था?

- A. 6
- B. 8
- C. 3
- D. 9

57.वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है?

- A. 11
- B. 16
- C. 19
- D. 14

58. 2021 में 31वां NATO शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था?

- A. ओटावा
- B. कोपेनहेगन
- C. ब्रुसेल्स
- D. मैट्रिड

59. विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है?

- A. 18 जून
- B. 17 जून
- C. 15 जून
- D. 21 जून

60. भारत में सी प्लेन सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

- i. बंदरगाह, जहाजरानी तथा जलमार्ग मंत्रालय तथा नागरिक उड़ायन मंत्रालय के बीच भारत में सी प्लेन सेवाओं के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।
- ii. अहमदाबाद में केवड़िया और साबरमती रिवरफ्रंट के बीच भारत की पहली सी प्लेन सेवा ने सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज के तहत अक्टूबर 2020 में परिचालन शुरू किया।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- A. केवल i
- B. केवल ii
- C. i और ii दोनों
- D. न तो i न ही ii

61. किस केंद्रीय मंत्रालय ने "गहरे समुद्र अभियान" का प्रस्ताव दिया है?

- A. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- B. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- C. जल शक्ति मंत्रालय
- D. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

62. 13वें BRICS शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में किस संस्थान ने BRICS नेटवर्क विश्वविद्यालयों के सम्मेलन की मेजबानी की है?

- A. IIT दिल्ली
- B. IIT कानपुर
- C. IIT बॉम्बे
- D. IIT मद्रास

63. विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

i. विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 IMD (इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट) द्वारा जारी किया गया था।

ii. भारत 43वें स्थान पर है।

iii. डेनमार्क पहले स्थान पर है।

- A. केवल i
- B. केवल ii
- C. केवल i और iii
- D. केवल i और ii

64. भारतीय नौसेना - यूरोपीय संघ नौसैनिक बल (IN-EUNAVFOR) अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया?

- A. अलास्का की खाड़ी
- B. बहरीन की खाड़ी
- C. वेनिस की खाड़ी
- D. अदन की खाड़ी

65. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है?

- A. 21 जून
- B. 11 जून
- C. 19 जून

D. 25 जून

66. किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह 'वीसा वुडसैट' लॉन्च करने की घोषणा की है?

- A. ऑस्ट्रेलिया
- B. स्पेन
- C. न्यूजीलैंड
- D. जर्मनी

67. हाल ही में मिल्खा सिंह का निधन हो गया। वह एक..... थे।

- A. क्रिकेटर
- B. मुक्केबाज़
- C. धावक
- D. पहलवान

68. ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

- i. भारत को 135वें स्थान पर रखा गया है।
- ii. विश्व आर्थिक मंच द्वारा इंडेक्स जारी किया गया था।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- A. केवल i
- B. केवल ii
- C. i और ii दोनों
- D. न तो i न ही ii

69. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के किस संस्करण के अवसर पर 'WHO M-योग' ऐप लॉन्च किया?

- A. 7
- B. 6
- C. 9

D. 5

70. जून 2021 में हुए ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की है?

- A. अहमद जन्नती
- B. इब्राहिम रायसी
- C. ईशाक जहांगीरी
- D. इसा कलंतरी

71. विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- i. भारत को 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में 64 बिलियन डॉलर प्राप्त हुए।
- ii. भारत दुनिया में FDI प्रवाह का दूसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है।
- iii. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यह रिपोर्ट जारी की है।

- A. केवल i
- B. केवल ii
- C. केवल ii और iii
- D. केवल i और ii

72. हाल ही में, चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ कौन सा अंतरिक्ष यान लॉन्च किया?

- A. शेनझोउ-16
- B. शेनझोउ-12
- C. शेनझोउ-14
- D. शेनझोउ-15

73. UNCCD द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 किस संगठन ने जीता?

- A. ग्रीन यात्रा
- B. नेचर फाउंडेशन
- C. पारिस्थितिक सुरक्षा फाउंडेशन

D. पारिवारिक वानिकी

74. F1 फ्रैंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है?

- A. मैक्स वेरस्टापेन
- B. सर्जियो पेरेज़
- C. लुईस हैमिल्टन
- D. फर्नांडो अलोंसो

75. SVAMITVA (स्वामित्व) योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

i.

SVAMITVA योजना भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यानी 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।

ii. इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए मुफ्त आवास प्रदान करना है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- A. केवल i
- B. केवल ii
- C. i और ii दोनों
- D. न तो i न ही ii

76. हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में SVAMITVA (स्वामित्व) योजना को लागू करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ एक समझौता जापन पर हस्ताक्षर किए हैं?

- A. उड़ीसा
- B. असम
- C. केरल
- D. तमिलनाडु

77. किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश ने 'मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना' शुरू की?

- A. उत्तर प्रदेश
- B. पुड़चेरी
- C. बिहार
- D. दिल्ली

78. हाल ही में खबरों में रहा मिशन कर्मयोगी का संबंध से है

- A. वित्तीय सुधार
- B. सिविल सेवा सुधार
- C. अवसंरचना सुधार
- D. कृषि सुधार

79. महत्वाकांक्षी "मिशन कर्मयोगी" के माध्यम से प्रमुख नौकरशाही सुधार लाने में सरकार की मदद करने के लिए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था?

- A. एस डी शिबू लाल
- B. गोविंद अच्युर
- C. वी के महापात्रा
- D. पंकज बंसल

80. किस राज्य ने नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुफलो को शामिल करते हुए एक आर्थिक सलाहकार परिषद की घोषणा की है?

- A. कर्नाटक
- B. उत्तर प्रदेश
- C. तमिलनाडु
- D. मध्य प्रदेश

###ANSWERS###

1. Ans. C.	21. Ans. B.	41. Ans. D.	61. Ans. A.
2. Ans. C.	22. Ans. C.	42. Ans. B.	62. Ans. C.
3. Ans. A.	23. Ans. C.	43. Ans. D.	63. Ans. D.
4. Ans. D.	24. Ans. A.	44. Ans. B.	64. Ans. D.
5. Ans. B.	25. Ans. D.	45. Ans. A.	65. Ans. A.
6. Ans. B.	26. Ans. C.	46. Ans. B.	66. Ans. C.
7. Ans. A.	27. Ans. B.	47. Ans. D.	67. Ans. C.
8. Ans. B.	28. Ans. A.	48. Ans. D.	68. Ans. A.
9. Ans. C.	29. Ans. C.	49. Ans. B.	69. Ans. A.
10. Ans. B.	30. Ans. D.	50. Ans. B.	70. Ans. B.
11. Ans. C.	31. Ans. C.	51. Ans. A.	71. Ans. A.
12. Ans. B.	32. Ans. A.	52. Ans. B.	72. Ans. B.
13. Ans. D.	33. Ans. C.	53. Ans. C.	73. Ans. D.
14. Ans. A.	34. Ans. A.	54. Ans. D.	74. Ans. A.
15. Ans. B.	35. Ans. C.	55. Ans. B.	75. Ans. A.
16. Ans. B.	36. Ans. B.	56. Ans. B.	76. Ans. B.
17. Ans. C.	37. Ans. B.	57. Ans. D.	77. Ans. D.
18. Ans. A.	38. Ans. D.	58. Ans. C.	78. Ans. B.
19. Ans. C.	39. Ans. C.	59. Ans. B.	79. Ans. A.
20. Ans. A.	40. Ans. A.	60. Ans. C.	80. Ans. C.

Gradeup



Why

Gradeup Super Subscription?



With Gradeup Super you get

- Structured Live Courses with the daily study plan
- Full syllabus coverage of Exam with live classes,
- Study notes and interactive quizzes.
- Get mock tests of different exams for better preparation
- Prepare with India's best Faculty with a proven track record
- Complete Doubt Resolution by Mentors and Experts
- Performance analysis and Report card to track improvement

